चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

बंगाल के मुसलमानों को दिखी उम्मीद की किरण

पेज 5

एक थे जॉर्ज फर्नांडिस!

पेज 9

भक्ति की शक्ति

पेज 12

कुंभ विरक्ति का नहीं, वैभव का प्रदर्शन

पेज 13

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 22 फरवरी–28 फरवरी 2010

बच्चों की आड़ में लूटखसोट

बच्चे, ज़मीन घोटाला और वसुंधरा

मुख्यमंत्री जी, यह क्या हो रहा है!

भारतीय संस्कृति में भोजन कराना पुण्य का काम समझा जाता है. लेकिन राजस्थान में पुण्य की आड़ में पाप का खेल हो रहा है. बच्चों का पेट भरने की आड़ में कुछ लोग चांदी काट रहे हैं. चूंकि वे नाम कद्दावर हैं, इसलिए हर बार बच निकलते हैं. लेकिन शेर की खाल में सियार वाली यह नीति ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं. शायद लोकसभा के बजट सत्र में सच से पर्दा उठ जाए.

रूबी अरुण

आख़िरकार यह माज़रा क्या है? राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कर क्या रही है? एक तरफ़ तो वह सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलने वाले मिड डे मील कार्यक्रम को राज्य में संचालित करने की ख़ातिर करोड़ों रुपये ख़र्च कर रही है तो दूसरी तरफ़ इसी योजना के नाम पर वह देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा पोषित स्वयंसेवी संगठनों से करोड़ों रुपये वसूल भी रही है. ये नज़राने दान के नाम पर स्वीकार किए जा रहे हैं. हालांकि यह काम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही हो रहा है. लिहाज़ा इसे क़ानूनी जामा पहनाने की गरज़ से राजस्थान सरकार ने एक ट्रस्ट का गठन भी कर दिया है. एमडीएम ट्रस्ट यानी मिड डे मील ट्रस्ट. अब इन बड़े घरानों का भी कमाल देखिए. सरकारी स्कूलों के बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के नाम पर अगर वे दोनों हाथों से धनराशियां लुटा रहे हैं तो उसकी एवज़ में राजस्थान सरकार से अनुदान भी ले रहे हैं. और, यही बात कुछ हज़म नहीं हो रही. मिड डे मील के नाम पर राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की इस कारगुज़ारी का मक़सद क्या है? मिड डे मील के नाम पर क्या खिचड़ी पक रही है राजस्थान सरकार और नामचीन औद्योगिक घरानों के बीच? समाजसेवा के नाम पर जो कुछ दिख रहा है, क्या वही सच है या पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है. यह जो लेन-देन का खेल है, वह सिर्फ़ धर्मार्थ के तहत है या इसकी आड़ में कुछ और गुल खिल रहे हैं? क्योंकि जो कुछ हो रहा है, वह महज़ समाजसेवा तो हो ही नहीं सकता. चौथी दुनिया ने जब तहक़ीक़ात की तो जो सच सामने आया, वह वाकई चौंकाने वाला है. भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार के समय शुरू हुई इस योजना की आड़ में बेशक़ीमती सरकारी ज़मीनों का वारा-न्यारा हो रहा है. ये घराने स्वयंसेवी संस्थाओं के ज़रिए समाजसेवा का स्वांग रचते हैं. धर्म और समाज के नाम पर कुछ करोड़ रुपयों का दान कर सैकड़ों करोड़ की ज़मीन हथियाते हैं और टैक्स चुकाने से भी बच जाते हैं. समाज से पुण्यात्मा होने का तमगा अलग से मिल जाता है. वैसे, ऐसा भी नहीं है कि सभी की सभी स्वयंसेवी संस्थाएं इस खेल में शामिल हैं. इनमें से वाक़ई कुछ ऐसी हैं, जो समाज के हित का सोचती हैं और काम करती हैं. पर इनकी संख्या नगण्य ही है.

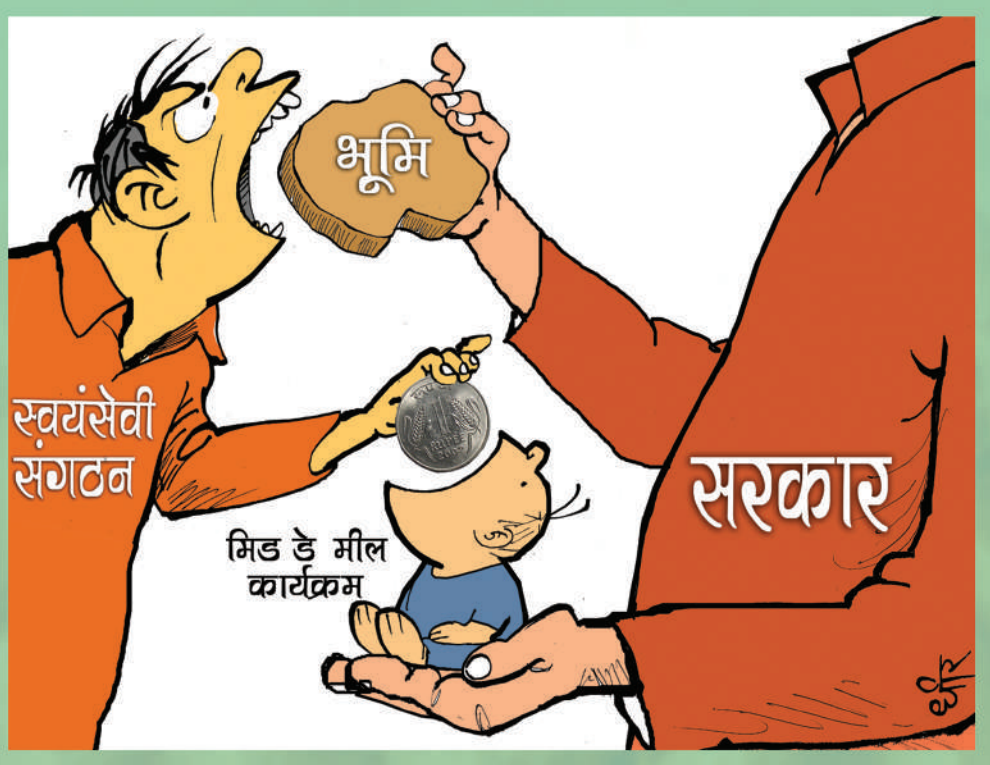

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद राजस्थान में शुरू की गई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना अपना ख़ूब रंग दिखा रही है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर राजस्थान में अक्षयपात्र फाउंडेशन, नांदी फाउंडेशन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ओआरजी फाउंडेशन, श्री सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट, इस्कॉन, टेंपल बोर्ड सिवाद, जेजी ह्यूमेनिटेरियन सोसायटी, अदम्य चेतना ट्रस्ट, डीसीएम श्रीराम ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, बोहरा कम्युनिटी, डुग्गर ट्रस्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नव प्रयास, आकृति और सेंटर फॉर नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव राज्य भर के सरकारी स्कूल के अस्सी लाख बच्चों को मिड डे मील मुहैय्या करा रहे हैं. और, अब तो इस्पात किंग लक्ष्मी मित्तल जैसे धनकुबेर भी इस काम में रुचि दिखा रहे हैं.

इन स्वयंसेवी संस्थाओं को उनके इस काम के बदले केंद्र और राज्य से पूरा अनुदान मिलता है. हालांकि तक़लीफ की बात यह है कि करोड़ों रुपये ख़र्च करने का आडंबर करके भी मिड डे मील के तहत बच्चों को सही खाना नहीं मिल पा रहा है. नागौर, झाडौल, बीकानेर और गंगानगर के ज़िलाधिकारियों के पास दर्ज़नों शिकायतें आई हैं कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा परोसे जा रहे खाने में कीड़े-मकौड़े मिलते हैं, सड़ी-गली सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, जिससे आएदिन बच्चे बीमार होते हैं. कई स्कूल तो ऐसे हैं, जहां बच्चों को खाना तक नहीं मिलता. क्या फ़ायदा इन बड़े ट्रस्टों और स्वयंसेवी संस्थाओं का? सरकार भी करोड़ों रुपये का अनुदान देकर दिखावा करती है कि उसे बच्चों का कितना खयाल है. जबकि सच यह है कि इन बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है.

ये संस्थाएं सरकार से अनुदान तो लेती हैं, पर उस अनुदान की राशि से कहीं ज़्यादा धनराशि सरकार को मिड डे मील के दुरुस्त संचालन के नाम पर दान स्वरूप सौंप देती हैं. तो सवाल यह उठता है कि अगर मक़सद समाजसेवा है तो फिर इन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनुदान लेने का औचित्य क्या है? लोक लेखा समिति की जल्दी ही पेश होने वाली रिपोर्ट में भी यह सवाल उठाया गया है और इस पर बेहद कड़ी टिप्पणी भी की गई है. लोक लेखा समिति की रिपोर्ट भी सरकारी ज़मीन के घोटाले पर ही टिकी है. हालांकि इन सबमें अशोक गहलोत सरकार की कोई ख़ास भूमिका नहीं है. इस लेन-देन का शुभारंभ वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने राज में ही कर दिया था.

शुरुआत करते हैं बैंगलोर इस्कान द्वारा संचालित अक्षयपात्र फाउंडेशन से. बैंगलोर में सरकारी ज़मीनों की ख़रीद-बिक्री में घोटाला करने के मामलों में यह पहले से ही बदनाम है. और, अब राजस्थान में भी इसका वही धंधा जारी है. यह फाउंडेशन राजस्थान के जयपुर, बारन और नाथद्वारा के सरकारी स्कूलों में एक लाख अस्सी हज़ार बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन का इंतज़ाम करता है. इसके लिए अक्षयपात्र को सरकारी अनुदान के अलावा अनाज भी मिलता है. पर यह सामान्य सरकारी प्रक्रिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि अक्षयपात्र ने जयपुर और नाथद्वारा में चलने वाले इस सरकारी कार्यक्रम के लिए राजस्थान सरकार को कुल सात सौ अट्ठाइस करोड़ रुपये की धनराशि दान में दी है. संस्था जब इतनी बड़ी धनराशि दान में दे सकती है तो फिर सरकारी अनुदान लेने का दिखावा क्यों कर रही है? जो कहानी सामने आई है, उसके मुताबिक माजरा यह है कि अक्षयपात्र फाउंडेशन जयपुर में एक मेगा टाउनशिप का निर्माण करा रहा है, जिसके लिए औने-पौने दामों में ज़मीन वगैरह उपलब्ध कराने का काम राजस्थान सरकार ने किया है. हालांकि अक्षयपात्र को ज़मीन मुहैय्या कराने की प्रक्रिया भाजपा की वसुंधरा सरकार के वक़्त से ही शुरू हो चुकी थी. राजस्थान में अक्षयपात्र के क़दम भी वसुंधरा राजे की मेहरबानियों के कारण ही पड़े. भाजपा के दिग्गज नेता और अदम्य चेतना नाम की विशाल स्वयंसेवी संस्था के मालिक अनंत कुमार ने वसुंधरा और अक्षयपात्र के कर्ता-धर्ता पंडित मधु दास के बीच संपर्क बनाने का काम किया था. अनंत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. वसुंधरा ने बेहद तामझाम के साथ जयपुर में इस संस्था का उद्घाटन किया और मिड डे मील का काम सौंप दिया. धीरे-धीरे अक्षयपात्र ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया. बैंगलोर की तर्ज़ पर यहां भी टाउनशिप बनाने का काम चालू कर दिया. दरअसल, अक्षयपात्र का काम ही यही है. पहले वह समाजसेवा के नाम पर पहल करता है. सरकार में अपनी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

> **बड़े घरानों का भी कमाल देखिए. सरकारी स्कूलों के बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के नाम पर अगर वे दोनों हाथों से धनराशियां लुटा रहे हैं तो उसकी एवज़ में राजस्थान सरकार से अनुदान भी ले रहे हैं. और, यही बात कुछ हज़म नहीं हो रही. मिड डे मील के नाम पर राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की इस कारगुज़ारी का मक़सद क्या है?**

आदित्य बिड़ला, एबी ग्रुप

आनंद महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा

नारायण मूर्ति, इन्फोसिस

अनंत कुमार, भाजपा नेता

चव्हाण खासतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के प्राइवेट सेक्टर में काम करने के कारण खासे नाराज हैं. उनका मानना है कि वे सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

हरित ऊर्जा को अपनाएं

हालांकि सरकार हरित ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने में मुश्किलें आ रही हैं. हालांकि न्यू एंड रीन्यूवल एनर्जी विभाग के मंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों को इस मुद्दे पर पत्र लिखा है, जिनमें रक्षा, रेल और पर्यटन मंत्रालय शामिल हैं. लेकिन उनका ज़वाब बहुत उत्साहजनक नहीं रहा. वास्तव में फारुख अब्दुल्ला के ग्रीन एज़ेंडे के प्रति अगर किसी ने उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया दी है तो सिर्फ लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ने. उन्होंने राष्ट्रपति भवन की तरह ही संसद की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए मंत्रालयों से मदद करने को कहा है. बहरहाल महाराष्ट्र सरकार ने ग्रीन एज़ेंडे के मसले पर त्वरित और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. राज्य पर्यावरण सचिव वालसा नायर सिंह ने इसके उपाय के तौर पर कई घोषणाएं की हैं. उन्होंने ऐसे कागज इस्तेमाल करने की बात कही है, जिन्हें नवीकृत किया जा सके. साथ ही उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा बचाने वाले बल्ब इस्तेमाल करने की भी बात कही है.

कर्नाटक सरकार भी राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के विकास हेतु जरूरी फंड इकट्ठा करने के लिए उद्योगों पर हरित कर लगाने के बारे में सोच रही है. साफ तौर पर कहें तो फारुख अब्दुल्ला के बाबुओं को अपने एजेंडे पर और ज्यादा जोर लगाने तथा केंद्रीय मंत्रालयों को तेजी से राह पर लाने की जरूरत है.

बाबुओं से चव्हाण खफा

बाबुओं के कॉरपोरेट समूहों से जुड़ने की ललक और उनके पलायन को देखते हुए चव्हाण यही मान रहे हैं कि हद की भी हद होती है. चव्हाण भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के प्राइवेट सेक्टर में काम करने से खासे नाराज हैं. मामले को नजदीक से जानने वालों के मुताबिक, चव्हाण इसके लिए एक नियम बहाल करने के बारे में सोच रहे हैं. वह चाहते हैं कि सरकारी बाबू सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद कम से कम दो साल तक किसी भी प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम न बनें. बहरहाल नब्बे के दशक के मध्य में सरकार ने बाबुओं को कॉरपोरेट जिम्मेवारियों के लिए प्रोत्साहित किया था. उस समय इस बारे में यह सोचा गया था कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के अनुभवों से उन्हें अपनी योग्यता और कौशल निखारने में मदद मिलेगी. और, जब वे सरकारी कामकाज से फिर से जुड़ेंगे तो प्रशासनिक कामकाज में उनका कौशल दिखाई भी देगा. लेकिन, कई बाबुओं के प्राइवेट सेक्टर के साथ कंसल्टेंट के तौर पर जुड़ने और कई मामलों में सरकार को सूचित किए बगैर जुड़ने से चव्हाण को यह महसूस हुआ कि वे सरकारी हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि बाबुओं को सरकारी

कामकाज की पूरी जानकारी होती है. वे जिस कॉरपोरेट समूह के लिए काम कर रहे होते हैं, उसे बढ़ावा दे सकते हैं और यह सरकारी हितों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. इस फैसले से बाबुओं को खासी परेशानी हुई है. अगर अधिकारीगण निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाले सेतु का काम करेंगे तो वे राज्य के विकास की गाड़ी को भी गति दे सकते हैं. चव्हाण ऐसा ही समझते हैं, इसलिए उन्होंने जो ठाना है, उस पर अडिग हैं.

सरकार ने महसूस किया अनाथ बच्चों का दर्द

कोसी बाढ़ में अनाथ हुए बच्चों द्वारा भीख मांगने की खबर से बिहार प्रशासन में हड़कंप मच गया है. बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष रामदेव राय ने कोसी बाढ़ में अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास की रिपोर्ट तलब की है. वहीं समाज कल्याण मंत्री दामोदर रावत ने कहा है कि जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों और संगठनों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी.

बिहार प्रशासन में तब खलबली मच गई, जब आपके प्रिय अखबार चौथी दुनिया ने कोसी बाढ़ में अनाथ हुए बच्चों द्वारा भीख मांगने की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रकाशित की. चौथी दुनिया ने भीख मांगते बच्चों की तस्वीर भी छापी थी, जिसे देखकर सहरसा के लोग आंदोलित हो गए और सड़क पर प्रदर्शन करने लगे. इस प्रदर्शन को आम जनता और स्थानीय नेताओं का भरपूर समर्थन मिला. सहरसा में लोजपा और कई संगठनों के लोगों ने धरना देकर आकांक्षा अनाथ आश्रम में बेहाल बच्चों को संकट से उबारने की मांग सरकार से की. युवा लोजपा के ज़िला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि क़रीब डेढ़ साल पहले बाढ़ आई थी, लेकिन बाढ़ की त्रासदी में अपने परिवार और समाज से बिछड़े क़रीब दो दर्जन बच्चों को अब तक सरकार आसरा नहीं दे पाई. सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि अनाथ बच्चों

IMPACT

को भीख तक मांगनी पड़ रही है. उन्होंने साफ़ कहा कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही से बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. युवा लोजपा ने धरने के माध्यम से पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राज्यपाल और आयुक्त के नाम डीएम को सौंपा.

चौथी दुनिया की पहल और लोगों की नाराज़गी का नतीजा यह हुआ कि बाल श्रम आयोग और समाज कल्याण विभाग ने ज़िला प्रशासन से बच्चों की ताजा स्थिति पर पूरी रिपोर्ट मांगी है. लोजपा कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार से बच्चों को संरक्षण देने की मांग की. समाज कल्याण मंत्री दामोदर रावत ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द बच्चों को तकलीफ से उबारा जाए. दूसरी तरफ बालश्रम आयोग के अध्यक्ष रामदेव राय ने कहा कि बच्चे भीख मांगकर खाना खाएं, यह कैसे होगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा. अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे और कितनी जल्दी मासूम बच्चों की तस्वीर और तकदीर बदलती है.

मोतीझील के लिए अब सौ करोड़ रुपये

तीन करोड़ नहीं, बल्कि अब सौ करोड़ रुपये खर्च करके बदहाल मोतीझील को खूबसूरत बनाया जाएगा. ज़िलाधिकारी नर्मदेश्वर लाल ने चौथी दुनिया में छपी खबर को गंभीरता से लेते हुए बताया कि तीन करोड़ रुपये की जगह अब हमने सरकार से लगभग सौ करोड़ रुपये की मांग की है, ताकि मोती–झील का कायापलट हो सके.

इधर प्रगतिशील युवा मंच के बैनर तले ज़िला मुख्यालय मोतिहारी के गांधी चौक पर एक दिवसीय मौन धरना आयोजित किया गया. धरने में शामिल लोग अपनी मांगों से संबंधित तख्तियां हाथ में लिए चुपचाप बैठे रहे और इस व्यस्त चौक से गुजरने वाले हज़ारों लोगों को मोतीझील के सौंदर्यीकरण के लिए पैगाम देते रहे. धरने के दौरान सभी ने प्रगतिशील युवा मंच के इस क़दम और चौथी दुनिया के प्रयास की सराहना की. चकिया के अमरेश पांडे ने बताया कि हम लोग सिर्फ़ बातें करते हैं, लेकिन प्रगतिशील

IMPACT

युवा मंच और चौथी दुनिया ने मोतीझील के सौंदर्यीकरण के लिए सार्थक प्रयास किए. राहगीर वंदना तिवारी ने कहा कि चौथी दुनिया में प्रकाशित ख़बर प्रशंसनीय है और यह अखबार वाकई हमारी फिक्र करने वाला है. धरने में शामिल नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने चौथी दुनिया की प्रति दिखाते हुए बताया कि अब तक इस अखबार ने जिन मुद्दों को सबके सामने रखा है, वे अपने आप में सराहनीय हैं. अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ज़िले की पहचान मोतीझील के सौंदर्यीकरण के लिए एकजुट हों. प्रगतिशील युवा मंच के संस्थापक सह अध्यक्ष मोहम्मद तमन्ना ने संघर्ष जारी रखने का वादा किया. नगर परिषद के अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना ने बताया कि शीघ्र ही इस दिशा में कार्य आगे बढ़ाया जाएगा और निर्धारित राशि किस प्रकार खर्च की जाए, इस बारे में दिशा–निर्देश दिए जाएंगे.

बच्चे, ज़मीन घोटाला और वसुंधरा

पृष्ठ एक का शेष

पहुंच बनाता है. फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में घुस जाता है. पहले बैंगलोर, फिर जयपुर, उसके बाद वृंदावन और अब मथुरा. मतलब यह कि समाजसेवा की आड़ में अक्षयपात्र अपने दूसरे धंधों की बेलें फैला रहा है.

अब ज़िक्र करेंगे नांदी फाउंडेशन का. इस संस्था को सरपरस्ती हासिल है मशहूर औद्योगिक घराने महिंद्रा एंड महिंद्रा की. महिंद्रा एंड महिंद्रा को जयपुर में सेज़ के तहत आने वाली तीन हज़ार एकड़ ज़मीन हासिल है, जिसमें वह वर्ल्ड सिटी नाम से एक वर्ल्ड क्लास कॉरपोरेट और बिज़नेस हाउसेज़ बना रहे हैं. 16 दिसंबर 2006 को राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वर्ल्ड सिटी की नींव ख़ुद अपने हाथों से रखी थी. वैसे कहने को इस मेगा प्रोजेक्ट में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भी साझीदार है, पर मिली जानकारी के मुताबिक़ उसकी भूमिका हाशिए पर रहने जैसी है. सरकार की इस मेहरबानी के बदले महिंद्रा एंड महिंद्रा ने राजस्थान सरकार को जयपुर में मिड डे मील के संचालन के लिए एक करोड़ रुपये दान में दिए हैं. महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उदयपुर, भीलवाड़ा और गंगानगर के एक लाख स्कूली बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी उठाई है. 3000 एकड़ सरकारी ज़मीन के मुक़ाबले यह सौदा फिर भी सस्ता है.

नांदी फाउंडेशन के इस काम में और भी बड़े–बड़े कॉरपोरेट घराने शरीक हैं. जैसे अक्षयपात्र को इंफोसिस का साथ मिला है. वैसे ही नांदी फाउंडेशन के साथ रेड्डी लैब, सत्यम आदि की साझीदारी है. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिस्सेदार है. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नांदी फाउंडेशन के साथ गंगानगर चित्तौड़ में 15000 बच्चों को दोपहर का खाना खिलाता है. कपासड़, नीमबहेड़ा और चित्तौड़गढ़ में 60000 बच्चों की ज़िम्मेदारी है. यानी कि कुल मिलाकर 75000 बच्चे और सरकार को दान में दी गई है एक करोड़ रुपये की राशि. बदले में सरकार ने उपकृत किया है 350 एकड़ ज़मीन देकर. जिस पर कंपनी बिजली का स्मॉल पावर प्लांट लगा रही है. इसके अलावा कंपनी मिनरल और माइनिंग के काम में भी हाथ आज़मा रही है. राजस्थान मिनरल रिच स्टेट में है, जहां लगभग 25 क़िस्म के मिनरल्स मिलते हैं. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को जिंक के अलावा ग्रेनाइट, कैलसाइट, क्ले, कॉपर, फ्लोराइड और फास्फेट का भी लाइसेंस राज्य सरकार से मिल चुका है.

अब बात करें एवी बिरला ग्रुप की, जिन्होंने 25 लाख रुपये इस योजना को चलाने के लिए राजस्थान सरकार की झोली में डाले थे. इस ग्रुप ने चित्तौड़गढ़ में नांदी फाउंडेशन के साथ मिलकर दस हज़ार बच्चों का पेट भरने का ज़िम्मा उठाया है. यूं तो इस कंपनी के साथ ज़मीन के बड़े व्यवसायिक इस्तेमाल का मसला नहीं जुड़ा है, पर इसे शैक्षिक संस्थानों को खोलने के लिए ज़मीन के बड़े टुकड़ों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है. लिहाज़ा राज्य सरकार की कृपा तो बनी ही रहनी चाहिए. और, इसकी ख़ातिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शामिल होना ही पड़ेगा. ऊपर से सीमेंट का धंधा. यानी बिरला सीमेंट. सरकार को भेंट तो चढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान ही देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां 13 मिलियन टन सीमेंट का हर साल उत्पादन होता है.

मध्य प्रदेश का पाटनी ग्रुप भी इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खुलकर योगदान दे रहा है. आर के मार्बल नाम की इसकी सहयोगी कंपनी नांदी फाउंडेशन के साथ मिलकर बीस हज़ार बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रही है. बदले में सरकार ने इस कंपनी को उदयपुर में ज़मीन और संगमरमर की खदान से नवाज़ा है. यहां एक बात जो बेहद ग़ौर करने वाली है, वह यह है कि सभी योजनाएं और कंपनियों की भागीदारी 2007 में शुरू हुई थीं, जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री के सिंहासन पर महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया आसीन थीं. आर के मार्बल ने वसुंधरा की इस मेहरबानी के बदले पच्चीस लाख रुपये राज्य सरकार के दामन में डाले थे. हालांकि वादा तो कंपनी ने पैंतालिस लाख रुपये का किया था.

बात जब सीमेंट की हो रही हो, तो जे के सीमेंट को दरकिनार कैसे किया जा सकता है. जे के सीमेंट ने मिड डे मील के नाम पर चालीस लाख रुपये का दांव खेला है. यह कंपनी चित्तौड़ में अपना कार्यक्रम चला रही है. एवज़ में सरकार ने एसीसी सीमेंट की खानों की संख्या में इज़ाफ़ा कर दिया है. यक़ीनन एसीसी फ़ायदे में है.

और, अब बात आर एस एम एल ग्रुप की. यह ग्रुप उदयपुर के सलंबर और झाडौल के बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन का इंतजाम करता है. इसके अलावा इसने चौरानवे लाख रुपये राजस्थान सरकार को दिए, ताकि वह अपनी योजना को स्वस्थ और समृद्ध तरीके से आगे बढ़ा सके. इनाम में मिली इसे भी ज़मीन, जिस पर यह एमबीए कॉलेज बनवा रहा है, ताकि छात्रों के प्रवेश और पढ़ाई की फीस से रुपयों की बारिश में यह नहा सके.

बोहरा कम्युनिटी. वैसे तो यह एक धार्मिक संस्था है, जो धर्मार्थ का काम करती है. इन कामों के लिए इस कम्युनिटी को तमाम इमारतों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वह इस संप्रदाय में आस्था रखने वालों की बेहतरी के काम कर सके. ज़ाहिर है, इमारतों के लिए ज़मीन तो चाहिए ही. और वह भी बड़े स्तर पर. लिहाज़ा एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं. एक करोड़ रुपये का दान कर यह संप्रदाय वाहवाही लूट रहा है. तो बदले में राज्य सरकार की खुली सहायता मिल रही है. यक़ीनन एक करोड़ रुपये का दान के नाम पर निवेश बुरा नहीं है. राजस्थान में सोलर प्लांट बिठाने वाले डुग्गर चैरिटेबल ट्रस्ट ने बीकानेर को अपना कर्मक्षेत्र चुना और राजस्थान सरकार को सौंपी 15 लाख रुपये की राशि. अब यह ट्रस्ट राजस्थान के विभिन्न जिलों में शैक्षिक संस्थानों की शुरुआत कर रहा है, जिसके लिए सरकार से उसे भरपूर सहायता भी मिल रही है.

यूआईटी जोधपुर यानी अरबन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट. इसने राज्य की वसुंधरा सरकार से न्यू होटल पॉलिसी 2006 के तहत राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए होटलों को बनाने का ठेका लिया. तबसे अब तक इस ट्रस्ट ने बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर में कई निर्माण किए. जो ज़मीन इस ट्रस्ट को मिली, वह बेहद न्यूनतम राशि पर इसे दी गई है. बदले में 25 लाख रुपये की सौगात तो कुछ भी नहीं. मिड डे मील के नाम पर इस ट्रस्ट ने वसुंधरा सरकार को पच्चीस लाख रुपये की राशि सौंपी. ऐसी संस्थाओं और कंपनियों की लंबी फ़ेहरिस्त है, जिन्होंने वसुंधरा सरकार को उपकृत किया. बदले में उन्हें भी भरपूर बख्शा गया. लेकिन यह कहानी भाजपा के गणमान्य नेता और वसुंधरा राजे के अज़ीज़ मित्र अनंत कुमार की संस्था अदम्य चेतना की चर्चा किए बिना पूरी नहीं होती. अनंत कुमार की यह संस्था बैंगलोर में पैदा हुई, पनपी और इसने राजस्थान में भी अपना साम्राज्य कायम किया. यक़ीनन महारानी का हाथ अनंत कुमार की संस्था के सिर रहा. कई विवाद जुड़े रहे अदम्य चेतना के साथ. खाते में गड़बड़ियों को लेकर जांच कमिटी भी बनी, पर अनंत कुमार की अदम्य चेतना का कुछ नहीं बिगड़ा. अदम्य चेतना ने भी मिड डे मील के नाम पर दान स्वरूप नब्बे लाख रुपये वसुंधरा सरकार के ख़ज़ाने में डाल दिए और बगैर साफ़–सफ़ाई एवं बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे, मिड डे मील का ठेका सरकार से हासिल करती रही. यानी कि पैसों और पहुंच के दम पर गड़बड़झाला चलता रहा, पर उनकी शिकायतें लोक लेखा समिति तक पहुंचती रहीं और उनकी जांच भी होती रही. अब लोक लेखा समिति की रिपोर्ट इस बजट सत्र में लोकसभा में पेश होने वाली है. लोक लेखा समिति के चेयरमैन जसवंत सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा देने से पहले सभी जांच समितियों की रिपोर्ट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट बनाकर लोक लेखा समिति के सुपुर्द कर दी है. उम्मीद की जा रही है कि इस रिपोर्ट के संसद में पेश होने के बाद कई सनसनीखेज ख़ुलासे होंगे. कई नामचीन हस्तियों पर सवाल उठेंगे. राजनेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग और उद्योगपतियों के साथ उनके नेक्सस की एक बार फिर चर्चा होगी. तब संभवत: राजस्थान में मिड डे मील के नाम पर चल रही बेशक़ीमती सरकारी ज़मीन की बंदरबांट का पर्दाफ़ाश भी हो पाए.

ruby@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 1 अंक 50,
दिल्ली, 22 फरवरी–28 फरवरी 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–47839990/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

बीटी बैगन को लेकर सरकार कठघरे में है. उसे हर तरफ़ से विरोध से स्वर सुनाई दे रहे हैं. नतीजतन उसने फ़िलहाल इसे प्रतिबंधित करने का फ़ैसला लिया है.

बैगन पर बवाल, सेहत का सवाल

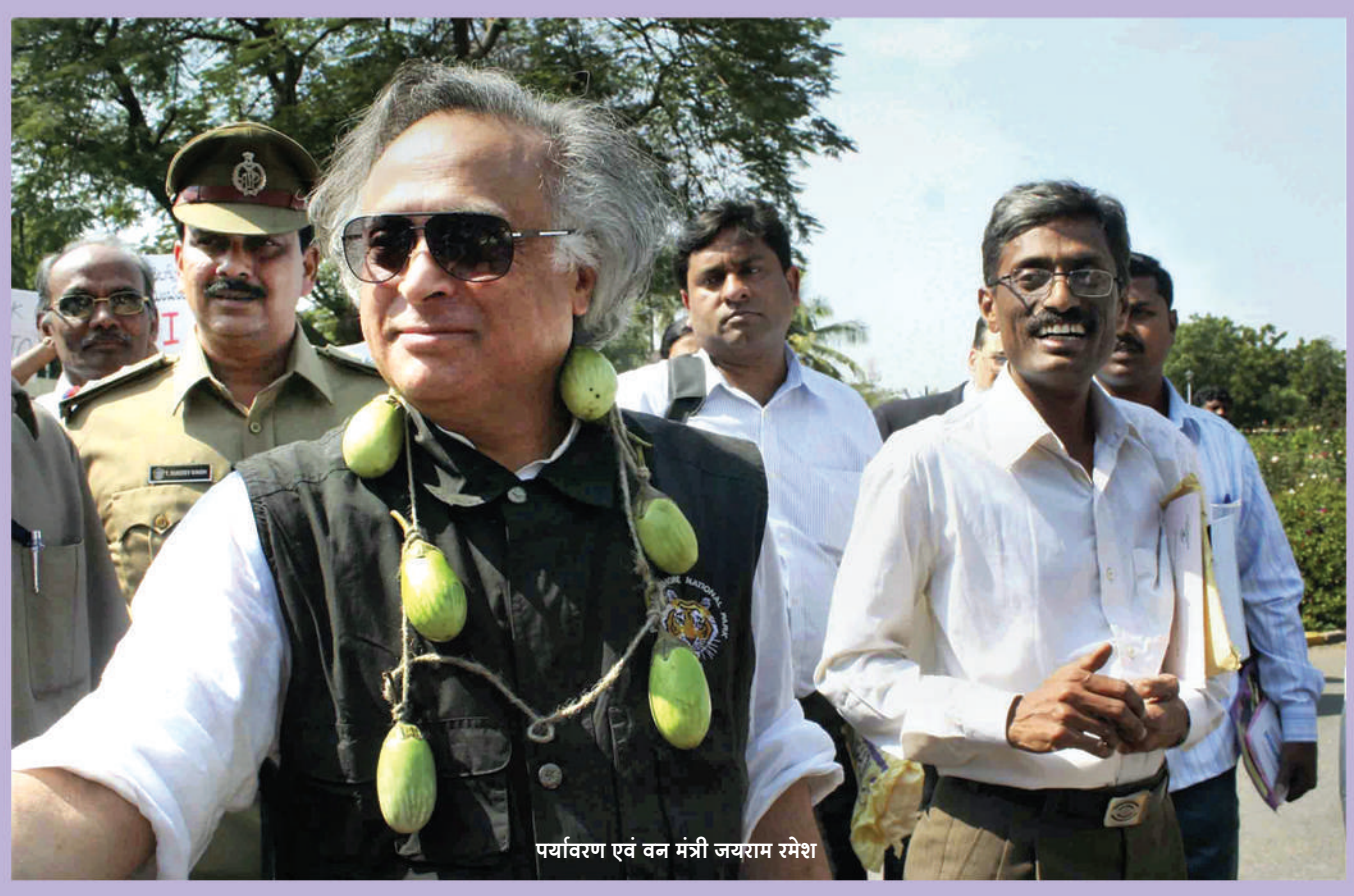

पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश

काफ़ी दिनों से बीटी बैगन को लेकर पूरे देश में व्यापक बहस चल रही है. इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं. कहने का मतलब यह है कि बीटी बैगन सुर्ख़ियों में है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आख़िर बीटी बैगन है क्या? बीटी बैगन दरअसल आनुवांशिक रूप से परिवर्द्धित बैगन है, जिसमें बैगन की जीन संरचना में बैक्टीरिया का जीन (क्राई–1 एसी) डाला जाता है. यह जीन एक प्रोटीन बनाता है. उस प्रोटीन की वजह से बैगन के मूल गुणों में बदलाव आ जाता है. चूंकि इस बैगन में प्रत्यारोपित जीन मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस (बीटी) से निकाला गया है, इसलिए यह बीटी बैगन कहलाता है. बैगन के जीन में यह बैक्टीरिया डालने से उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. साथ ही बैगन के तने एवं फलों को खाने वाले कीड़ों से भी उसकी रक्षा होती है.

ख़ासियत

बैगन में लगने वाले कीड़े उसका रस चूस लेते हैं. इस वजह से बैगन का पौधा विकास नहीं कर पाता या फिर फ़सल बर्बाद हो जाती है. लेकिन, जब कीड़े इस बीटी बैगन का रस चूसते हैं तो उनकी मौत हो जाती है. उनकी मौत की वजह बनता है, बीटी बैगन में मौजूद विषैला प्रोटीन. यह प्रोटीन बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस से बनता है. बीटी की इस ख़ूबी के कारण किसानों को कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा.

विरोध की वजह

इसका विरोध करने वालों में ख़ासतौर पर स्वयंसेवी संगठन, कृषि वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और किसान शामिल हैं. इन सभी का मानना है कि बीटी बैगन के उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा ही, इसके अलावा यह पर्यावरण के लिहाज़ से भी काफ़ी ख़तरनाक है. विरोधियों का मानना है कि जिन खाद्य पदार्थों के जीन में बदलाव किया जाता है, वह सेहत के लिए नुक़सानदायी साबित हो सकता है. कृषि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इससे सबसे पहले मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ेगा. हाल में मध्य प्रदेश में इस पर एक शोध किया गया. शोध में पाया गया कि बीटी बैगन के इस्तेमाल से कई तरह की बीमारियां जैसे खुजली, शरीर में फोड़ा, चेहरे पर सूजन आदि होती हैं. इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर इसका विरोध किया जा रहा है. माहिको (महाराष्ट्र हाईब्रिड सीड्स कंपनी) ने चूहों पर जो स्टडी की थी, उसमें मानव पर होने वाले संभावित ख़तरों पर ध्यान नहीं दिया गया. कई ग़ैर सरकारी संगठनों ने इसे असुरक्षित और ख़तरनाक बताकर उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर कर रखी है.

भारत में कैसे आया?

माहिको एक भारतीय कंपनी है. इसने एक अमेरिकी कंपनी मोनसांटो के साथ मिलकर यह रिसर्च किया है. यही कंपनियां बीटी कॉटन को भी देश में लाईं. बीटी बैगन के रिसर्च की शुरुआत 2000 में हुई. 2006 में इसका ट्रायल हुआ और 14 अक्टूबर 2009 को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) से इसे मंजूरी मिली.

मंजूरी देने पर उठा विवाद

इसे मंजूरी देनी है या नहीं, इसकी ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार के कृषि, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय पर है. जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) फ़सलों के परीक्षण के लिए दिशा–निर्देश तय करना कृषि मंत्रालय का काम है. कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इसके लिए दिशा–निर्देश तय किए. इन दिशा–निर्देशों पर निगरानी का काम पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाली जीईएसी का है. इसी संस्था ने ही बीटी बैगन के व्यवसायिक उत्पादन को मंजूरी दी थी.

समर्थकों की राय

बीटी बैगन समर्थकों का मानना है कि खाद्य सुरक्षा के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार खाद्यान्न ज़रूरी हैं. इसके कीट प्रतिरोधी होने के बावजूद वे इसे खाने के लिए सुरक्षित बताते हैं. इसके समर्थक यह भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीटी बैगन का नहीं, बल्कि बीटी कॉटन पर शोध हुआ है. और, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क़ है. कोई भी आदमी बैगन को पकाकर ही खाता है. इससे बैगन में स्वास्थ्य को नुक़सान पहुंचाने वाले कारक नष्ट हो जाते हैं. इनका यह भी कहना है कि बीटी के जीन छोटे–छोटे अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं, जो कि मानव शरीर के लिए ज़रूरी है और सामान्य भी. साथ ही मानव शरीर में भी अम्ल होते हैं, इसलिए बीटी बैगन के इस्तेमाल से मानव शरीर पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. माहिको का भी कहना है कि 11 लाख टन बीटी कॉटन का इस्तेमाल हो रहा है और कॉटन में बीटी जीन बैगन जैसा ही है.

फ़ायदे

बीटी बैगन की फ़सल के कीड़ों से सुरक्षित रहने का अनुमान है, नतीजतन, किसानों को कीटनाशकों पर ख़र्च नहीं करना पड़ेगा. फ़सल की बर्बादी कम होगी. ऐसा अनुमान है कि इससे 1000 करोड़ रुपये तक के नुक़सान से बचा जा सकता है. कम लागत पर अधिक पैदावार होगी, जिससे किसान फ़ायदे में रहेंगे.

बीटी बैगन का विरोध करने वाले मानते हैं कि जिन खाद्य पदार्थों के जीन में बदलाव किया जाता है, वह सेहत के लिए हानिकारक होते हैं. कृषि वैज्ञानिकों भी यही मानते हैं कि इससे तात्कालिक फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन भविष्य में इसका नकारात्मक असर ही पड़ेगा.

उठने वाले सवाल

इसे अनुमति देने के पहले समुचित प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखा गया. बिना निष्पक्ष परीक्षण कराए ही अनुमति दे दी गई. स्वास्थ्य के लिहाज़ से इसे सुरक्षित नहीं माना जा रहा है. शुरू में कम लागत पर उत्पादन से मुनाफ़ा तो होगा, लेकिन बाद में मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने से कीटनाशकों का उपयोग बढ़ जाएगा.

सरकार का रुख़

बीटी बैगन के मसले पर सरकार तीखी आलोचना झेल रही थी. आख़िरकार उसने इसके इस्तेमाल की मंजूरी को अनिश्चित काल के लिए टालने का फ़ैसला किया. पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस क़िस्म के व्यवसायिक इस्तेमाल को तब तक मंजूरी नहीं देने की बात कही है, जब तक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके दीर्घकालिक असर का पूरी तरह पता नहीं लग जाता. उन्होंने इसके लिए वैज्ञानिक अध्ययन कराए जाने की भी बात कही, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय करने से मना कर दिया. शुरू में जीईएसी ने माहिको कंपनी के परीक्षण से हासिल रिपोर्ट पर एक उप समिति बनाई थी. यह समिति एनजीओ के विरोध के बाद बनाई गई थी. देश के कई राज्यों– केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड– आदि में इस फ़सल का व्यापक विरोध किया जा रहा था.

दूसरे कई देशों में भी प्रतिबंध

यूरोपीय संघ के 20 देशों ने भी इसकी मुख़ालफत की है. इनमें जर्मनी, फ्रांस एवं स्पेन जैसे देश हैं. ऑस्ट्रिया और हंगरी भी इसी कतार में शामिल हैं. वहीं श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और अल्जीरिया में भी यह प्रतिबंधित है. जबकि अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, पराग्वे और दक्षिण अफ्रीका में इसे अनुमति मिल चुकी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बीटी बैगन ज़िंदगी या मौत

पी वी सतीश

बीटी बैगन के मामले में पूरे देश में चल रही विचार-विमर्श की प्रक्रिया का समापन जिस तरह से वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने अपने विचार प्रकट करके किया है, मैं भी उस पर अपनी राय देना चाहता था. लेकिन, मेरे दोस्त जो जनवरी 2010 में बैंगलुरु में एक सेमिनार का आयोजन कर रहे थे, वे चाहते थे कि मेरी राय दूरदर्शी हो. लेकिन मैं इस विचार से हैरान हूं. कोई व्यक्ति कैसे दूरदर्शी बयान दे सकता है? कोई बहुत ही मूर्ख आदमी यह सोच सकता है कि फलां व्यक्ति दूरदृष्टि वाला है और ऐसी बात कह सकता है, जो आगे चलकर बिल्कुल सही हो जाए. बात चाहे जो भी हो, जहां तक मैं अपनी बात करूं तो 40 साल से ज़्यादा हो गए. उन दिनों मैं कॉलेज में था. मैं दृष्टिदोष का शिकार हो गया. डॉक्टरों ने कहा कि मैंने नंगी आंखों से सूर्यग्रहण देख लिया है, इसलिए मेरी आंख की कॉर्निया क्षतिग्रस्त और नज़र अस्पष्ट हो गई है. वह पहला मौक़ा था, जब मेरी नज़र में सुधार किया गया. बाद में ऐसे कई अवसर आए, जब ज़िंदगी में मुझे अपनी नज़र में तत्काल सुधार की ज़रूरत महसूस हुई. चाहे वह साहित्य, कला और मीडिया के बारे में मेरी समझ की बात हो या फिर अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को समझने की बात क्यों न हो.

सत्तर के दशक की बात है. तब मैं दूरदर्शन के लिए टेलीविज़न प्रोड्यूसर का काम कर रहा था. उस समय मैं अक्सर कर्नाटक के गुलबर्ग, रायचूर और बीजापुर ज़िलों का दौरा करता था. ये वे ज़िले थे, जिन्हें विकास मामलों के जानकार बिल्कुल पिछड़ा मानते थे. मैं भी उन्हें वास्तविक तौर पर पिछड़ा ही मानने लगा. वहां मैं ऐसे लोगों से जुड़ा, जो मददगार प्रवृत्ति के थे. कहां मैं मीडिया से जुड़ा व्यक्ति और कहां उन जैसे पिछड़े लोग! उन्हें मुझसे सीखने को तैयार रहना चाहिए. लेकिन कुछ माह ही बीते होंगे, मेरा सारा दृष्टिकोण बदल गया. सुदूर बसे और दुर्गम माने जाने वाले गांवों के लोगों से जब मेरे ताल्लुकात बढ़े, उनकी चौपालों में चारपाई पर मेरा उठना-बैठना शुरू हुआ, उनकी रसोइयों तक मैं गया और उनके खेतों-खलिहानों तक पहुंचा तो धीरे-धीरे विकास के प्रति मेरा पूरा नज़रिया ही बदल गया. मैंने इस बात की तलाश शुरू कर दी कि डेवलपमेंट मीडिया में हमारे दृष्टिकोण कितने संकीर्ण थे. इससे बड़ा सुधार हुआ. मेरे नज़रिए में सबसे बड़ा बदलाव दो दशक पूर्व तब आया, जब आंध्र प्रदेश के मेडक ज़िले में पांच हज़ार दलित महिलाओं के साथ मैंने काम करना शुरू किया. यह भी वह इलाक़ा है, जो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है. वे महिलाएं समाज के काफ़ी अंत्यज्य वर्ग से ताल्लुक़ रखती थीं. वे सभी लघु और सीमांत किसान थीं. उनमें से ज़्यादातर पढ़ी-लिखी भी नहीं थीं. लेकिन, उन्होंने मुझे जो सिखाया, उससे मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन्हें खाद्य और फ़सल के बारे में गहरी समझ थी. उन्होंने कृषि के प्रति मेरे नज़रिए में परिवर्तन किया. उसके बाद इससे जुड़े मुद्दों पर मेरी पूरी सोच ही बदल गई.

इसलिए, अगर आज कोई दूरदर्शिता भरा बयान देना है तो वह उनका नज़रिया होगा. आज मैं उस नज़रिए को ही प्रस्तुत करना चाहूंगा. पिछले दिनों विश्व समुदाय के सामने जलवायु परिवर्तन पर कम्युनिटी चार्टर पेश करने के लिए मैं कोपेनहेगन में था. एक आयोजन में इस बात पर परिचर्चा हो रही थी कि दुनिया की सरकारों के सामने क्या मांग रखी जानी चाहिए. मध्य प्रदेश की एक महिला जो प्रतिनिधि मंडल के साथ थीं, अचानक बोलीं, उन्हें कह दीजिए कि हमें कोई मांग नहीं करनी है. लेकिन, अगर वे इस धरती पर जीवन फिर से वापस लाना चाहते हैं तो मांग हम लोगों के सामने उन्हें रखनी चाहिए. ऐसा इसलिए, क्योंकि जीवन और प्रकृति के साथ कैसे जिया जाता है और कैसे उनकी देखभाल की जाती है, इस बारे में केवल हमें पता है. कहने का मतलब यह कि उन्होंने उन सारी शिक्षाओं का निचोड़ मेरे सामने रख दिया, जिसे पिछले दो दशकों के दौरान मैंने सीखा था. उस महिला ने मुझसे जो कुछ कहा, उसकी शिक्षा यह थी कि अगर आप इस ग्रह पर कृषि को जिंदा रखना चाहते हैं तो इसे पृथ्वी, बीजों, पौधों, फसलों और खाद्यान्नों के साथ हमारे मानवीय रिश्ते के तौर पर देखा जाना चाहिए. सभी चीज़ों में ज़िंदगी अंतर्निहित है. इसे पहचानो और इसका आदर करो. उस महिला ने जो कहा, अगर उसे सही तरीक़े से समझा जाए और उस पर अमल किया जाए तो बीटी बैगन जैसे मुद्दे अप्रासंगिक हो जाएंगे.

जिस महिला के साथ मैंने काम किया, ऊंची पैदावार की अवधारणा पर वह जोर से हंस पड़ती है. उसके अनुसार, हाईब्रीड सीड्स वह चीज़ नहीं है, जिससे ख़ुशहाली लाई जा सके. वास्तव में ये वे बीज हैं, जो हमें आगम पंतालू (क्रेजी क्रॉप्स) देते हैं. यह अवधारणा इस विश्वास से निकली है कि प्रकृति के कुछ नियम हैं. और, नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमें धरती से कितना कुछ लेने की ज़रूरत है. अगर बेलगाम तरीक़े से ज़मीन से फ़सल लेने की कोशिश करेंगे तो आप धरती से जीवन पाने की चिरौरी नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उसका ख़ून चूस रहे होंगे. उस ख़ून से आपको थोड़ी देर के लिए भले ही ख़ुशहाली पाने में मदद मिल जाए, लेकिन अंततः वह मौत के मुंह में समा जाएगी और आप ख़ाली हाथ रह जाएंगे. आप अनाथ हो जाएंगे. आधुनिक विज्ञान यह बताता है कि हमें कभी भी उम्र में छोटी लड़की के साथ विवाह बंधन में बंधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. जब तक कि वह किशोरावस्था को पार नहीं कर लेती, उसे गर्भधारण नहीं करना चाहिए. हमारी आबादी बेलगाम न बढ़े और जन्म दर नियंत्रण में रहे, इसके लिए करोड़ों रुपये भी ख़र्च किए गए. विज्ञान भी इस बात का हिमायती है कि धरती पर भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए. तो फिर वही विज्ञान अंकुरण, जन्म और वृद्धि के प्राकृतिक चक्र को पूरा किए बग़ैर फ़सलों को सीमित अवधि में तैयार करने को जायज़ कैसे कह सकता है? हमारी आबादी न बढ़े, इसके लिए तो परिवार नियोजन जैसी योजना है, लेकिन धरती माता के लिए कोई इस नज़रिए से क्यों नहीं सोचता? वह अनिवार्य रूप से अनियंत्रित होकर हमें क्यों कुछ प्रदान करें?

अगर हम मेदक की दलित महिला के नज़रिए से देखें तो हमें तुरंत ही इस बात का पता चल जाएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका लक्ष्य धरती से अनियंत्रित पैदावार लेना है और जो प्रकृति के सभी नियमों से दूर होती जा रही है, कैसे जीवन का विज्ञान नहीं है और कैसे बीटी बैगन मौत का प्रतीक बन गया है. इसलिए हमारे सामने सवाल पृथ्वी पर जीवन का मार्ग प्रशस्त करने या प्रकृति की मौत का है. और, मुझे लगता है कि कुछ भी चुनना बहुत आसान है.

feedback@chauthiduniya.com

बीटी बैगन के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन

विशेषज्ञ समूह ने दोषपूर्ण भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति की ग़ैर मौजूदगी को माओवादियों को मिल रहे समर्थन के मूल कारकों में गिना.

सरकार कंपनियों के आगे नतमस्तक

यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि व्यवस्था को घर के भूखे-प्यासे और मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग नहीं दिखते या वह उन्हें देखना नहीं चाहती. जबकि उन ताक़तों के स्वागत में वह आरती का थाल सजाकर खड़ी है, जो घर को लूटने की मंशा लेकर आने को आतुर हैं.

आदियोग

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव गदगद हैं कि बड़े उद्योग राज्य पर बहुत मेहरबान हैं और अब तक कोई चार लाख करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं. छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने बस एक ही दशक तो पूरा हुआ है और कामयाबी का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया गया. गुजरी चार फरवरी को रायपुर में एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सम्मेलन का उदघाटन करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास की इस तेज़ रफ़्तार को और तेज़ किया जाएगा. निवेश के लिए और अधिक कंपनियों को न्यौता दिया जाएगा. हर तरह की सहूलियतों और रियायतों से उनका स्वागत किया जाएगा. कंपनियों को जगह से लेकर बिजली-पानी तक की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी.

गोया कि छत्तीसगढ़ न हुआ, मुनाफ़े के लुटेरों का खुला चारागाह कि कंपनियां आएं और कुदरत की बेशक़ीमती नेमतों का खजाना चट कर जाएं. मुट्ठी भर लोगों के हित में गांव के गांव वीरान हो जाएं और हज़ारों-हज़ार लोग तबाह हो जाएं. राज्य का शासन-प्रशासन कंपनियों के सामने हाथ जोड़े खड़ा है. जल, जंगल और ज़मीन की बलि चढ़े तो क्या, विकास से कोसों दूर खड़ी दुखियारी जनता पर मुसीबतों का पहाड़ टूटे तो क्या? आख़िर राज्य का तो विकास हो रहा है. जो इस विकास पर उंगली या प्रतिरोध में आवाज़ उठाए, वह विकास का दुश्मन है, माओवादी है. उसकी बोलती बंद कर दी जाएगी. इसे जम्हूरियत की बदक़िस्मती कहिए कि यह सवाल पूछना पड़ रहा है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार आख़िर किस लिए होती है, किसके लिए होती है? फ़िलहाल तो उड़ीसा की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी कॉरपोरेट जगत के सामने बिछ जाने की हद दर्ज़े की उतावली में है और इसके लिए क़ायदे-क़ानूनों को परे धकेल देने की जिद पर है. माओवाद के ख़तरे का हौव्वा अच्छे-अच्छों की हवा निकाल देने के लिए काफ़ी जो है. थोड़ा पीछे मुड़कर याद दिलाने की ज़रूरत है कि मई 2006 में योजना आयोग ने विकास और माओवादी उभार के आपसी रिश्तों की पड़ताल करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया था. इस समूह ने आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित बेहद संवेदनशील 20 ज़िलों के अलावा इन्हीं पांच राज्यों में माओवादी प्रभाव से मुक्त 20 दूसरे ज़िलों को अपने तुलनात्मक अध्ययन के लिए चुना था. विशेषज्ञ समूह ने अप्रैल 2008 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, घर आदि के संदर्भ में हमारे सामने दो दुनिया हैं. इस रिपोर्ट ने बेबाकी के साथ खुलासा किया कि सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं ने आर्थिक रूप से पहले से कमज़ोर स्थानीय समुदाय को कमज़ोर बनाने का काम किया. इसी वजह ने माओवादी प्रभाव को मज़बूती और विस्तार देने का आधार प्रदान किया. विशेषज्ञ समूह ने दोषपूर्ण भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति की ग़ैर मौजूदगी को माओवादियों को मिल रहे समर्थन के मूल कारकों में गिना. माना कि जो माओवाद के बारे में बहुत कम जानते हैं, वे भी जानते हैं कि माओवादियों का नारा रहा है-ज़मीन जोतने वालों की और माओवादियों की तमाम गतिविधियां ज़मीन पर ग़रीबों के क़ब्ज़े से जुड़ी रही हैं.

विशेषज्ञ समूह ने यह भी माना कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की परिकल्पना ख़ुद में ग़रीबों की आजीविका पर हमला है, भले ही उसकी स्थापना बहुफ़सली ज़मीन पर हो या न हो. इतना ही नहीं, विशेषज्ञ समूह ने छोटे और सीमांत किसानों को लीज पर ज़मीन दिए जाने के लिए नीति बनाए जाने और भूमिहीन किसानों द्वारा सरकारी ज़मीन पर क़ब्ज़े को अतिक्रमण न माने जाने की वकालत की. विशेषज्ञ समूह ने पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन का दर्ज़ा न दिए जाने और उसे अपनी कठपुतली बना देने के लिए राज्यों की तीखी आलोचना की. बेहतर और स्वच्छ प्रशासन की विफलता के लिए अफसरशाही को भी कठघरे में खड़ा किया.

यह पहली और अब तक की आख़िरी सरकारी रिपोर्ट थी, जिसने माओवादी समस्या के लिए सरकार और प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराया. माओवादियों से लड़ने के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खड़े किए गए सलवाजुड़ूम को तुरंत ख़त्म किए जाने की ज़रूरत भी सामने रखी गई. माओवादी अतिवाद को महज़ क़ानून व्यवस्था की नज़र से देखे जाने पर अपनी असहमति दर्ज़ करते हुए विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट ने माओवादी उभार के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को उजागर किया. सिफ़ारिश की कि भूमि अधिग्रहण क़ानून में सार्वजनिक उद्देश्य को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण तक सीमित रखा जाना चाहिए. कंपनियों के लिए ज़मीन हड़पने की कार्रवाइयों को कतई रोका जाना जाहिए. लेकिन, योजना आयोग की यह रिपोर्ट कहीं ठंडे बस्ते में फेंक दी गई और उसकी सिफ़ारिशों को धूल फांकने के लिए छोड़ दिया गया. इसके बाद प्रधानमंत्री न जाने कितनी बार दोहरा चुके हैं कि माओवादी देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हैं. केंद्रीय गृह मंत्री माओवादियों से निपट लेने की योजना को अंतिम मुक़ाम तक पहुंचाने में व्यस्त हैं. देश के सामने यह झूठ परोसा जा रहा है कि माओवादी ग़रीब जनता के विकास में बाधक बन गए हैं. ग़रीबों का भला किया जाना है तो पहले माओवादियों का सफाया ज़रूरी है. इसीलिए ऑपरेशन ग्रीन हंट है.

छत्तीसगढ़ में जनविरोध की एक झलक और (सबसे ऊपर) शिवनाथ नदी पर बना मोंगरा बांध, जो खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पा रहा

छत्तीसगढ़ ने निजी हाथों को अपनी नदियां बेच देने की मिसाल क़ायम की है. तीन साल पहले शिवनाथ नदी पर मोंगरा बांध बनाए जाने की शुरुआत हुई थी. प्रचार किया गया था कि बांध का पानी सिंचाई के काम आएगा. खेतों तक बस कहने भर को पानी पहुंच पाता है.

लेकिन, सच तो यह है और जिसकी तस्दीक योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह भी कर चुका है कि जब सुनवाई की गुंजाइश ख़त्म कर दी जाती है और ज़िंदा रहने का संकट गहराने लगता है तो आत्मघात की राह खुलती है या फिर हाथों में बंदूक़ आती है. इस सच से मुंह चुराना हालात को और अधिक पेचीदा और बेकाबू बना देने का काम करता है. छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा से लेकर बीजापुर, रायगढ़, कांकेर, सरगुजा, जसपुर तक में यही सबक हमारे सामने है. लेकिन जो न समझने पर अड़े हों, उन समझदारों को तो नहीं समझाया जा सकता. सच तो यह है कि दो दशक पहले उदारीकरण और निजीकरण का झंडा बुलंद किए जाने के साथ ही विकास की अवधारणा ने पलटी मारी थी. इसके चलते वंचितीकरण ने भी तेज़ गति पकड़ी. देशी-विदेशी कंपनियों के लिए लूट की ज़मीन तैयार की जाने लगी और बदले में असंतोष का स्वर उछाल मारने लगा. जो पहले से ग़रीब थे, वे और ग़रीब होते गए. साफ़ हो गया कि भला-भला सा लगने वाला वैश्वीकरण का नारा दरअसल पूंजीपतियों के लिए लूट के नए पैंतरे का नाम है, जिसमें विकास मायावी रूप धरता है और ग़रीबों को छलता है. याद रहे कि 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में टाटा के इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता किया था. तब माओवादियों ने कहा था कि यह करार विस्थापन का सबब बनेगा और ऐसे में वे चुप नहीं बैठेंगे. माओवादियों की इसी धमकी से निपटने के लिए सलवाजुड़ूम की पैदाइश हुई थी यानी आदिवासियों को आदिवासियों से भिड़ा दो और तमाशा देखो. और आज, दंतेवाड़ा ज़िले के तक़रीबन सात सौ गांव उजड़ चुके हैं. 50 हज़ार आदिवासी सलवाजुड़ूम के शिविरों में नरक की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बाक़ी तीन लाख उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे हैं.

माओवादियों के सफाए के नाम पर पुलिस, सुरक्षाबलों और सलवाजुड़ूम को लूट, आगजनी, हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों का सिलसिला चलाने का जैसे सर्टीफिकेट थमा दिया गया है. गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने सरकारी तौर-तरीक़ों और ज़्यादतियों का विरोध किया तो वह माओवादियों के समर्थक करार दिए गए. उन पर अपहरण करने तक का आरोप जड़ दिया गया. इस कदर घेराबंदी हुई कि उन्हें छत्तीसगढ़ से निकल भागना पड़ा. मेघा पाटेकर एवं संदीप पांडेय जैसे सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई. ख़ैर, सरकारी अत्याचारों की लंबी सूची है और जिसे अख़बारों में लगभग जगह नहीं मिल सकी.

भिलाई में एसीसी जामुल कंपनी का सीमेंट संयंत्र है. यह स्विटज़रलैंड की बहुराष्ट्रीय होलसिम ग्रुप कंपनी की इकाई है. कंपनी श्रम क़ानूनों के उल्लंघन के लिए ख़ासी बदनाम रही है, लेकिन उसका कभी बाल बांका नहीं हुआ, इसलिए कि उसे सरकार का वरदहस्त हासिल है. ऐसे में मज़दूरों को हड़ताल भी करनी होती है तो अचानक. कमाल की बात है कि पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाने और उसकी सुरक्षा के लिए किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के लिए यह कंपनी कई पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी है. लेकिन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नोटिस ने उसकी इस छवि की पोल खोल दी. उसे पर्यावरण के तय मानकों की अनदेखी करके पानी और हवा को ज़हरीला बनाने का दोषी पाया गया. कंपनी अब अपनी सफाई दे रही है कि वह प्रदूषण रोकने के लिए कितनी गंभीर है और क्या कुछ करने को तैयार है. देश में सीमेंट के कुल 128 संयंत्र हैं और उनमें से कुल छह को नोटिस थमाई गई. लेकिन, सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का. जांजगीर चांपा के डभरा ब्लॉक में एथेना पावर लिमिटेड की परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय पक्ष के सिलसिले में जन सुनवाई का आयोजन हुआ और कंपनी को हरी झंडी मिल गई. इस फ़ैसले को चुनौती दी गई. दबाव बना तो जांच-पड़ताल हुई. पता चला कि जन सुनवाई की कार्रवाई की फाइल और उसके वीडियो दस्तावेज़ में ख़ासा फासला था. तब कहीं जाकर कंपनी के पक्ष में दिया गया फ़ैसला निरस्त हुआ और अब नए सिरे से जन सुनवाई आयोजित करने का आदेश हुआ. यह फरवरी के पहले सप्ताह की बात है.

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने निजी हाथों को अपनी नदियां बेच देने की मिसाल क़ायम की है. राजनांदगांव ज़िले के अंबागढ़ चौकी ब्लॉक चलें. तीन साल पहले यहां शिवनाथ नदी पर मोंगरा बांध बनाए जाने की शुरुआत हुई थी. प्रचार किया गया था कि बांध का पानी सिंचाई के काम आएगा. सिंचाई के लिए पानी की निकासी का बंदोबस्त भी किया गया, लेकिन कुछ इस तरह कि आधा किलोमीटर बाद पानी का बड़ा हिस्सा वापस बांध की ओर चला जाता है और खेतों तक बस कहने भर को पानी पहुंच पाता है. बांध में डूबने के लिए पोसार गांव ख़ाली हो चुका है. बांध कुल 56 गांवों को निगलेगा. पहले चरण में 14 गांव डूब के निशाने पर हैं. ज़्यादातर गांव बांध के पानी से घिर चुके हैं. शौच-पेशाब के लिए जगह नहीं बची. खेती की ज़मीन पहले ही बांध में समा चुकी है. लेकिन सरकार के पास पुनर्वास की कोई नीति नहीं. जिनकी ज़मीन गई, उनमें से आधे लोगों को अभी तक मुआवज़ा नहीं मिल सका है. जिन्हें मुआवज़ा मिला भी, तो बाज़ार दर के आधे से भी कम पर. मतलब कि दूसरी जगह ज़मीन नहीं ख़रीदी जा सकती. लोग जाएं तो जाएं कहां, जिएं तो जिएं कैसे? वैसे, मोंगरा बांध का पानी भिलाई की कंपनियों के काम आएगा. जुरमिल मोर्चा और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (मज़दूर कार्यकर्ता समिति) मोंगरा बांध के ख़िलाफ़ साझा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है.

जिस दिन छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने कंपनीपरस्ती का सरकारी गीत गाया, उसके ठीक दूसरे दिन राज्य के कृषि सचिव के घर छापा पड़ा और तीन सौ करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला. यह विकास नाम की खेती में बेजा लाभ मार्का यूरिया छिड़कने का मुआवज़ा था. पकड़े गए तो चोर, वरना चौकीदार. क्या पता, न जाने कितनी डालों पर मधु कोड़ा बैठे हों. कंपनीपरस्ती कोई घाटे का सौदा है क्या? जितना बड़ा ओहदा, ईमान बेचने का उतना बड़ा इनाम!

feedback@chauthiduniya.com

वाममोर्चा सरकार रंगनाथ मिश्र आयोग की उन सिफ़ारिशों से सहमत है, जिनमें कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक, ख़ासतौर से मुसलमान शिक्षा और विकास में पिछड़ गए हैं.

बंगाल के मुसलमानों को दिखी उम्मीद की किरण

बिमल राय

आख़िरकार बंगाल सरकार ने संसद में रखी गई रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फ़ैसला कर ही लिया. यह फ़ैसला उस समय हुआ है, जब विपक्षी लहर को मोड़ने के लिए माकपा उठ खड़ी हुई है, जिसे बांग्ला में घुरे *दाड़ानो* कहा जाता है. सरकार को लगा कि मुसलमान केवल धर्म निरपेक्षता के बेदाग़ चेहरे और सांप्रदायिक सौहार्द्र के रिकॉर्ड से संतुष्ट नहीं होने वाले, उनकी दशा भी सुधरनी चाहिए. हालांकि आबादी के अनुपात में यह लॉलीपाप से ज़्यादा नहीं लगता. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में राज्य के मुसलमानों की हालत का जब खुलासा हुआ, तब सबकी आंखें खुलीं. राज्य की आबादी में मुसलमान 25 फ़ीसदी हैं. माना जाता है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों सहित स्थानीय निकाय चुनावों में वाममोर्चा की करारी हार का प्रमुख कारण मुस्लिम वोट बैंक का खिसकना रहा. रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने और अगले साल विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने केरल सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की पहल का अनुकरण किया है, जहां कुछ और मुसलमान उप-जातियों को अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) में शामिल कर आठ प्रतिशत तक आरक्षण देने का फ़ैसला किया गया है.

वाममोर्चा सरकार रंगनाथ मिश्र आयोग की उन सिफ़ारिशों से सहमत है, जिनमें कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक, ख़ासतौर से मुसलमान शिक्षा और विकास में पिछड़ गए है. मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फ़ैसले का भी ध्यान रखा है. उन्होंने कहा है कि सरकार किसी भी समुदाय को आरक्षण देने के लिए उसकी आर्थिक हालत को आधार बनाएगी और केवल वही परिवार दस प्रतिशत आरक्षण के हक़दार होंगे, जिनकी वार्षिक आय साढ़े चार लाख रुपये से कम होगी. पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की सिर्फ़ 12 जातियों को ओबीसी दर्ज़े में रखा गया है. जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लगभग पूरी मुस्लिम आबादी ही ओबीसी में शामिल है. राज्य सरकार ने 1995 में पहली बार माना कि राज्य में पिछड़ी जातियां भी हैं और उसने एक सूची तैयार की. देर से जागने की एक वजह यह थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडलवाद के दौर में जब पूरा उत्तर भारत आरक्षण की आग में जल रहा था, तब बंगाल में एक चिंगारी भी नहीं दिखी थी. वैसे बंगाल का सामाजिक ढांचा कुछ ऐसा है कि यहां जातिवाद की बुराइयां उभर नहीं पातीं. हालांकि पिछड़ी जातियों के अस्तित्व से इंकार नहीं किया जा सकता. बांग्ला अख़बारों के वैवाहिक विज्ञापनों में जातिवाद की जड़ों की गहराई आसानी से मापी जा सकती है, जिसमें चटर्जी कन्या के लिए चटर्जी वर को ही प्राथमिकता दी जाती है.

सरकार ने जिन 26 जातियों को पिछड़ा माना, वे हैं कपाली, कुर्मी, वैश्य कपाली, सूत्रधार, कर्मकार, कुंभकार, स्वर्णकार, तेली, नापित, जोगीनाथ, ग्वाला गोप, मैरा मोदक (हलवाई), बरूजीवी, मालाकार, सत्तसाची, तांती, कंसारी, शंखाकार, काइती, राजू, तंबोली, तमाली, नागर, करनी, धानुक और जुलाहा. वैसे मंडल कमीशन ने राज्य में 177 पिछड़ी जातियों की पहचान की थी. बाद में सरकार ने 37 मुस्लिम उप समूहों की पहचान की, जिनमें से चार को ओबीसी में शामिल किया जाना है. इनके अलावा खोट्टा, सरदार और बेलदार उप समूहों को भी सरकार की इनायत का इंतज़ार है, जिनकी आबादी 27 लाख के आसपास है. बंगाल सरकार के मौजूदा ऐलान से अजलाफ और अरजाल श्रेणी के पिछड़े मुसलमानों को फ़ायदा होगा. अशरफ समुदाय के मुसलमान धनी वर्ग में आते हैं, इसलिए उन्हें इस सूची से अलग रखा गया है. पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य मसुदल हुसैन के मुताबिक़, अंसारी और कुरैशी भी 12 पिछड़े मुसलमानों में शामिल हैं, पर बेलदार (क़ब्र खोदने वाले), अब्दाल (सफाईकर्मी), महलदार (मछुआरे), कहार (पालकी ढोने वाले) एवं कुछ अन्य उप-जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकता है. सरकार अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के अधिकारियों और आयोगों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बना रही है, जो अंतिम सूची तैयार करेगी. मुख्यमंत्री इस फ़ैसले को 2011 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर नहीं देख रहे. उनका कहना है कि रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश हो चुकी है और सरकार इसे राज्य में लागू करना चाहती है.

माकपा केंद्रीय कमेटी के सदस्य मोहम्मद सलीम ने कहा कि रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट अगर समय से संसद में रख दी गई होती तो सरकार बिना देर किए इसे राज्य में लागू कर देती. उन्होंने पिछली यूपीए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात कही, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग की गई थी और माकपा उस सरकार का समर्थन कर रही थी. मुख्यमंत्री और माकपा के दूसरे नेता भले ही इसे लागू करने को चुनावी फ़ायदे से न जोड़ें, पर हाल के चुनावों में मिली करारी शिकस्त को वे कैसे भूल सकते हैं? प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक़, राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 53 सीटों पर मुसलमानों के वोट निर्णायक हैं. तीन ज़िलों यानी मालदा, मुर्शिदाबाद एवं उत्तर दिनाजपुर और कुल 63 प्रखंडों में मुसलमानों की आबादी 63 प्रतिशत है. कहने की बात नहीं, राज्य की मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी मुसलमानों का है. विपक्षी दल, ख़ासकर भाजपा आरोप लगाती रही है कि अपना वोट बैंक मज़बूत करने के लिए माकपा इन घुसपैठिए मुसलमानों को राजनीतिक पनाह देती है. कूचबिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और चौबीस परगना आदि ज़िलों में अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों का जाल है. माकपा की धर्म निरपेक्षता पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई. मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को देखते हुए ही सरकार ने तस्लीमा नसरीन को राज्य के बाहर का रास्ता दिखाया. अभी हाल में हुए कोलकाता पुस्तक मेले में लेखिका आना चाहती थीं, पर सरकार ने अनुमति नहीं दी.

पश्चिम बंगाल में एक चौथाई आबादी मुसलमान है. पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं होते. दंगे बिहार में भी नहीं होते. मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक हालत दोनों राज्यों में बेहद ख़राब है. दंगे न होने को वाममोर्चा के नेता और कभी लालू प्रसाद यादव मेडल की तरह पहनते रहे हैं. सवाल यह है कि क्या मुसलमानों को इसलिए ख़ुश रहना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं और इस नाते क्या उन्हें यह भूल जाना चाहिए कि विकास और जीवन के तमाम मानदंडों पर वे पिछड़ रहे हैं? क्या कोई समुदाय सुरक्षा और विकास दोनों का हक़दार नहीं है? पश्चिम बंगाल सरकार ख़ुद मानती है कि एक चौथाई आबादी होने के बावजूद राज्य की नौकरियों में सिर्फ़ 2.1 फ़ीसदी मुसलमान हैं. सरकार के अपने उपक्रमों के उच्च पदों पर सिर्फ़ 1.2 फ़ीसदी मुसलमान हैं. बंगाल सरकार ने यह आंकड़ा सच्चर कमेटी को दिया है. केरल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगभग बराबर है, पर वहां राज्य सरकार की नौकरियों में मुसलमान साढ़े दस फ़ीसदी हैं. यहां तक कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में राज्य सरकार की नौकरियों में 5.4 फ़ीसदी मुसलमान हैं, जबकि वहां समुदाय की आबादी सिर्फ़ 9.1 फ़ीसदी है. बंगाल कांग्रेस का दावा है कि 1977 में वामपंथियों की सरकार बनने से पहले राज्य की नौकरियों में अभी की तुलना में ज़्यादा मुसलमान थे.

एक नज़र शिक्षा पर डालें. पूरे देश में 40 फ़ीसदी मुसलमान मिडिल पास करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 26 प्रतिशत. पूरे देश में 24 फ़ीसदी मुसलमान मैट्रिक तक तालीम पाते हैं, लेकिन बंगाल में सिर्फ़ 12 फ़ीसदी ही. बंगाल सरकार मदरसों को काफ़ी धन मुहैया कराती है, पर .मदरसा शिक्षा अभी भी रोज़गारपरक नहीं बन पाई है. प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक़, पश्चिम बंगाल में 29 फ़ीसदी बैंक खाते मुसलमानों के हैं, पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी सरकार के कहने पर जिन क्षेत्रों को अपेक्षाकृत सस्ता क़र्ज़ मिलता है, उनमें मुसलमानों का हिस्सा सिर्फ़ 9.2 फ़ीसदी है. पश्चिम बंगाल में औसतन एक बैंक खाते में 30,000 रुपये जमा हैं, जबकि औसत मुसलमान के खाते में सिर्फ़ 14,000 रुपये जमा हैं. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उक्त आंकड़े विस्तार से देखे जा सकते हैं. राज्य में मुसलमानों की हालत के बारे में लेखक एम के ए सिद्दीकी ने लिखा है कि केवल कोलकाता की आबादी का 15 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम है. 60 प्रतिशत रिक्शा-ठेला चालक, 90 प्रतिशत बीड़ी श्रमिक और जरी का काम करने वाले 100 प्रतिशत लोग मुस्लिम समुदाय के हैं. पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में है, जहां सबसे कम आरक्षण दिया जाता है. यहां दलित, आदिवासी और ओबीसी को मिलाकर 35 प्रतिशत आरक्षण है. ओबीसी के लिए सिर्फ़ सात फ़ीसदी आरक्षण है. मौजूदा क़ानूनों के मुताबिक़, मुसलमानों को आरक्षण इसी ओबीसी कोटे के तहत मिलता है. तमिलनाडु में ओबीसी कोटा 50 फ़ीसदी, केरल में 40 फ़ीसदी और कर्नाटक में 32 फ़ीसदी है. इसलिए इन राज्यों में उन मुसलमानों के लिए रोज़गार और शिक्षा के बेहतर मौक़े हैं, जो ओबीसी में शामिल हैं. तमिलनाडु में मुसलमानों की लगभग पूरी आबादी (95 फ़ीसदी) ओबीसी श्रेणी में आती है. समझा जा सकता है कि अगर बंगाल में ओबीसी को सिर्फ़ सात फ़ीसदी आरक्षण दिया जा रहा है तो यह मुसलमानों का कितना हित करेगा?

दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों में मध्यम वर्ग लगभग नदारद है. इसलिए नौकरियों, शिक्षा और बैंक लोन मिलने में हो रहे भेदभाव को लेकर उनमें आंदोलन का तेवर नहीं रहा. फिलीस्तीन पर इज़रायली हमले, डेनमार्क के कार्टून विवाद, इराक पर अमेरिकी हमले, तस्लीमा नसरीन के लेखन जैसे मुद्दों पर ही वामपंथी पार्टियां गोलबंद होती रही हैं. मुसलमानों की हिफ़ाज़त और उनके हित में बोलने के मामले में माकपा की बराबरी इस समय मुख्यधारा की कोई भी पार्टी शायद ही कर सकती है, पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने सच से परदा हटा दिया. लोकसभा चुनाव से पहले जारी घोषणापत्र में भी माकपा ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग से एक हिस्सा रखा, जिसमें इक्वल अपॉरच्यूनिटी कमीशन बनाने, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने और मुस्लिम बाहुल्य ज़िलों में रोज़गार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष पहल करने की बात कही गई. राज्य में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वर्षों से आंदोलन कर रहे सिद्दीकुल्ला चौधरी ने सरकार के इस फ़ैसले का स्वागत किया है, हालांकि उनकी मांग 20 प्रतिशत आरक्षण की है. कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने अपनी कोई साफ़ राय नहीं रखी है, लेकिन भाजपा ने कड़े शब्दों में फ़ैसले की आलोचना की. प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथागत राय ने कहा है कि राज्य में अपने डांवाडोल राजनीतिक काफ़िले को बचाने के लिए सरकार ने यह एक बहुत घटिया राजनीतिक पैंतरेबाजी की है. उनके मुताबिक़, अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां हमेशा से लगी हुई हैं. विहिप महासचिव प्रवीण तोगड़िया ने इसे हिंदुओं के कमज़ोर वर्गों के ख़िलाफ़ बताया है.

पिछले लोकसभा चुनाव में सीपीएम का सिर्फ़ एक मुसलमान प्रत्याशी पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत सका. मुस्लिम बाहुल्य इलाक़ों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. पश्चिम बंगाल में भाजपा का एक सक्षम चुनौती के रूप में मौजूद न होना अब माकपा के लिए मुसीबत है. डर और सुरक्षा की राजनीति की सीमाएं अब साफ़ नज़र आने लगी हैं. विधानसभा चुनाव से पहले अब इतना समय नहीं है कि राज्य में मुसलमानों के साथ न्याय किया जा सके. ख़ैर, ओबीसी का कोटा बढ़कर 17 फ़ीसदी हो गया है. यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार विकास की दौड़ में पिछड़े मुसलमानों की माली हालत सुधारने के लिए तहे दिल से कोशिश करेगी. अगर वह ऐसा कर पाती है तो तीन दशकों से किए गए निवेश का उसे राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा.

राह में मज़हब और अदालतें

यह एक संयोग ही था कि जिस दिन बुद्धदेव भट्टाचार्य ने राज्य में 10 फ़ीसदी आरक्षण की घोषणा की, उसी दिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फ़ैसला भी आया, जिसमें 15 मुस्लिम समुदायों को शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य सरकार के फ़ैसले को ख़ारिज़ कर दिया गया. मुख्य न्यायाधीश ए आर दवे की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय बेंच ने व्यवस्था दी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता. यह फ़ैसला 5-2 के बहुमत के आधार पर लिया गया. मालूम हो कि ओबीसी कोटे में ही मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलता है. अदालत के आदेश के तुरंत बाद मुख्यमंत्री के रोसैया ने फ़ैसले को विशेष अनुमति याचिका के ज़रिए सुप्रीमकोर्ट में चुनौती देने का निर्देश दिया. 26 जनवरी 2008 को अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खटिक समाज की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने पूछा था कि क्या इस्लाम जाति प्रथा की इजाज़त देता है? याचिका दायर करने वाले ने पक्ष रखा था कि हिंदू खटिकों (कसाई का काम करने वाले) को अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है और उन्हें आरक्षण मिल रहा है, जबकि मुसलमान खटिकों को नहीं, जिन्हें अजलाफ श्रेणी में रखा गया है. 1950 के राष्ट्रपति के आदेश, जिसमें हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म की अनुसूचित जातियों को ही आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया और इस पर सुप्रीमकोर्ट ने मुहर लगाई. इसके विरोध में ईसाइयों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी अदालतों की शरण लेते रहे हैं. हालांकि ईसाई और मुस्लिम धर्मों में हर नागरिक को समान माना जाता है. 2008 की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा था, क्या मुसलमान जाति प्रथा स्वीकार करने लगे? हमने सोचा था कि उनमें सिर्फ़ अमीर और ग़रीब दो ही श्रेणियां हैं. न्यायमूर्ति ने इस संबंध में केरल का उदाहरण दिया, जहां मुस्लिम समुदाय में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है. वैसे याचिका दायर करने वाले ने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की रपटों के आधार पर ही आरक्षण की मांग की थी. इन दो रपटों के आने के बाद इस संबंध में पेचीदगियां और बढ़ गई हैं.

feedback@chauthiduniya.com

मैंने अनायास ही पूछ लिया, अभी टूरिस्ट आ रहे हैं या नहीं? जवाब मिला, अभी ठंडी है न साहब, इसलिए टूरिस्ट कम आता है. गर्मी में ज़्यादा टूरिस्ट आता है.

हमारे लिए आज़ादी हमारी कमाई है

उमाशंकर मिश्र

पृथ्वी के स्वर्ग यानी कश्मीर में रहने वाला हर शख्स सिर्फ़ अमन और चैन चाहता है, जिससे वह दो जून की रोटी आसानी से कमा सके. लेकिन, दुर्भाग्य यह है कि पिछले बीस सालों से यहां आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच में पिसना आमजन की नियति बन गया है.

क़रीब 60 वर्षीय अब्दुल सलाम मुंडु को देखकर यह नहीं समझ में आता कि झुर्रियां उनके चेहरे पर हैं या फिर उनका चेहरा ही झुर्रियों के बीच है. इतने पर भी मुंडु की हाज़िरजवाबी और बेबाकी देखते ही बनती है, झूठ नहीं बोलता साहब, आपसे औरों की तरह 400 या 500 नहीं लूंगा. सिर्फ़ 150 रुपये दे देना, हम आपको पूरा डल लेक दिखाएगा. आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे 200 से 250 रुपये भी दे सकता है. हम आपको ग़लत नहीं बोलेगा साहब, आप हमारा मेहमान है, इसलिए ख़ूब ख़िदमत करेगा हम आपका, पारंपरिक फैरन पहने हुए छरहरी क़द–काठी के अब्दुल सलाम मुंडु के इतने आग्रह पर उनकी बात मैं टाल नहीं सका. मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा देर नहीं घूमना, इसलिए सौ रुपये ही दूंगा. आमतौर पर इतने कम पैसों में कोई भी शिकारे वाला टस से मस नहीं होता. सीजन में तो यही शिकारे वाले सैलानियों से 500 से 600 रुपये तक वसूल लेते हैं. बहरहाल मेरी बात पर अब्दुल राजी हो गए और हाथ पकड़ कर अपने शिकारे की ओर लेकर चल पड़े. झील तक क़रीब 200 गज के रास्ते के बीच अब्दुल लगातार बोलते रहे. उन्होंने डल झील समेत कश्मीर और स्थानीय आवभगत के बारे में बताकर आकर्षण का एक सूक्ष्म एवं वर्चुअल रेखाचित्र मेरी आंखों के आगे खींच दिया.

झील के किनारे पहुंचते ही अचानक उन्होंने मुझसे कहा, आप यहीं रुकिए, मैं शिकारे को जरा सजा लेता हूं. ख़ूब ख़िदमत करेगा हम आपका. फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर शिकारे की गद्दीदार सीट पर बैठाते हुए हाथ में एक टोकरी थमाकर कहा, यह कांगड़ी है साहब, इससे आप हाथ सेंक सकते हैं और पास रखने से सर्दी भी नहीं लगेगी. फिर शिकारे के दूसरे सिरे पर खड़े होकर उन्होंने अपने साथी राशिद को आवाज़ लगाई और मुझसे मुख़ातिब होते हुए कहा कि हम अकेला नाव नहीं चलाएगा साहब, दो लोग चलाएगा, जिससे जल्दी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज दिखा सकें.

इतने में राशिद भी आ गए और अब्दुल ने शिकारे पर बैठकर पतवार घुमानी शुरू कर दी. शिकारा थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अब्दुल ने ऊंची आवाज़ में कहा, यह छोटा लेक है और इसी के पास में यह गोल्डन लेक है. उन्होंने बताया कि झील के इस हिस्से में ही पंच सितारा हाउसबोट है, जहां अंग्रेज आकर ठहरते हैं. इसलिए इसे गोल्डन लेक कहा जाता है. थोड़ा और आगे बढ़े तो झील के पानी पर तैरते खरपतवार की तरफ़ इशारा करते हुए बताया कि यह लोटस गार्डन है. यहां कमल खिलते हैं, लेकिन अभी सर्दी की वजह से सब मुरझा गए हैं. जब थोड़ा मौसम बदलेगा तो यहां सुंदर कमल देखने को मिलेंगे. कुछ ही दूरी पर लोटिंग गार्डन था. अब्दुल ने बताया कि गर्मी के मौसम में लोटिंग गार्डन में टमाटर, खीरा, कमल ककड़ी जैसी सब्जियों की खेती होती है.

सुबह के क़रीब 11 बज रहे थे. घने कोहरे की चादर से छनकर आ रही मखमली धूप से डल झील के पानी में सुनहरा प्रकाशपुंज समेटे किरणें उठ रही थीं और ठंडी हवा के झोंके शिकारे को अधिक तेज़ी से धकेल रहे थे. झील में तैरते शिकारे से दूर पहाड़ की चोटी पर कोहरे की चादर में लिपटे शंकराचार्य मंदिर को देखा जा सकता था. सूरज की किरणें मंदिर के गुंबद पर पड़ रही थीं और शंकराचार्य मंदिर धीरे–धीरे इस धुंधले आवरण के आगोश से बाहर झांकने लगा था. पास में रखी कांगड़ी से थोड़ी–बहुत गर्माहट ज़रूर मिल रही थी. वैसे तो अब्दुल मुंडु की बातें भी कम गर्मजोशी भरी नहीं थीं.

इतना सब चल ही रहा था कि शिकारे के पास एक और नाव आकर रुक गई. नाव में दो नवयुवक मुझे पारंपरिक कश्मीरी फैरन और साफा पहन कर फोटो खिंचवाने के लिए सैलानियों की सुंदर तस्वीरें दिखाकर रिझाने लगे. अंततः उन्होंने कश्मीर की मनमोहक वादियों का हवाला देते हुए फोटो खिंचवाने के लिए बाध्य कर दिया. इस बीच अब्दुल भी बोल पड़े, कश्मीर में कहीं भी फोटो खिंचाएंगे तो अच्छा आएगा साहब. फोटो खिंचवा कर हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक दूसरे व्यक्ति ने शिकारे के दाईं तरफ़ अपनी नाव लगा दी. उसने अपने खेतों में उगाई गई केसर दिखाकर उसके सैकड़ों फ़ायदे गिनाने के बाद कहा कि अभी सीजन का टाइम नहीं है, इसलिए आपको सस्ते में दे दूंगा. जब मैंने उसके आग्रह को नकार दिया तो उसने एक दूसरे डिब्बे से गहरे भूरे रंग का एक चमकदार सा दिखने वाला टुकड़ा निकाला और उसे दिखाते हुए धीरे से कहने लगा कि यह शिलाजीत है, दूर हिमालय में मिलने वाले इस पत्थर को पहाड़ का पसीना भी कहा जाता है. यह कई प्रकार की बीमारियों में अचूक इलाज के लिए कारगर है.

इससे पहले कि अपने पिटारे में से वह मोबाइल बोट वेंडर कुछ और निकाल कर दिखाता, मैंने केसर की एक डिब्बी लेकर उसे अलविदा कह दिया. यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था कि बाईं तरफ़ एक और नाव आकर खड़ी हो गई. उसमें बैठे अधेड़ उम्र के छरहरे व्यक्ति ने नाव के बीचोबीच कई तरह के सामान सजा रखे थे. एक छोटा सा चमकीले तराशे हुए पत्थरों से जड़ा पर्स दिखाते हुए उसने कहा कि यह कश्मीरी पर्स है. और भी कई चीजें वह दिखाने लगा, इस बीच कश्मीरी पर्स को अपने हाथ में लेकर मैंने एक फोटो खींच ली.

इस तरह देखें तो डल झील में पानी पर तैरती हुई एक अलग ही दुनिया नज़र आती है. वैसे अब्दुल मुंडु से काफ़ी कुछ जानने को बाक़ी रह गया था. इसी बीच शिकारा डल झील के बीचोबीच पहुंच गया. आसपास पुराने से दिखने वाले पानी पर तैरते हुए हाउसबोट की कतारों के बीच अब्दुल ने अपना शिकारा लगा दिया और कहा, इसे ओल्ड सिटी कहते हैं. मैंने पूछा, और क्या–क्या है डल झील में देखने के लिए? जवाब में अब्दुल ने बताया कि चार चिनार, कबूतरखाना, स्वीमिंग पूल, मोटरबोट और भी बहुत कुछ है. ओल्ड सिटी पानी पर तैरते हुए बाज़ार का नाम है, जहां कश्मीरी कला, संस्कृति, परंपरा और हुनरमंदी की मिसाल नायाब चीजें बिकती हैं. अब्दुल ने मुझे ओल्ड सिटी से घरवालों के लिए शॉल आदि लेने को कहा, लेकिन मेरे मना करने पर उन्होंने शिकारे का रुख़ मोड़ दिया.

मैंने अनायास ही पूछ लिया, अभी टूरिस्ट आ रहे हैं या नहीं? जवाब मिला, अभी ठंडी है न साहब, इसलिए टूरिस्ट कम आता है. गर्मी में ज़्यादा टूरिस्ट आता है. लड़ाई के डर से भी लोग कम आते हैं. यह हमारी बदक़िस्मती है कि लड़ाई की वजह से टूरिस्ट नहीं आते तो हम कैसे कमाएगा? हम लोग मर जाएगा. आप भी बाहर जाकर सबको बताएंगे कि अब्दुल अच्छा आदमी था, हमारा बहुत ख़िदमत किया, लेकिन उसका बिजनेस नहीं है. लीडर तो अपना काम करता है, हमारा ख्याल नहीं रखता है. हमारा सुनता नहीं. यहां तो अच्छी बात बोलेगा तो गोली खाएगा. दो लोगों की लड़ाई में हम पिसते हैं. ग़रीब का तो कोई सुनता ही नहीं. बिना रुके अब्दुल मुंडु इतना कुछ कह गए, जो हर आम कश्मीरी के दिल में हर रोज पिछले 20 सालों से दबा हुआ है.

मैंने मुंडु से सवाल किया, आपने तो मिलिटेंसी का दौर कश्मीर में देखा होगा. किस तरह का मंजर अपनी आंखों से देखा है आपने? हमने बर्बादी देखा है साहब, आसमान की तरफ़ मुंह करके चप्पू चलाते हुए अब्दुल ने जवाब दिया. आगे वह फिर कहने लगे, यहां तो सबका धंधा टूरिज़्म है. टूरिस्ट नहीं आएगा तो हम कैसे जिएगा? आप सरकार से क्या चाहते हैं? प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा, अमन और आज़ादी. मैंने पूछा कि आज़ादी का आपके लिए क्या मतलब है? तो बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब अब्दुल सलाम मुंडु ने दिया. उन्होंने कहा, हमारे लिए आज़ादी हमारा कमाई है. सबका मर्जी है हमको काम मिले.

कश्मीर में चार दिन रहकर ऐसा महसूस हुआ कि अलगाववादियों, राजनीतिक पार्टियों, मीडिया और यहां तक कि कश्मीरी लोगों के मन में भी आम जनजीवन के बीच फौज की मौजूदगी को लेकर एक तरह की ख़िलाफ़त थी. आम लोगों की हिफाज़त में लगे फौजियों को लेकर स्थानीय लोगों में इस तरह ख़िलाफ़त का बीज पनपने का कारण क्या हो सकता है? यह सवाल मेरे मन में कौंधने लगा. इसका जवाब एक आम कश्मीरी ही दे सकता था. अब्दुल ने मेरी इस जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, फोर्स मदद देता है, उसका ड्यूटी है. वह भी मरता है, हमको भी बचाता है. अगर यह भी नहीं होता तो लड़ाई (मिलिटेंसी) की वजह से यहां आदमी कुत्ता की माफ़िक मरता. आर्मी तो हमारी हिफाज़त में है. कोई दुश्मन आया और उसने जंग उठाया तो फोर्स बेचारा क्या करेगा? वह भी मरता है. और, हम लोग तो ख़ाली बैठते ही मर जाएंगे. हमारा तो यही चप्पू है, चलाता है तो कमाता है.

बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थीं, लेकिन समय पूरा हो गया था और शिकारा भी धीरे–धीरे वापस किनारे की ओर बढ़ रहा था. किनारे पर पहुंच कर अब्दुल को मैंने पूर्व निर्धारित मेहनताने से 50 रुपये अधिक दिए तो मुस्करा कर उन्होंने कहा, आप ख़ुश हैं न साहब? अब जब आप बाहर जाएगा तो अपने जानने वालों को भी अब्दुल सलाम मुंडु के शिकारा नंबर 15 में आने के लिए जरूर बोलना.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... प्रधानमंत्री जी और महंगाई! ...धीर

पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाक़े में सर्वे के दौरान पता चला कि यहां जो लोग 15 या 20 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं, उनके पास भी राशनकार्ड नहीं हैं.

शीला जी, कैसे ज़िंदा रहेंगे ग़रीब

दिल्ली की जन वितरण प्रणाली में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार प्रकाश में आया है. सरकार अमीरों को ग़रीबी का सर्टिफिकेट दे रही है. मतलब ग़रीबी रेखा से ऊपर वालों को बीपीएल कार्ड बांट रही है. दूसरी ओर ग़रीबों के पास राशनकार्ड ही नहीं हैं. हद तो यह है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस समस्या से निपटने के लिए जन वितरण प्रणाली को ही ख़त्म करने की योजना बना रही हैं.

शशि शेखर

- ज़्यादातर ग़रीब परिवारों के पास राशनकार्ड नहीं
- एपीएल कोटे वालों के पास बीपीएल कार्ड
- दिल्ली में पीडीएस को ख़त्म करने की योजना

जिस देश के नेताओं पर चारा, खाद, चीनी खा जाने और कोलतार पी जाने तक के आरोप लगते हों, वहां की जनता (अपेक्षाकृत अमीर) अगर ग़रीबों का राशन हड़प ले तो ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए. लेकिन आश्चर्य तब होता है, जब यह सब कुछ देश की राजधानी यानी दिल्ली में हो रहा हो. दरअसल, दिल्ली की जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन में घोटाले का मामला प्रकाश में आया है. ज़्यादातर एपीएल कार्ड वाले लोग बीपीएल कार्ड के कोटे में सेंधमारी कर चुके हैं. बड़ी संख्या में ग़रीब लोगों के पास राशनकार्ड ही नहीं है. यह खुलासा हुआ है एक सर्वे रिपोर्ट से, जिसे अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान दिल्ली एवं नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड डिबेट इन डेवलपमेंट ने तैयार किया है. रिपोर्ट में राजधानी के नेहरू कैंप, मानसरोवर झुग्गी–झोपड़ी, हर्ष विहार एवं खजूरी खास जैसे पिछड़े इलाक़ों में रहने वाले परिवारों को शामिल किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक़, सरकारी आंकड़ों के मुक़ाबले दिल्ली में आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवारों की संख्या कहीं ज़्यादा है. इसमें भी लगभग 50 फ़ीसदी परिवारों के पास राशनकार्ड हैं ही नहीं. महंगाई ने जीना हराम कर दिया है, सो अलग.

जून–अक्टूबर 2009 के दौरान पूर्वी दिल्ली के कुछ ख़ास इलाक़ों के 80 घरों में जाकर राशनकार्ड के बारे में पूछा गया. इसके बाद जो अंतिम सूचना मिली, वह चौंकाने वाली थी. 13 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड, 19 के पास बीपीएल और 7 परिवारों के पास एपीएल कार्ड थे. आश्चर्यजनक रूप से 41 परिवारों के पास किसी भी तरह का राशनकार्ड नहीं था. मतलब यह कि 51 फ़ीसदी लोगों के पास राशनकार्ड नहीं था. हालांकि 2004–05 के एक सर्वे के मुताबिक़, दिल्ली की 26 फ़ीसदी आबादी, जो ग़रीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती है, उसमें से 33 फ़ीसदी के पास बीपीएल कार्ड, 39 फ़ीसदी के पास एपीएल कार्ड और 28 फ़ीसदी के पास राशनकार्ड नहीं हैं. लेकिन, इस पूरे सर्वे का सबसे दुखद पहलू यह है कि ग़रीबी रेखा से ऊपर रहने वाले 74 फ़ीसदी में से 18 फ़ीसदी परिवार ऐसे हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड हैं. ज़ाहिर है, वे परिवार ग़रीबों का हक़ मार रहे हैं. इसके अलावा राशनकार्ड पर जितना अनाज ग़रीबों को मिलता है, वह एक परिवार की ज़रूरत का महज़ 60 फ़ीसदी ही होता है.

पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाक़े में सर्वे के दौरान पता चला कि यहां जो लोग 15 या 20 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं, उनके पास भी राशनकार्ड नहीं हैं. इसकी मुख्य वजह यह है कि इन परिवारों द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश न कर पाना, जिससे साबित हो सके कि अमुक परिवार दिल्ली का निवासी है. ऐसे किराएदारों में ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश से आए लोग हैं. हर्ष विहार की तीन गलियों में सर्वे किया गया. वहां लगभग 628 परिवार रहते हैं, जिनमें से 10 फ़ीसदी किराएदार हैं. पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि इनमें से 25 फ़ीसदी परिवारों के पास राशनकार्ड नहीं हैं. सर्वे टीम ने जब वहां के 20 ऐसे परिवारों से संपर्क किया, जो ग़रीबी रेखा के नीचे थे, तो पता चला कि उनमें से 14 परिवारों के पास राशनकार्ड थे ही नहीं. यह भी पता चला कि अगर कोई कार्डधारक दो दिनों के भीतर अपना राशन नहीं लेता है तो राशन दुकानदार सारा अनाज काला बाज़ार में बेच देता है और रजिस्टर पर इंट्री कर देता है. नाप–तौल में घपला तो आम शिक़ायत थी.

लेकिन, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस समस्या पर ध्यान देने या सुधार करने के बजाय जन वितरण प्रणाली को ही ख़त्म करने की योजना बना रही हैं. शीला दीक्षित जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भ्रष्टाचार की बात तो स्वीकार करती हैं, फिर भी वह मौजूदा व्यवस्था को सुधारने के बजाय योजना आयोग से इसे ख़त्म करने की अनुमति मांग रही हैं. अब वह ग़रीबों को राशन के बदले हर महीने 1100 रुपये देने के फ़ैसले पर विचार कर रही हैं, जिनमें से 1000 रुपये खाद्य सब्सिडी और 100 रुपये किरोसिन सब्सिडी के तौर पर देने की योजना है. लेकिन, उन्हें यह सोचना होगा कि ख़ामियों पर ध्यान देने के बजाय किसी व्यवस्था को भंग कर देने से समस्या ख़त्म नहीं हो जाती. नई व्यवस्था अपने साथ कोई समस्या नहीं लाएगी, इसकी क्या गारंटी है? दूसरी ओर, दिलचस्प रूप से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जन वितरण प्रणाली के लिए देश में काफ़ी खाद्यान्न है और सरकार पीडीएस को मज़बूत करेगी. वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाला कोई भी परिवार भूखा न रहने पाए. आंकड़ों के मुताबिक़, देश में पांच करोड़ टन खाद्यान्न का स्टॉक है. बावजूद इसके न सिर्फ़ दिल्ली, बल्कि देश के कई हिस्सों में जन वितरण प्रणाली की स्थिति काफ़ी दयनीय है. कई जगह लोगों को राशन नहीं मिलता. और, मिलता भी है तो पूरा नहीं मिलता. लेकिन दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री हारुन युसुफ ने चौथी दुनिया से हुई बातचीत में जो कुछ कहा, उसके मुताबिक़ प्रधानमंत्री के दावे अर्थहीन नज़र आते हैं. जब हारुन युसुफ से दिल्ली के ऐसे ग़रीब परिवारों के बारे में पूछा गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो युसुफ इसके लिए केंद्र सरकार की ही नीति को इसके पीछे की वजह बताते है. युसुफ कहते है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए चार लाख नौ हज़ार राशन कार्ड का ही कोटा बनाया है और हम जानते है कि दिल्ली में ग़रीब परिवारों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इस कोटे को केंद्र सरकार नहीं बढाती है.

प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी कहा है कि भारत के लोग भूख की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए मरते हैं, क्योंकि भारतीय नौकरशाही व्यवस्था में मानवीय गरिमा का कोई महत्व नहीं है. साथ ही नेताओं के पास वह राजनीतिक इच्छाशक्ति भी नहीं है, जिससे जन वितरण प्रणाली को मज़बूत बनाया जा सके.

shashishekhar@chauthiduniya.com

दिल्ली में राशन कार्ड की स्थिति(जून-अक्टूबर2009)

	अंत्योदय	बीपीएल	एपीएल	कोई कार्ड नहीं	कुल
कुल	13	19	7	41	80
प्रतिशत	16	24	9	51	100

दिल्ली में राशनकार्ड की स्थिति (2004-2005)

(जनसंख्या %)	अंत्योदय/बीपीएल	एपीएल	कोई कार्ड नहीं
बीपीएल (26)	32.7%	39.1 %	28.2%
एपीएल (74)	18.2%	57.6%	24.2%

हारुन युसुफ
खाद्य एवं जन आपूर्ति मंत्री, दिल्ली सरकार.

भारत सरकार ने राशनकार्ड के संबंध में चार लाख नौ हज़ार की एक सीमा बना रखी है . सर्वे बताता है कि दिल्ली में बीपीएल कार्डों की संख्या बढ़नी चाहिए. हम सहमत हैं और गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं. केंद्र सरकार के सामने भी यह बात रखी गई है.

बी एल जोशी
एनसीआरडीडी, दिल्ली.

जिन लोगों के जिस तरह के राशनकार्ड बनने चाहिए, वे नहीं बन रहे हैं. दरअसल, लोगों की पहचान ही ग़लत तरीक़े से की जा रही है. बीपीएल कार्ड ग़रीबों को नहीं मिलता. ग़लत सूचना देकर ग़रीबी रेखा से ऊपर के लोग बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं.

दिलवालों की दिल्ली में ऐसे जीते हैं ग़रीब

दिल्ली का एक चेहरा यहां की झुग्गी झोपड़ियां और यहां रहने वाले ग़रीब भी हैं

- पूर्वी दिल्ली की एक अनाधिकृत कॉलोनी है हर्ष विहार. रजनी एवं उसके पति राधेश्याम अपने तीन बच्चों के साथ एक कमरे के मकान में रहते हैं. राधेश्याम की मासिक आय तीन हज़ार रुपये है और रजनी की एक हज़ार रुपये. यानी परिवार की कुल कमाई चार हज़ार रुपये महीना है. खाने पर 1500 रुपये, बिजली पर 350 रुपये, रसोई गैस पर 500 रुपये, दवाइयों पर 100 रुपये और तंबाकू आदि पर 60 रुपये ख़र्च हो जाते हैं. पांच लोगों के इस परिवार में रोजाना 250 ग्राम दूध आता है, ताकि दो वक़्त की चाय बन सके. इसमें भी महीने के 180 रुपये चले जाते हैं. रजनी दो साल पहले गांव से आते वक़्त दो किलो दाल लेकर आई थी. वह दाल अभी तक बची हुई है. पिछले दो महीने से घर में दाल नहीं बनी. यह परिवार एपीएल कार्डधारक है. महीने में पांच किलो चावल (9 रुपये प्रति किलो) और 10 किलो गेहूं (7 रुपये प्रति किलो) मिलता है. रजनी को हर महीने खुले बाज़ार से गेहूं और चावल ख़रीदना पड़ता है. स्थिर आय और बढ़ती महंगाई के चलते इस परिवार को अपना बजट संतुलित रखने के लिए खाद्य सामग्री में कटौती करनी पड़ रही है.
- सीता देवी अपने दो बच्चों, पति और देवर के साथ इसी इलाक़े में रहती हैं. पति और देवर की मासिक आय 1500 रुपये है. सीता शादियों-समारोहों में बर्तन धोकर महीने भर में 1500 रुपये कमा लेती हैं. पति शराबी है. वह अपनी कमाई शराब पर ख़र्च करने के बाद सीता से भी ज़बरदस्ती पैसा मांगता है. सीता के पास भी एपीएल राशनकार्ड है. राशन दुकान से जितना भी अनाज मिलता है, उसके अलावा सीता को खुदरा बाज़ार से हर महीने पांच किलो चावल और 40 किलो गेहूं ख़रीदना पड़ता है. घर में कभी भी दाल नहीं बनती. कभीकभार शादी-समारोह से लाई गई सब्ज़ी ही बच्चे खा पाते हैं. घर के सदस्य जो कपड़े पहनते हैं, वे दान के हैं. ज़रा सोचिए, महंगाई की मार से ऐसे परिवार ख़ुद को कैसे बचा पाते होंगे?
- खजूरी की झुग्गी-झोपड़ी में रेहड़ी पर चार भाई मिलकर समोसे और जलेबी बेचते हैं. पहले महीने की कमाई थी 40 हजार रुपये. महंगाई बढ़ी, आलू के दाम बढ़ गए, फिर भी वे एक समोसा 5 रुपये का ही बेचते हैं. वजह, दाम बढ़ाने या साइज़ घटाने पर बिक्री कम होने की आशंका है. ज़ाहिर है, आमदनी घट गई. नतीजतन, महंगाई बढ़ने से एक तो परिवार की आमदनी घटी, दूसरी ओर अपनी ज़रूरतें भी कम करनी पड़ रही हैं.

चौथी दुनिया

समाज में महिलाओं का दर्ज़ा आज भी पुरुषों के बाद और निम्नतर माना जाता है. समाज की तथाकथित हाई सोसाइटी में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है.

मलेशिया की छवि एक शांत राष्ट्र की रही है, जहां जातीय और धार्मिक विविधता देखने को मिलती है.

चौथी दुनिया

एम जे अकबर

नए ब्राह्मणों से ख़तरा

भारतीय लोकतंत्र विनाशकारी ख़तरे में है. यह ख़तरा इसे आत्मविश्वासी, आक्रमक, स्पष्टवादी, देशभक्त एवं साधन संपन्न ताक़तों से है. यह ख़तरा इसे संपन्न लोगों की सफलता से है. यह सलाह देना कुछ अतिशयोक्ति वाली बात हो सकती है कि इस वर्ग की ख़ासियत संवेदनशीलता और अंग्रेज़ी है.

शायद सफल लोगों में कई आफ्टरशेव या परफ्यूम को नापसंद करते हों. साथ ही वह इतने मूर्ख भी नहीं होंगे कि इसकी ख़ुशबू का अहसास उन्हें 15 फीट पहले ही हो जाए. वह भी इस वजह से कि यह आज के समय का सबसे विज्ञापित आफ्टरशेव है. लेकिन वे अंग्रेज़ी भाषा के प्रति वफ़ादार हैं. इसकी वजह भी है. दरअसल अंग्रेज़ी भाषा पूरी दुनिया में सफलता का मूलमंत्र है. यह बात साबित भी हो चुकी है. 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई. और, 30 के आसपास का (बहुत अधिक कहें भी तो 40) का यह नया वर्ग उस समय से चले आ रहे सतत उच्च विकास का नतीजा है. यह वर्ग अपने साथ शासन के लिए एक नई सोच, ख़ुशमिज़ाजी मक़सद और एक पेशेवर नज़रिया लाया. साथ ही यह सामाजिक दायित्वों में कमी का स्वागत करता है. इसलिए इस वर्ग के लोगों को एक संभावित अदृश्य ख़तरे के तौर पर क्यों समझा जाना चाहिए? उनकी दौलत मौजूदा बिज़नेस, मीडिया और राजनीति में अच्छी ख़ासी दख़ल रखती हैं. उनकी ज़िम्मेदारियों को दरकिनार कर दिया जाता है. और, इस बात को उनके सेलिब्रिटी स्टेटस से अलग रखकर ही देखा जाता है. राजनेता हमेशा से मशहूर रहे हैं और अभी भी हैं. यदि आप सार्वजनिक ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप पर आम लोगों की नज़र रहेगी ही. लेकिन वे आम लोग सेलिब्रिटी नहीं होते हैं. यह दोनों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करता है.

लेकिन इसे भी शोरशराबे की संस्कृति से दबाया जा रहा है. यह समृद्धि और विकास कर रहे संभ्रांत तबके की एक और वर्चस्ववादी ख़ासियत है. ख़तरा इस तथ्य में निहित है कि इस क्रीमी लेयर आबादी का 20 फ़ीसदी हिस्सा शीर्ष पदों पर क़ब्ज़ा जमाए हुए है. लेकिन, 80 फ़ीसदी लोगों के लिए फ़ैसले लेने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है. निस्संदेह इससे ग़रीबी की समस्या सामने आती है. इस मसले को हल करने की कई कोशिशें की गईं. इतनी कोशिशें भारत में ही हो सकती हैं, जहां भिखारी अपनी गाड़ियों की खिड़की से टकटकी लगाकर नहीं देखते हैं. दुर्भाग्यवश, यदि कोई भिखारी बड़ी गाड़ियों की काली फ़िल्मों वाले शीशे से नज़र नहीं आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह है ही नहीं. ग़रीबी की वजह से ही ग़रीबी है. उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है. और, इसीलिए सत्ता में उनकी भागीदारी नाममात्र की है. यदि एक मायने में देखें तो इसके आधुनिक स्वरूप में पुरानी जाति व्यवस्था नज़र आती है. यह सरकार की कार्मिक विचारधारा है, जिसे नए ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित–प्रसारित किया जा रहा है. ये ब्राह्मण पीछे टीक (चुटिया) रखने के बजाय टाई बांध रहे हैं.

कॉमनवेल्थ दिल्ली संभ्रांत वर्ग के लिए शहर की राजधानी है. इसे उनकी सहूलियत और सुविधा के हिसाब से बनाया गया है. नए बन रहे इस शहर में साइकिल वालों के लिए एक भी लेन नहीं बनाई जा रही है. इसकी वजह बिल्कुल साफ़ है. क्योंकि अभी भी दिल्ली में इसका बाज़ार नहीं है. (जबकि लंदन में मेयर और भविष्य के प्रधानमंत्री साइकिल का ही इस्तेमाल करते हैं.) आप कभी यह स्वीकार ही नहीं करते कि आपके यहां ग़रीबी है. इस तरह आप ग़रीबी को दूर करने का उपाय तलाशते हैं. यदि आपको झुग्गी-झोपड़ी नज़र नहीं आती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इनका अस्तित्व ही नहीं है. अभी राष्ट्रमंडल खेलों का बहाना बनाकर बुनियादी संरचनाओं पर ख़र्च किया जा रहा है, पर असलियत में देखें तो यह विलासिता के लिए किया जाने वाला ख़र्च है. यह सारी चीज़ें एक वर्ग विशेष की आवश्यकताओं के लिए किया जाने वाला ख़र्च है. जब तक रामराज्य नहीं आ जाता, तब तक भारत को किसी भी अंतरराष्ट्रीय समारोहों का आयोजन नहीं करना चाहिए. ऐसी बातें कोई ईर्ष्यालु होने के नाते नहीं कहता या यह उसकी अपनी मूल सोच नहीं होती है. कमी और असमानता का माहौल तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन इसी कमी को आप उपलब्ध अवसरों से पूरा करते हैं. और, इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारा सामाजिक दायित्व समानतावादी है अथवा कुलीनवादी. पूंजीवादी लंदन ने 2012 के ओलंपिक खेलों के आयोजन के अवसर को ग़रीब क्षेत्रों के विकास के लिए इस्तेमाल किया है. जबकि दिल्ली ने ठीक इसके उलट काम किया. यह उन्हीं जगहों का विकास कर रही है, जो पहले से विकसित है. और, दिल्ली ने उन क्षेत्रों की लगातार अनदेखी की है, जो सुविधाओं से वंचित हैं.

क्या आने वाले दशकों में दिल्ली ही विकास का मॉडल है? यहां समाज का एक नया वर्ग रहता है. इसकी संख्या काफ़ी अधिक है और दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. यह वर्ग महत्वाकांक्षी लोगों का है. यह वर्ग संपन्न लोगों की सफलता का समर्थन करता है. इसकी वजह यह है कि ये कहते हैं तो उसी जमात में शामिल होना चाहते हैं. यह भारत का एक उभरता हुआ वर्ग है, जिसमें संभवतः अधिक से अधिक 30 करोड़ लोग रहते हैं. और, ये कुलीनों से अपना भविष्य आउटसोर्स करने के लिए लालायित हैं, क्योंकि इन्होंने सफलता का स्वाद चख लिया है. ये सभी उसी कुलीन वर्ग में शामिल होना चाहते हैं. इस वर्ग में एक आम चुनाव को एक पार्टी या दूसरे के पक्ष में करने की क्षमता है. लेकिन शासन को बरकरार रखने के लिए यह उतना योग्य नहीं है.

यह 800 मिलियन निर्धन लोगों को गुडविल के भरोसे छोड़ देता है. लोकतंत्र का मतलब उदारता नहीं है. सवाल अधिकार का है. लोकतंत्र का मतलब दूसरों को आश्रय देने से भी नहीं है, बल्कि समानता से है. लोकतंत्र का तात्पर्य है कि वह सभी को साथ लेकर चले, न कि किसी वर्ग विशेष को. लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक विचारधारा में समान साझीदारी से है, न कि यह सिर्फ़ बैलेट बॉक्स तक सीमित है. मॉल चिकने हाईवे से जुड़े हुए हैं और उनके आसपास मोबाइल टावर हैं. परिवहन की यह दुनिया गांवों की पहुंच से परे है. ये दोनों बातें दुःख और निराशा देती हैं. ग्रामीण भारत केजीवन हाईवे का टैक्स नहीं दे सकते तो उन्हें बड़े शहरों में सपने नहीं देखने चाहिए. जबकि नए ब्राह्मण 100 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से यात्रा करते हैं. ऐसे में वे भी निरंतर कठिन परिश्रम की चक्की में पिसते रहना नहीं चाहते हैं. ये छोटे शहरों में अपनी ज़िंदगी एक मज़दूर के रूप में ख़त्म नहीं करना चाहते हैं. ये नई दिल्ली में नौकरी चाहते हैं. ग़रीब मूर्ख नहीं हैं. वे जानते हैं कि ये मैनेजर नहीं बन सकते. लेकिन, यदि यह मुल्क उनके हुनर के लिए लाभदायक रास्ता नहीं निकाल सकता तो उनके क्रोध से सामाजिक तानाबाना ही कमज़ोर होगा. यदि शीर्ष पर बैठे लोग उनके लिए कोई जगह नहीं खोज सकते हैं तो कई दूसरे रास्ते भी हैं. कुछ रास्ते बंदूक़ों के साथ शुरू होते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

महिलाओं को समान दर्जा समाज की हक़ीक़त नहीं

रवि किशोर

आज हर कोई भारतीय समाज में महिलाओं को समानता की बात करता है, लेकिन जो बातें की जा रही हैं या जिस बात की वकालत की जा रही है, हक़ीक़त उससे काफ़ी अलग है. पुरुष प्रधान भारतीय समाज में सामाजिक–आर्थिक प्रतिबंधों के चलते महिलाएं हाशिए पर हैं. भारतीय संदर्भ में लैंगिक समानता की बात केवल काग़ज़ों पर दिखाई देती है. भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण की बातें करने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती और हतोत्साहित करने वाली बात यह है कि महिलाओं की क़ानूनी स्थिति व समाज में उनकी वास्तविक स्थिति के बीच की गहरी खाई को पाटा कैसे जाए. यह खाई सिर्फ़ समाज के अंदर ही देखने को नहीं मिलती है. सरकार और न्यायपालिका में भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिलती है. यह सही है कि देश के शीर्ष पद पर आज एक महिला विराजमान है और लोकसभा अध्यक्ष पद की ज़िम्मेदारी भी एक महिला के ही ज़िम्मे है. यहां तक कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन एवं देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की कमान भी एक महिला के ही हाथ में है. लेकिन, इन बातों से आम महिलाओं की स्थिति सुधारने में कोई मदद नहीं मिल पा रही है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, लेकिन यह आज भी न्यूनतम है. सर्वोच्च न्यायालय का ही उदाहरण लें, पिछले कई वर्षों से वहां कोई महिला न्यायाधीश नहीं रही है. आज भी न्यायाधीश के पद पर सिर्फ़ दो महिला न्यायमूर्ति विराजमान हैं. यहां तक कि उच्च न्यायालयों में भी महिला न्यायाधीशों की संख्या नगण्य है. हालांकि सभी लोग समान प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, लेकिन हक़ीक़त में इसका कोई प्रभाव नज़र नहीं आता है. फ़ैसला लेने के लिहाज़ से महत्वपूर्ण स्थानों में, जिनमें न्यायपालिका भी शामिल है, महिलाओं की भागीदारी किसी नखलिस्तान की तरह है, जिसमें कोई विस्तार नहीं हो रहा.

दहेज निरोधक क़ानून 1961 से प्रभावी है और इसमें बाद में कड़े संशोधन भी हुए, फिर भी हालात बुरे हैं. दहेज के कारण होने वाली हत्या के मामलों को देखें तो स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा. गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारित करने वाली जांच पर क़ानूनी रोक है, फिर यह निर्बाध रूप से जारी है और मादा भ्रूण की हत्या बेरोकटोक की जा रही है. भ्रूण की ग़ैरक़ानूनी लैंगिक जांच शहर और गांव दोनों ही जगहों पर की जा रही है. भ्रूण के मादा होने का पता चलने पर गर्भपात कराने का चलन जोर पकड़ता जा रहा है. दहेज प्रतिषेध क़ानून के साथ ही घरेलू हिंसा निरोध क़ानून भी प्रभावी है, लेकिन महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की घटनाओं पर इसका शायद ही कोई असर देखने को मिलता है. घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में पुलिस में रिपोर्ट कम ही दर्ज़ कराई जाती है. महिलाओं की पुरुषों पर सामाजिक–आर्थिक निर्भरता इसकी एक बहुत बड़ी वजह है. सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के कोई उपाय न होने से हर सितम सहकर भी पति के घर में रहना उनकी विवशता होती है. ज़्यादातर मामलों में महिलाओं की पति पर निर्भरता देखने को मिलती है. पति का साथ छूट जाने की स्थिति में उनके पास जीवनयापन का कोई विकल्प नहीं होता. जीवनयापन के लिए पति से पैसा पाने की क़ानूनी लड़ाई में काफ़ी वक़्त बर्बाद हो जाता है.

पूरा का पूरा मामला हमारे सामाजिक ताने–बाने से जुड़ा है. समाज में महिलाओं का दर्ज़ा आज भी पुरुषों के बाद और निम्नतर माना जाता है. समाज की तथाकथित हाई सोसाइटी में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है. हाल के दिनों में एक बड़ा परिवर्तन यह देखने को मिला है कि सामाजिक समारोहों में महिलाएं अब पुरुषों के साथ गलबहियां करते हुए ज़्यादा नज़र आने लगी हैं. विवाह समारोह आदि में धनबल का फूहड़ प्रदर्शन ग़ौर करने वाली बात है. हालांकि दहेज प्रतिषेध क़ानून और भारतीय दंड संहिता में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. मसलन 1980 में एक बड़ा बदलाव यह हुआ कि दहेज लेना और देना दोनों को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया, लेकिन इससे दहेज लेने और देने की कुरीति पर कोई असर नहीं हुआ. वास्तविकता यह है कि पिछले कुछ दशकों में दहेज की कुरीति सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों में घर कर चुकी है. दहेज के मामले केवल तभी दर्ज़ कराए जाते हैं, जब विवाह के बाद तनाव हद की सीमा को लांघ गया हो या इसके अलावा दूसरा कोई उपाय न बचा हो.

बलात्कार के मामले को ही लें. बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के बावजूद इसके ज़्यादातर मामले दर्ज़ नहीं कराए जाते, क्योंकि मामला दर्ज़ कराने से लेकर तहक़ीक़ात की पूरी प्रक्रिया महिलाओं की गरिमा को काफ़ी कलंकित करने वाली है. जांच के स्तर पर भी महिलाओं को उत्पीड़ित होना पड़ता है. न्यायिक प्रक्रिया भी महिलाओं के पक्ष में मददगार नज़र नहीं आती है. बावजूद इसके उच्चतर न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है, ने इसके लिए स्पष्ट दिशा– निर्देश जारी कर रखे हैं. विसाका मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी होने के बाद यौन उत्पीड़न के मामलों में कुछ सकारात्मक प्रगति देखने को मिली. लेकिन, इतने सालों के बाद सरकार इस मसले पर कोई क़ानून बना पाने में नाकाम रही है और सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला आज भी दिशा–निर्देश का काम कर रहा है. जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर यह कह रखा है कि सरकार इस मसले पर एक कारगर विधेयक लाएगी, लेकिन सरकार इसमें नाकाम रही. ये तो बस कुछ दृष्टांत भर हैं. क़ानून को लागू करने वाली एजेंसियों के साथ यह प्रतिबद्धता नहीं दिखाई देती है. हाल ही में चर्चित रहा रुचिका–राठौड़ मामला तो बस एक उदाहरण है, जिसमें क़ानून का पालन कराने वाले तंत्र की कमियां उजागर हुईं. इस मामले ने एक बार फिर से यह साबित किया कि महिलाएं हमेशा उत्पीड़न ही झेलती हैं और आरोपी बेख़ौफ़ होकर घूमता रहता है. केवल इतना ही नहीं, रुचिका मामले में एक बेकसूर–मासूम लड़की को आत्महत्या के लिए बाध्य होना पड़ा और आरोपी क़ानून का पालन कराने वाली सबसे सक्षम एजेंसी पुलिस महकमे का आला अधिकारी बना दिया गया. और तो और, उसे राष्ट्रपति पदक तक से नवाजा गया. यह बेहद दुखद और शर्मनाक़ बात थी.

आख़िर ऐसी स्थिति क्यों है? हम सभी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं. न्याय दिलाने और क़ानून का पालन कराने वाली यानी दोनों ही एजेंसियां इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं. समाज के क़ायदे–क़ानून और सामाजिक व्यवहार के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है. क़ानून तो लागू कर दिया गया है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है. विधायिका केवल काग़ज़ पर क़ानून लागू करने के बारे में चिंता करती है. वह इस बात की फ़िक्र ज़रा भी नहीं करती कि क़ानून का पालन उसकी मूल भावना को ध्यान में रखते हुए सही तरीक़े से किया गया या नहीं. वह इसके पालन में ढिलाई बरतने का सारा दोष क़ानून लागू करने वाली एजेंसी के मत्थे मढ़कर अपना पल्ला झाड़ लेती है. राजनेताओं को तो बस अपने वोटबैंक की फ़िक्र रहती है.

जहां तक विधायी सवाल हैं तो पंचायत एवं ज़िला परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में सही क़दम उठाए गए हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल का भविष्य राजनीतिक कारणों से अभी भी अधर में लटका हुआ है. कई राजनेता पहले से जारी आरक्षण व्यवस्था में ही महिलाओं को आरक्षण की सुविधा देना चाहते हैं. संविधान महिला और पुरुष दोनों के समान अधिकारों की बात करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा शायद ही देखने को मिलता है. हम बड़ी बेसब्री से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जल्द ही पारित होगा.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

लाजवाब चौथी दुनिया

अब तक हम कई समाचारपत्रों–पत्रिकाओं से रूबरू हो चुके हैं, लेकिन चौथी दुनिया पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि असल में खबर क्या होती है. आज तक जो भी समाचार इसमें पढ़ने को मिले, वे प्रशंसा के योग्य रहे. दक्षिण भारत के पाठकों के लिए यह एक नई दुनिया में ले जाने वाला अखबार है.

एच एस शर्मा एवं रोशन शर्मा, *बंगलुरु, कर्नाटक.*

सुधार की ज़रूरत

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. पिछले चालीस सालों से विभिन्न पत्र–पत्रिकाएं पढ़ता आ रहा हूं. लेकिन चौथी दुनिया में अलग तरह के लेख और समाचार होते हैं. अपेक्षा यह है कि किसी विषय पर बार–बार लेख न छापे जाएं. महापुरुषों की जीवनी पर आधारित लेख, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं पर्यटन से संबंधित सामग्री प्रकाशित हो तो यह अखबार और भी रुचिकर बन सकता है.

सूर्य नारायण राउत, *कटहलबाड़ी, दरभंगा, बिहार.*

सिर्फ बयानबाज़ी हल नहीं

अगर भारतीय छात्रों के साथ आस्ट्रेलिया में हुई पिछली कुछ हिंसात्मक वारदातों को छोड़ दें तो ऐसी कोई घटना याद नहीं आती, जबकि दो देशों के बीच इस तरह का तनाव देखा गया हो. लेकिन, अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है तो जरूरत इस बात की है कि कोई ठोस कदम उठाया जाए. सिर्फ बयानबाजी से काम चलने वाला नहीं है.

रवि बजाज, *मनेर, पटना, बिहार.*

नई पुलिसिया छवि

आईआईएम में पुलिस वाला लेख काफी प्रेरणादायक लगा. इसमें एक पुलिस वाले के अनुभव थे. पुलिस की जिस छवि से हम वाकिफ हैं, दरअसल हर शख्स वैसा नहीं है. कई पुलिस वाले उस छवि के उलट भी हैं. लेख में आत्मकथात्मक चित्रण ज्यादा था, पर शिक्षा और खासकर प्रबंधन शिक्षा के कई पहलुओं से रूबरू होने का मौका मिला.

असगर अली, *सतना, मध्य प्रदेश.*

सबसे अलग अख़बार

देश एवं समाज पर पैनी नज़र रखने और आमजन के हितों की रक्षा में समाचारपत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ऐसा मुझे चौथी दुनिया पढ़कर लगा, क्योंकि यह अख़बार सबसे अलग लगता है.

राजीव विश्वकर्मा, *नौबस्ता, कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

बुजुर्गों पर आपका ध्यान

चौथी दुनिया एक उत्कृष्ट साप्ताहिक है जिसके स्तंभ वाकई उम्दा होते हैं. 8–14 फरवरी का अंक पढ़ा. इसमें डी आर आहूजा का स्तंभ बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की जरूरत पढ़ा. वाकई यह एक बड़ा मुद्दा है जिसेक पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है. आज की पीढ़ी बुजुर्गों को बोझ समझने लगी है. जबकि सच यह है कि वृद्धों अनुभवों का खज़ाना तथा नई पीढ़ी के मार्गदर्शक होते हैं. सरकार को मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड डिपेंडेंस एक्ट, जिसे 2007 में तैयार किया गया था, तुरंत लागू करने की जरूरत है. परंतु इसमें भी कुछ खामियां हैं. जिन्हें दूर करने के बाद ही इस कानून का मकसद सार्थक हो सकेगा. आपसे अनुरोध है कि राजनीतिक लेखों के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े लेख इसी तरह प्रकाशित करते रहें. युवाओं, खासकर बेरोजगार युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर लेख अवश्य प्रकाशित करें ताकि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके. अलग अलग क्षेत्रों में सफल युवाओं के प्रेरणादायक अनुभवों को भी चौथी दुनिया में जगह दें. अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश से जुड़ी जानकारियों का इंतजार रहेगा.

अरुण सरोहा, *दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली*

कार्टून दुनिया और धीर जी

हमें धीर जी के कार्टून बहुत अच्छे लगते हैं. वह गंभीर विषयों पर भी अपनी सार्थक टिप्पणी आस–ानी से करते हैं. साहित्य दुनिया पृष्ठ पर मुन्नी मोबाइल सीरीज़ और कुंभ पर आधारित आलेख प्रशंसनीय हैं.

रागिनी सहरावत, *जनकपुरी, नई दिल्ली.*

वाजिब क़ीमत

चौथी दुनिया मैंने पहली बार देखा. बहुत अच्छा लगा. पहली बार राजनीतिक एवं सामाजिक सरोकारों वाला अख़बार पढ़ा. यह निश्चित ही आने वाले समय में प्रगति करेगा. कीमत भी सबकी पहुंच के अंदर है.

रूपक चौधरी, *वैशाली, बिहार.*

बेहतरीन प्रस्तुति

चौथी दुनिया का 18–24 जनवरी का अंक बहुत अच्छा लगा. नरेगा, दिल्ली–बिहार के बाबुओं और जसवंत सिंह पर लेख पढ़ने को मिले. हर तीसरा आदमी दरिद्र वाली स्टोरी ने समाज की स्थिति से अवगत कराया. ख़बरों की दृष्टि से अख़बार की प्रस्तुति बेहतरीन है.

अशोक जैन, *कोटरी, सीहोर, मध्य प्रदेश.*

बेहतरीन प्रस्तुति लगी

चौथी दुनिया के 25 जनवरी के अंक में नरेगा के सामने नई चुनौतियों के रूप में जिन पांच समस्याओं की चर्चा की गई है, वास्तव में नरेगा का यही चरित्र है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ही नहीं, बल्कि बिहार सहित पूरे भारत में नरेगा का यही हाल है. पूरे देश में नरेगा योजनाओं में धांधली जारी है. यह ख़बर पूर्ण जानकारी वाली लगी. इसी तरह के मुद्दों को छापते रहें और पूर्ण जानकारी दें. कुल मिलाकर अख़बार की प्रस्तुति बेहतरीन लगी.

शंकर शर्मा, *बेगूसराय, बिहार*

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

एक थे जॉर्ज फर्नांडिस!

एक थे जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को भारत में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में मधुलिमए के साथ मिलकर शानदार शक्ल दी. समाजवादी आंदोलन ने भारतीय राजनीति में नेतृत्व करने वाले ऐसे व्यक्तियों को पैदा किया, जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में आम आदमी और उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए काफ़ी संघर्ष किए. जॉर्ज फर्नांडिस हमारे बीच हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी आज ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जो कितनी है कितनी नहीं, पता ही नहीं. एक जानदार ज़िंदादिल आदमी, जिसके जीवन में संघर्षों की लंबी फ़ेहरिस्त है, आज बेजान खिलौना सा बन गया है.

जॉर्ज फर्नांडिस को डॉक्टर लोहिया जॉर्ज कहकर बुलाते थे और यही उनका संक्षिप्त नाम मशहूर हो गया. जॉर्ज ने बीस साल की उम्र के बाद अपने को आम आदमी, मज़दूर और ग़रीब के दु:ख से जोड़ लिया. उस समय की बंबई की बेस्ट की लड़ाई और उसमें जॉर्ज के नेतृत्व में जीत ने जॉर्ज को मज़दूरों का हीरो बना दिया. समाजवादी आंदोलन टुकड़ों में भले बंटा, पर जॉर्ज का संघर्ष नहीं बंटा. जहां मज़दूर वहां जार्ज. बिहार आंदोलन आया और जॉर्ज उसमें कूद पड़े. भारत में पहली बार तीन दिनों की मुक़म्मल रेल हड़ताल उन्हीं दिनों हुई, जॉर्ज के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने रेल पटरी तीन दिनों के लिए सूनी कर दी. पचहत्तर में आपातकाल लगा, जॉर्ज भूमिगत हो गए. अंडरग्राउंड होकर आपातकाल विरोधी आंदोलन संगठित किया. मशहूर बड़ौदा डायनामाइट कांड हुआ, जॉर्ज पकड़े गए. जेल में रहते लोकसभा का चुनाव जीते और सतहत्तर में केंद्रीय मंत्री बने. कोकाकोला को भारत से जाने पर विवश किया, ताकि भारतीय पेय को बाज़ार मिल सके. कई बार केंद्रीय मंत्री बने. परिस्थितियों ने उन्हें अटल जी के साथ जोड़ा. केंद्रीय सरकार के वह संकटमोचक बन गए.

जॉर्ज ने इंसानों को भी गढ़ा, उनके विकास में सहयोग किया. शायद ही कोई नाशुक्रा हो, जो कहे कि उसे जॉर्ज का सहयोग नहीं मिला. आज कांग्रेस, जद, समाजवादी पार्टी सहित हर दल में महत्वपूर्ण व्यक्ति नेतृत्व में हैं और उन्हें हमेशा परेशानी में जॉर्ज की मदद मिली है. अफ़सोस इस बात का है कि आज जब जॉर्ज को मदद की ज़रूरत है तो सभी ख़ामोश हैं.

जॉर्ज अल्ज़ाइमर नाम की बीमारी की गिरफ़्त में हैं और छठी स्टेज में हैं. इस बीमारी का शिकार व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है और धीरे–धीरे खाना निगलना भी भूल जाता है. डॉक्टर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को उसी जगह रखना चाहिए, जहां से वह परिचित हो. उसके आसपास वे व्यक्ति रहें, जिन्हें वह देखता रहा हो. उसका बिस्तर तक वैसा ही रखना चाहिए, जैसा वह रखता था. उसे उन सबसे मिलाना चाहिए, जिनसे वह मिलता रहा है. लेकिन आज जॉर्ज के साथ हो क्या रहा है?

इससे पहले कि आगे की बात कहें, आपको बता दें कि जॉर्ज का व्यक्तिगत जीवन काफ़ी दु:खपूर्ण रहा है. उन्होंने मशहूर कांग्रेसी नेता हुमायूं कबीर की बेटी लैला कबीर से शादी की, लेकिन लैला कबीर कभी लैला जॉर्ज फर्नांडिस नहीं बन पाईं. उनका इगो, उनकी अकड़, उनका जॉर्ज की ज़िंदगी पर छींटाकशी जॉर्ज को कभी उनमें अपना कॉमरेड या साथी या सहचरी जैसा भाव नहीं जगा पाया. एक बेटा होने के बाद भी दोनों अलग हो गए. पच्चीस साल लैला कबीर जॉर्ज से अलग विदेश में रहीं और कभी उन्होंने जॉर्ज की ज़िंदगी में नहीं झांका.

जॉर्ज का परिवार उनके साथी बन गए. जॉर्ज के साथियों में पुरुष और महिलाएं दोनों रहीं, जॉर्ज ने सभी के साथ सम्मानजनक रिश्ता रखा. व्यक्तिगत जीवन में जॉर्ज इतने सादे रहे कि उनका घर हमेशा उनके संघर्ष और उनकी पार्टी का केंद्र रहा. पच्चीस सालों तक जॉर्ज की ज़िंदगी सार्वजनिक रही. सैकड़ों उनके प्रशंसक और दोस्त रहे, जो उनसे हमेशा मिलते रहते थे. ऐसा नहीं कि जॉर्ज को धोखे नहीं मिले, राजनीति में भी मिले और पार्टी में भी मिले. कुछ तो ऐसे थे, जिन्हें जॉर्ज ने बनाने में सबसे लड़ाई लड़ी, पर बनने के बाद उन्होंने जॉर्ज को ही किनारे करने की कोशिश की.

जॉर्ज की पिछले लोकसभा चुनाव में हार के बाद बुरी हालत हो गई थी. उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था. मुंबई की यूनियन के साथियों ने उनके लिए हौजखास में एक मकान ख़रीदा था, पर मकान का टाइटिल यूनियन के नाम था. उस यूनियन ने जॉर्ज को मकान में न आने देने की कोशिश की. जॉर्ज के दोस्त उनके लिए किराए का मकान तलाश रहे थे. तभी नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार से राज्यसभा के लिए भेज दिया. यह नीतीश का जॉर्ज के प्रति आदर था, क्योंकि तीन महीने पहले ही जॉर्ज नीतीश और शरद यादव से अलग होकर लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हारे थे.

जॉर्ज की बीमारी बढ़ रही थी, वह छठी स्टेज में आ गई. इसकी केवल सात स्टेज होती हैं. नितिन गडकरी आख़िरी बड़े नेता थे, जो जॉर्ज से भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद मिलने आए थे. जॉर्ज अपने लॉन में उनके साथ टहले और मराठी में उनसे बातचीत भी की. इस दौर में जया जेटली जॉर्ज के साथ लगातार रहीं और उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह करती रहीं. जॉर्ज अपनी छोटी–बड़ी हर आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर थे. जॉर्ज का इलाज एम्स के दो डॉक्टर पिछले दस सालों से कर रहे थे. पिछले पंद्रह सालों से जॉर्ज टूथ पिक से लेकर हवाई जहाज के टिकट तक के लिए अपने इन्हीं साथियों पर निर्भर थे. अचानक ख़बर आई कि बंगलौर में जॉर्ज की मां के नाम ज़मीन का एक टुकड़ा है, जो इसलिए ख़रीदा गया था कि बुढ़ापे में जॉर्ज वहां रहकर समाज सेवा केंद्र चलाएंगे. जॉर्ज के भाइयों ने उस पर से अपना हक़ वापस ले लिया और वह ज़मीन जॉर्ज को मिल गई. उस ज़मीन को बेचने से सोलह करोड़ रुपये मिले, जिसमें टैक्स काटने के बाद तेरह करोड़ उनके खाते में आ गए.

अब जॉर्ज करोड़पति हो गए, लेकिन उनकी याददाश्त उनका साथ छोड़ रही थी. अचानक लैला कबीर, लैला फर्नांडिस बनकर भारत आ गईं, उनके साथ उनका बेटा भी था. जॉर्ज उन्हें देखकर बिफ़र गए. जॉर्ज ने कभी लैला को पसंद नहीं किया, उनके हज़ारों साथी इस बात को जानते हैं, देश का हर नेता इसे जानता है. जॉर्ज की स्थिति बिल्कुल बच्चे जैसी हो गई है
लैला कबीर के भाई अलतमश कबीर सुप्रीम कोर्ट
किसी का भाई– भतीजा बड़े पद पर हो तो वहां
है. लैला कबीर जॉर्ज को लेकर बाबा रामदेव के
दिन रहे. बाबा रामदेव ने दावा किया कि उन्होंने
दिया है. अब जॉर्ज को लैला कबीर दिल्ली वापस
में रखा है.

यहां जॉर्ज के लिए सब अजनबी हैं. उनके सा
नहीं हैं, बिस्तर नहीं है, किताबें नहीं हैं, उनके पा
यहां हैं तो लैला, जिन्हें जॉर्ज ने कभी पसंद नहीं
कर दिए गए हैं, जिन्होंने दसियों साल से उनका
उनका इलाज कर रहा है पता नहीं. उनसे अब को
या हंसते हैं, पता नहीं. उनके राजनीतिक कार्यकर
रहे कि क्या करें.

क्या यह डॉक्टरों की राय के ख़िलाफ़ जॉर्ज
यह जॉर्ज के मानवाधिकारों का हनन नहीं है? क्या
से अलग रही पत्नी का बदला तो नहीं है? क्या ज
तो नहीं मिल रही है? आख़िर क्यों जॉर्ज से उनके
नहीं दिया जा रहा है?

जॉर्ज के कुछ साथी इस स्थिति के ख़िलाफ़ अ
वे पशोपेश में हैं कि कहीं इससे बयानबाजी न
राजनीति में रहने वाला, सर्वोच्च नेतृत्व का हिस्सा
हो गया है कि उसके साथी जो आज राजनीति में ब
दें? जॉर्ज ने अपना एक चुना परिवार बनाया, जिस
पर आज वह परिवार रो रहा है. जॉर्ज फर्नांडिस
पहले कहीं देखी–सुनी नहीं गई. मुलायम सिंह याद
बृजभूषण तिवारी, मोहन सिंह सहित सारे समाजवाद
रखने वाले लोग आज ख़ामोश क्यों हैं? सरकार ख़
इसका संज्ञान नहीं ले रही? ईश्वर, अल्लाह और
कि किसी दुश्मन को भी जॉर्ज जैसी स्थिति न
मेडिकल बोर्ड करे और उन्हें उनके साथियों से मिल
ऐसा होगा. वह राज्यसभा सदस्य भी हैं. क्या राज्य

अगर कुछ नहीं हो पाता तो अफ़सोस रहेगा.
उनके रहते लिखना पड़ रहा है कि एक थे जार्ज फ

अल्लाह शब्द पर किसी का एकाधिकार

अनवर इब्राहीम

मलेशिया एक बार फिर से ग़लत कारण से अंतरराष्ट्रीय ख़बर की सुर्ख़ियों में है. पिछले दो सप्ताह के दौरान असामाजिक तत्वों ने पूजा के दस स्थलों को अपना निशाना बनाया है. इन स्थलों में ईसाइयों के गिरिजाघर और सिखों के गुरुद्वारे शामिल हैं. बहरहाल इस हमले में वहां कोई हताहत नहीं हुआ और संपत्तियों को जो नुक़सान पहुंचा उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है. लेकिन यह बात भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्षति के लिए नहीं कही जा सकती है. सरकारी अधिकारियों की ओर से कई विरोधाभासी बयानों के बाद हिंसा के वास्तविक कारणों का खुलासा अब भी नहीं हो पाया है. मलेशिया की छवि एक शांत राष्ट्र की रही है जहां जातीय और धार्मिक विविधता रही है. इन हमलों के बाद मलेशिया की यह छवि दांव पर है. सांप्रदायिक और धार्मिक मसलों से निपटने के मामले में मलेशिया का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है. मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों के साथ जो बुरा व्यवहार होता है, वह प्राय: उससे भी ख़राब होता है जिसका आरोप पश्चिमी देशों पर मुस्लिम समुदाय के लोग लगाते रहे हैं. मैंने मुस्लिम देशों में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता पर ध्यान देने की मांग की है जो हमारे न्याय, निष्पक्षता और विविधता की मांग में संतुलन और विश्वसनीयता को प्रदर्शित करे. ये ऐसे मूल्य हैं जो इस्लामिक परंपराओं से जुड़ी हैं. 12वीं शताब्दी के विधिवेत्ता अल–शातिबी ने भी इन मूल्यों को शरीया के ऊंचे उद्देश्यों के रूप में समझाया है. हम लोगों ने देखा है कि अपेक्षाकृत उदारवादी और प्रगतिशील माने जाने वाले पश्चिमी देशों में जब कोई पक्षपातपूर्ण क़ानून पास होता है तो इसका विरोध पूरी दुनिया के मुसलमान करते हैं. अभी जैसा कि जर्मनी में बुर्क़ा या स्वीटजरलैंड में मीनारों को लेकर हुआ. लेकिन मलेशिया लगातार अपने यहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने में असफल रहा है. हाल की आगजनी की घटनाएं और हमले इस बात का संकेत है कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मलेशिया के रुख़ में गड़बड़ी कहां है. हमले की इस घटना को उस विवाद के चलते बढ़ावा मिला जिसमें मलेशिया के ईसाई समुदाय के लोगों ने अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया था. मलेशिया में इस समुदाय की जनसंख्या लगभग 20 लाख यानी 10 फ़ीसदी है. 2007 में गृह मंत्रालय ने एक कैथोलिक न्यूजपेपर, हेराल्ड पर अल्लाह शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था. बाद में, मलय भाषा में अनुदित, बाइबल की 15 हज़ार कॉपियां ज़ब्त कर ली गई थीं, जिसमें गॉड शब्द का अनुवाद अल्लाह किया गया था.

31 दिसंबर, 2009 को क्वालालंपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश से उक्त प्रतिबंध को नामंज़ूर कर दिया गया. इस प्रतिबंध को नामंज़ूर करने के पीछे न्यायालय का तर्क यह था कि मलेशिया का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है. तभी से मलेशिया की स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और इस तनाव को बढ़ाने के पीछे बहुत हद तक कुछ ग़ैर–ज़िम्मेवार नेताओं, मुख्यधारा की मीडिया और कुछ मुट्ठी भर ग़ैर सरकारी संगठनों

(सत्ताधारी दल से जुड़े) का भी हाथ रहा हैं. उदाहरण के तौर पर, देश के सबसे बड़े दैनिक अख़बार, उटुसन मलेशिया (यूएमएनओ से संबद्ध) ने मुस्लिम जनभावनाओं को भड़काने का काम किया है. अख़बार ने ग़ैर–मुस्लिमों को इस बात के लिए ज़िम्मेदार बताया है कि इन्होंने अल्लाह शब्द का अनादर किया है और ये लोग धर्म परिवर्तन के ज़रिए इस मुस्लिम बहुल देश में अपनी जनसंख्या बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं. मैंने पहले भी इस तरह के आक्रमक दुष्प्रचार का इस्तेमाल होते देखा है, जब नेताओं ने लोगों को भयभीत कर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की. इस तरह के हथकंडे शर्मनाक घटनाओं, जैसे न्यायालय के विवादित निर्णय या सैन्य ख़रीदारी में अनियमितता या रॉयल मलेशियन एयर फोर्स से दो जेट इंजन की चोरी, से ध्यान हटाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं. यह स्थिति तब से और ख़राब हुई है जब से सत्ताधारी दल ने गत वर्ष संसद में अपना दो तिहाई बहुमत खोया है. यूएमएनओ अब हताश है और जन समर्थन पाने के लिए संघर्ष कर रही है.

दुनिया के कुछ मुसलमान इस तरह के दावे कर सकते हैं कि अल्लाह शब्द पर उनका एकाधिकार है. यह स्वीकारा जा चुका है कि अल्लाह शब्द इस्लाम पूर्व अरब जगत में इस्तेमाल में था. अरब जगत के और प्रचलित भाषाओं में भी ईश्वर या गॉड के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता था.

दुनिया के कुछ मुसलमान इस तरह के दावे कर सकते हैं कि अल्लाह शब्द पर उनका एकाधिकार है. यह स्वीकारा जा चुका है कि अल्लाह शब्द इस्लाम पूर्व अरब जगत में इस्तेमाल में था. अरब जगत के और प्रचलित भाषाओं में भी भगवान के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता था. अरामैक में इसे इलाहा और हिब्रू में इलोहिम के नाम से जानते थे. ऐतिहासिक पांडुलिपियों से भी यह साबित हुआ है कि अरब भाषा बोलने वाले मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सामूहिक रूप से ईश्वर की प्रार्थना करते थे और ब्रह्मांड के रचयिता और पालक भगवान के लिए 1400 साल तक अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करते रहे. दक्षिण–पूर्व एशिया में इस्लाम का इतिहास अपने विविध और विस्तृत परंपरा और मुस्लिम तथा ग़ैर–मुस्लिमों के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्तों के लिए लो
मलेशिया से बाहर के मुस्लिम
बेतुका मान रहे हैं और यह न
इतना विरोध और क्यों उपद्रव
रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम
घटना के बाद, बड़ी मेहनत से ल
की है कि मुस्लिम, ईसाई और
(उनकी जड़ें अब्राहम या इब्राहि
हैं और इसलिए एक समान ई
स्थानीय समुदाय की संवेदनशी
से बातचीत और वचनबद्धता के
बजाए इसके कि लोगों के बी
जाएं. मुस्लिम समुदाय को इस
चाहिए कि वे ईसाई समुदाय स
चिंताओं से अवगत कराए. स्पेन
बेहतरीन उदाहरण हैं और मल
अनुसरण करना चाहिए. कॉमन
2007 में शुरू किया गया थ
मुस्लिम विद्वानों का ध्यान अप
मुसलमानों और ईसाइयों के ब
तथा समृद्धि से जीवन जीने का
भूमिका निभाई है. प्रधानमंत्री
समय से ही मलेशिया की अंत
रहा है. राष्ट्रीय एकता को बढ़ा
मुस्लिम युवाओं द्वारा महिला
कोड़े बरसाए जा रहे हैं, मंदिर
पर गाय की कटी सिर के साथ
करने वाले मुसलमानों या इस्ल
अपनी पुरानी आस्थाओं की ओ
व्यवहार होता है. आख़िर नजी
चाहते हैं? मलेशिया भ्रष्टाचा
जा रहा है. हमारा पर्यटन उद्योग
रहा है.

यह सब कुछ ऐसे मलेशिय
रखता है, जिनकी प्रतियोगिता
राजनीतिक ध्रुवीकरण वाले वर्त
कुछ लोगों के हितों की बलि
राजनीति पुरानी हो गई है और
लोग ऐसा कर रहे हैं वह सिर्फ स
कर रहे हैं. अधिसंख्यक मलेशिय
नकारती है. वे महसूस करते
– जैसे मंदी, शिक्षा का गिरत
घटनाएं– का सामना कर रहे
होगा. साथ ही साथ निष्पक्षत
सिद्धांत को भी धरातल पर उत

*(लेखक मलेशिया के पूर्व उप प्रध
के सदस्य हैं. फिलह*

जब तोप मुक़ाबिल हो

एक थे जॉर्ज फर्नांडिस!

संतोष भारतीय

एक थे जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को भारत में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में मधुलिमए के साथ मिलकर शानदार शक्ल दी. समाजवादी आंदोलन ने भारतीय राजनीति में नेतृत्व करने वाले ऐसे व्यक्तियों को पैदा किया, जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में आम आदमी और उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए काफ़ी संघर्ष किए. जॉर्ज फर्नांडिस हमारे बीच हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी आज ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जो कितनी है कितनी नहीं, पता ही नहीं. एक जानदार ज़िंदादिल आदमी, जिसके जीवन में संघर्षों की लंबी फ़ेहरिस्त है, आज बेजान खिलौना सा बन गया है.

जॉर्ज फर्नांडिस को डॉक्टर लोहिया जॉर्ज कहकर बुलाते थे और यही उनका संक्षिप्त नाम मशहूर हो गया. जॉर्ज ने बीस साल की उम्र के बाद अपने को आम आदमी, मज़दूर और ग़रीब के दुःख से जोड़ लिया. उस समय की बंबई की बेस्ट की लड़ाई और उसमें जॉर्ज के नेतृत्व में जीत ने जॉर्ज को मज़दूरों का हीरो बना दिया. समाजवादी आंदोलन टुकड़ों में भले बंटा, पर जॉर्ज का संघर्ष नहीं बंटा. जहां मज़दूर वहां जार्ज. बिहार आंदोलन आया और जॉर्ज उसमें कूद पड़े. भारत में पहली बार तीन दिनों की मुक़म्मल रेल हड़ताल उन्हीं दिनों हुई, जॉर्ज के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने रेल पटरी तीन दिनों के लिए सूनी कर दी. पचहत्तर में आपातकाल लगा, जॉर्ज भूमिगत हो गए. अंडरग्राउंड होकर आपातकाल विरोधी आंदोलन संगठित किया. मशहूर बड़ौदा डायनामाइट कांड हुआ, जॉर्ज पकड़े गए. जेल में रहते लोकसभा का चुनाव जीते और सतहत्तर में केंद्रीय मंत्री बने. कोकाकोला को भारत से जाने पर विवश किया, ताकि भारतीय पेय को बाज़ार मिल सके. कई बार केंद्रीय मंत्री बने. परिस्थितियों ने उन्हें अटल जी के साथ जोड़ा. केंद्रीय सरकार के वह संकटमोचक बन गए.

जॉर्ज ने इंसानों को भी गढ़ा, उनके विकास में सहयोग किया. शायद ही कोई नाशुक्रा हो, जो कहे कि उसे जॉर्ज का सहयोग नहीं मिला. आज कांग्रेस, जद, समाजवादी पार्टी सहित हर दल में महत्वपूर्ण व्यक्ति नेतृत्व में हैं और उन्हें हमेशा परेशानी में जॉर्ज की मदद मिली है. अफ़सोस इस बात का है कि आज जब जॉर्ज को मदद की ज़रूरत है तो सभी ख़ामोश हैं.

जॉर्ज अल्ज़ाइमर नाम की बीमारी की गिरफ़्त में हैं और छठी स्टेज में हैं. इस बीमारी का शिकार व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है और धीरे–धीरे खाना निगलना भी भूल जाता है. डॉक्टर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को उसी जगह रखना चाहिए, जहां से वह परिचित हो. उसके आसपास वे व्यक्ति रहें, जिन्हें वह देखता रहा हो. उसका बिस्तर तक वैसा ही रखना चाहिए, जैसा वह रखता था. उसे उन सबसे मिलाना चाहिए, जिनसे वह मिलता रहा है. लेकिन आज जॉर्ज के साथ हो क्या रहा है?

इससे पहले कि आगे की बात कहें, आपको बता दें कि जॉर्ज का व्यक्तिगत जीवन काफ़ी दुःखपूर्ण रहा है. उन्होंने मशहूर कांग्रेसी नेता हुमायूं कबीर की बेटी लैला कबीर से शादी की, लेकिन लैला कबीर कभी लैला जॉर्ज फर्नांडिस नहीं बन पाईं. उनका इगो, उनकी अकड़, उनका जॉर्ज की ज़िंदगी पर छींटाकशी जॉर्ज को कभी उनमें अपना कॉमरेड या साथी या सहचरी जैसा भाव नहीं जगा पाया. एक बेटा होने के बाद भी दोनों अलग हो गए. पच्चीस साल लैला कबीर जॉर्ज से अलग विदेश में रहीं और कभी उन्होंने जॉर्ज की ज़िंदगी में नहीं झांका.

जॉर्ज का परिवार उनके साथी बन गए. जॉर्ज के साथियों में पुरुष और महिलाएं दोनों रहीं, जॉर्ज ने सभी के साथ सम्मानजनक रिश्ता रखा. व्यक्तिगत जीवन में जॉर्ज इतने सादे रहे कि उनका घर हमेशा उनके संघर्ष और उनकी पार्टी का केंद्र रहा. पच्चीस सालों तक जॉर्ज की ज़िंदगी सार्वजनिक रही. सैकड़ों उनके प्रशंसक और दोस्त रहे, जो उनसे हमेशा मिलते रहते थे. ऐसा नहीं कि जॉर्ज को धोखे नहीं मिले, राजनीति में भी मिले और पार्टी में भी मिले. कुछ तो ऐसे थे, जिन्हें जॉर्ज ने बनाने में सबसे लड़ाई लड़ी, पर बनने के बाद उन्होंने जॉर्ज को ही किनारे करने की कोशिश की.

जॉर्ज की पिछले लोकसभा चुनाव में हार के बाद बुरी हालत हो गई थी. उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था. मुंबई की यूनियन के साथियों ने उनके लिए हौजखास में एक मकान ख़रीदा था, पर मकान का टाइटिल यूनियन के नाम था. उस यूनियन ने जॉर्ज को मकान में न आने देने की कोशिश की. जॉर्ज के दोस्त उनके लिए किराए का मकान तलाश रहे थे. तभी नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार से राज्यसभा के लिए भेज दिया. यह नीतीश का जॉर्ज के प्रति आदर था, क्योंकि तीन महीने पहले ही जॉर्ज नीतीश और शरद यादव से अलग होकर लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हारे थे.

जॉर्ज की बीमारी बढ़ रही थी, वह छठी स्टेज में आ गई. इसकी केवल सात स्टेज होती हैं. नितिन गडकरी आख़िरी बड़े नेता थे, जो जॉर्ज से भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद मिलने आए थे. जॉर्ज अपने लॉन में उनके साथ टहले और मराठी में उनसे बातचीत भी की. इस दौर में जया जेटली जॉर्ज के साथ लगातार रहीं और उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह करती रहीं. जॉर्ज अपनी छोटी–बड़ी हर आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर थे. जॉर्ज का इलाज एम्स के दो डॉक्टर पिछले दस सालों से कर रहे थे. पिछले पंद्रह सालों से जॉर्ज टूथ पिक से लेकर हवाई जहाज के टिकट तक के लिए अपने इन्हीं साथियों पर निर्भर थे. अचानक ख़बर आई कि बंगलौर में जॉर्ज की मां के नाम ज़मीन का एक टुकड़ा है, जो इसलिए ख़रीदा गया था कि बुढ़ापे में जॉर्ज वहां रहकर समाज सेवा केंद्र चलाएंगे. जॉर्ज के भाइयों ने उस पर से अपना हक़ वापस ले लिया और वह ज़मीन जॉर्ज को मिल गई. उस ज़मीन को बेचने से सोलह करोड़ रुपये मिले, जिसमें टैक्स काटने के बाद तेरह करोड़ उनके खाते में आ गए.

अब जॉर्ज करोड़पति हो गए, लेकिन उनकी याददाश्त उनका साथ छोड़ रही थी. अचानक लैला कबीर, लैला फर्नांडिस बनकर भारत आ गईं, उनके साथ उनका बेटा भी था. जॉर्ज उन्हें देखकर बिफ़र गए. जॉर्ज ने कभी लैला को पसंद नहीं किया, उनके हज़ारों साथी इस बात को जानते हैं, देश का हर नेता इसे जानता है. जॉर्ज की स्थिति बिल्कुल बच्चे जैसी हो गई है. जॉर्ज के घर में झगड़ा हुआ. लैला कबीर के भाई अल्तमश कबीर सुप्रीम कोर्ट में जज हैं. हमारे समाज में जब किसी का भाई– भतीजा बड़े पद पर हो तो वहां आतंक का वातावरण बन जाता है. लैला कबीर जॉर्ज को लेकर बाबा रामदेव के आश्रम पहुंच गईं. वहां जॉर्ज कुछ दिन रहे. बाबा रामदेव ने दावा किया कि उन्होंने जॉर्ज को बोलने के क़ाबिल बना दिया है. अब जॉर्ज को लैला कबीर दिल्ली वापस लाई हैं और उन्हें अपने मकान में रखा है.

यहां जॉर्ज के लिए सब अजनबी हैं. उनके साथ पच्चीस सालों से रह रहे लोग नहीं हैं, बिस्तर नहीं है, किताबें नहीं हैं, उनके पालतू पशु नहीं हैं, दीवारें नहीं हैं. यहां हैं तो लैला, जिन्हें जॉर्ज ने कभी पसंद नहीं किया. उनके डॉक्टर उनसे अलग कर दिए गए हैं, जिन्होंने दसियों साल से उनका इलाज किया है. कौन डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है पता नहीं. उनसे अब कोई मिल नहीं सकता. वह रोते हैं या हंसते हैं, पता नहीं. उनके राजनीतिक कार्यकर्ता असहाय हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें.

क्या यह डॉक्टरों की राय के ख़िलाफ़ जॉर्ज के साथ अत्याचार नहीं है? क्या यह जॉर्ज के मानवाधिकारों का हनन नहीं है? क्या यह जॉर्ज से नाराज़ पच्चीस सालों से अलग रही पत्नी का बदला तो नहीं है? क्या जॉर्ज को तलाक़ न लेने की सजा तो नहीं मिल रही है? आख़िर क्यों जॉर्ज से उनके राजनैतिक सहकर्मियों को मिलने नहीं दिया जा रहा है?

जॉर्ज के कुछ साथी इस स्थिति के ख़िलाफ़ अपील निकालना चाह रहे हैं, पर वे पशोपेश में हैं कि कहीं इससे बयानबाजी न शुरू हो जाए. क्या ज़िंदगी भर राजनीति में रहने वाला, सर्वोच्च नेतृत्व का हिस्सा बना रहा व्यक्ति इतना असहाय हो गया है कि उसके साथी जो आज राजनीति में बड़े पदों पर हैं, उसे अकेला छोड़ दें? जॉर्ज ने अपना एक चुना परिवार बनाया, जिसने उनका साथ कल तक दिया, पर आज वह परिवार रो रहा है. जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन की यह त्रासदी इससे पहले कहीं देखी–सुनी नहीं गई. मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, बृजभूषण तिवारी, मोहन सिंह सहित सारे समाजवादी और मानवाधिकार में विश्वास रखने वाले लोग आज ख़ामोश क्यों हैं? सरकार ख़ामोश है और अदालत भी क्यों इसका संज्ञान नहीं ले रही? ईश्वर, अल्लाह और गॉड अगर हैं तो उनसे प्रार्थना है कि किसी दुश्मन को भी जॉर्ज जैसी स्थिति न दिखाएं. जॉर्ज का इलाज एक मेडिकल बोर्ड करे और उन्हें उनके साथियों से मिलाया जाए. हमें भरोसा नहीं कि ऐसा होगा. वह राज्यसभा सदस्य भी हैं. क्या राज्यसभा भी कुछ नहीं कर सकती?

अगर कुछ नहीं हो पाता तो अफ़सोस रहेगा. इसीलिए अफ़सोस के साथ हमें उनके रहते लिखना पड़ रहा है कि एक थे जार्ज फर्नांडिस.

संपादक
editor.chauthiduniya.com

अल्लाह शब्द पर किसी का एकाधिकार नहीं

अनवर इब्राहीम

मलेशिया एक बार फिर से ग़लत कारण से अंतरराष्ट्रीय ख़बर की सुर्ख़ियों में है. पिछले दो सप्ताह के दौरान असामाजिक तत्वों ने पूजा के दस स्थलों को अपना निशाना बनाया है. इन स्थलों में ईसाइयों के गिरिजाघर और सिखों के गुरुद्वारे शामिल हैं. बहरहाल इस हमले में वहां कोई हताहत नहीं हुआ और संपत्तियों को जो नुक़सान पहुंचा उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है. लेकिन यह बात भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्षति के लिए नहीं कही जा सकती है. सरकारी अधिकारियों की ओर से कई विरोधाभासी बयानों के बाद हिंसा के वास्तविक कारणों का खुलासा अब भी नहीं हो पाया है. मलेशिया की छवि एक शांत राष्ट्र की रही है जहां जातीय और धार्मिक विविधता रही है. इन हमलों के बाद मलेशिया की यह छवि दांव पर है. सांप्रदायिक और धार्मिक मसलों से निपटने के मामले में मलेशिया का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है. मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों के साथ जो बुरा व्यवहार होता है, वह प्राय: उससे भी ख़राब होता है जिसका आरोप पश्चिमी देशों पर मुस्लिम समुदाय के लोग लगाते रहे हैं. मैंने मुस्लिम देशों में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता पर ध्यान देने की मांग की है जो हमारे न्याय, निष्पक्षता और विविधता की मांग में संतुलन और विश्वसनीयता को प्रदर्शित करे. ये ऐसे मूल्य हैं जो इस्लामिक परंपराओं से जुड़ी हैं. 12वीं शताब्दी के विधिवेत्ता अल–शातिबी ने भी इन मूल्यों को शरीया के ऊंचे उद्देश्यों के रूप में समझाया है. हम लोगों ने देखा है कि अपेक्षाकृत उदारवादी और प्रगतिशील माने जाने वाले पश्चिमी देशों में जब कोई पक्षपातपूर्ण क़ानून पास होता है तो इसका विरोध पूरी दुनिया के मुसलमान करते हैं. अभी जैसा कि जर्मनी में बुर्का या स्वीटजरलैंड में मीनारों को लेकर हुआ. लेकिन मलेशिया लगातार अपने यहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने में असफल रहा है. हाल की आगजनी की घटनाएं और हमले इस बात का संकेत है कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मलेशिया के रुख़ में गड़बड़ी कहां है. हमले की इस घटना को उस विवाद के चलते बढ़ावा मिला जिसमें मलेशिया के ईसाई समुदाय के लोगों ने अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया था. मलेशिया में इस समुदाय की जनसंख्या लगभग 20 लाख यानी 10 फ़ीसदी है. 2007 में गृह मंत्रालय ने एक कैथोलिक न्यूजपेपर, हेराल्ड पर अल्लाह शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था. बाद में, मलय भाषा में अनुदित, बाइबल की 15 हज़ार कॉपियां ज़ब्त कर ली गई थीं, जिसमें गॉड शब्द का अनुवाद अल्लाह किया गया था.

31 दिसंबर, 2009 को क्वालालंपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश से उक्त प्रतिबंध को नामंजूर कर दिया गया. इस प्रतिबंध को नामंजूर करने के पीछे न्यायालय का तर्क यह था कि मलेशिया का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है. तभी से मलेशिया की स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और इस तनाव को बढ़ाने के पीछे बहुत हद तक कुछ ग़ैर–ज़िम्मेवार नेताओं,

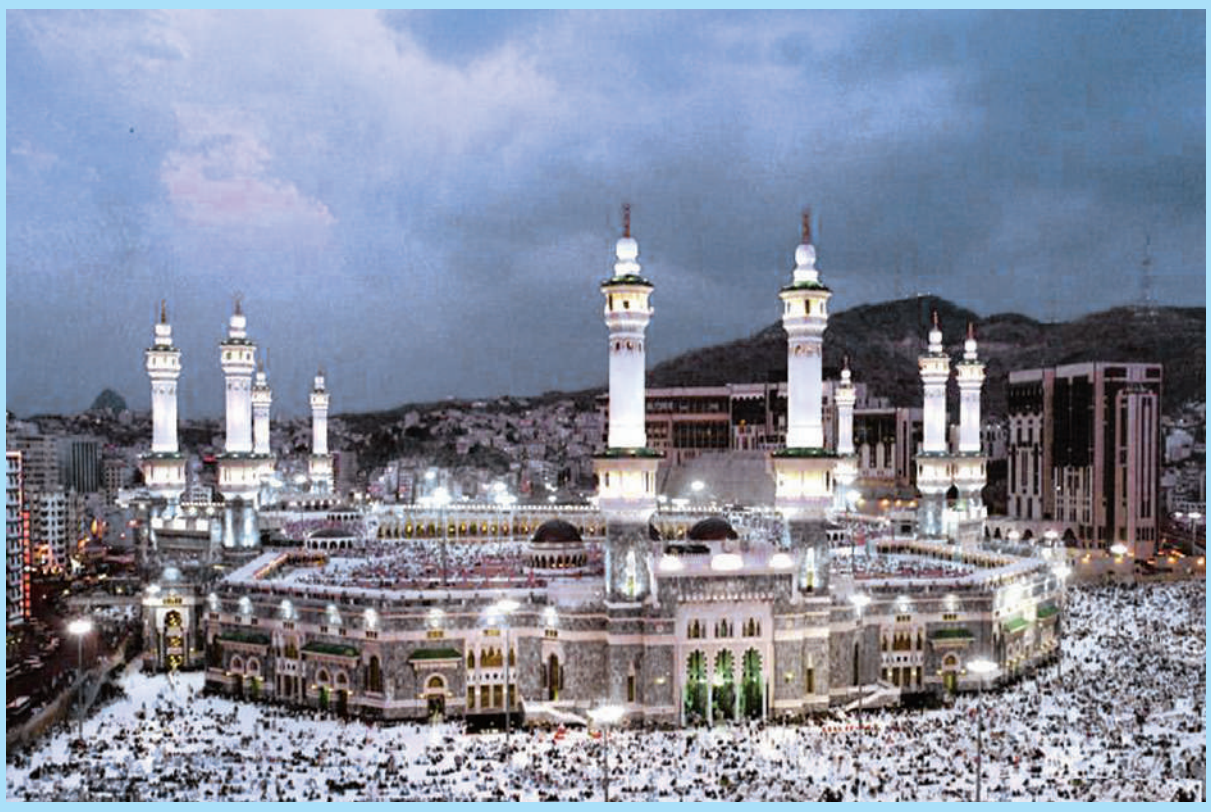

(सत्ताधारी दल से जुड़े) का भी हाथ रहा हैं. उदाहरण के तौर पर, देश के सबसे बड़े दैनिक अख़बार, उटुसन मलेशिया (यूएमएनओ से संबद्ध) ने मुस्लिम जनभावनाओं को भड़काने का काम किया है. अख़बार ने ग़ैर–मुस्लिमों को इस बात के लिए ज़िम्मेदार बताया है कि इन्होंने अल्लाह शब्द का अनादर किया है और ये लोग धर्म परिवर्तन के ज़रिए इस मुस्लिम बहुल देश में अपनी जनसंख्या बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं. मैंने पहले भी इस तरह के आक्रमक दुष्प्रचार का इस्तेमाल होते देखा है, जब नेताओं ने लोगों को भयभीत कर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की. इस तरह के हथकंडे शर्मनाक घटनाओं, जैसे न्यायालय के विवादित निर्णय या सैन्य ख़रीदारी में अनियमितता या रॉयल मलेशियन एयर फोर्स से दो जेट इंजन की चोरी, से ध्यान हटाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं. यह स्थिति तब से और ख़राब हुई है जब से सत्ताधारी दल ने गत वर्ष संसद में अपना दो तिहाई बहुमत खोया है. यूएमएनओ अब हताश है और जन समर्थन पाने के लिए संघर्ष कर रही है.

दुनिया के कुछ मुसलमान इस तरह के दावे कर सकते हैं कि अल्लाह शब्द पर उनका एकाधिकार है. यह स्वीकारा जा चुका है कि अल्लाह शब्द इस्लाम पूर्व अरब जगत में इस्तेमाल में था. अरब जगत के और प्रचलित भाषाओं में भी भगवान के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता था. अरामैक में इसे इलाहा और हिब्रू में इलोहिम के नाम से जानते थे. ऐतिहासिक पांडुलिपियों से भी यह साबित हुआ है कि अरब भाषा बोलने वाले मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सामूहिक रूप से ईश्वर की प्रार्थना करते थे और ब्रह्मांड के रचयिता और पालक भगवान के लिए 1400 साल तक अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करते रहे. दक्षिण–पूर्व एशिया में इस्लाम का इतिहास अपने विविध और विस्तृत परंपरा और मुस्लिम

> **दुनिया के कुछ मुसलमान इस तरह के दावे कर सकते हैं कि अल्लाह शब्द पर उनका एकाधिकार है. यह स्वीकारा जा चुका है कि अल्लाह शब्द इस्लाम पूर्व अरब जगत में इस्तेमाल में था. अरब जगत के और प्रचलित भाषाओं में भी ईश्वर या गॉड के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता था.**

सौहार्दपूर्ण रिश्तों के लिए लोकप्रिय रहा है. यही वजह है कि मलेशिया से बाहर के मुस्लिम विद्वान इस अल्लाह विवाद को बेतुका मान रहे हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आख़िर इतना विरोध और क्यों उपद्रव मचा हुआ है. पश्चिमी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय ने, ख़ास कर 9/11 की घटना के बाद, बड़ी मेहनत से लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि मुस्लिम, ईसाई और यहूदी एकसमान धार्मिक पृष्ठभूमि (उनकी जड़ें अब्राहम या इब्राहिम से जुड़ी हुई हैं) को साझा करते हैं और इसलिए एक समान ईश्वर को पूजते है. इस मुद्दे पर स्थानीय समुदाय की संवेदनशीलता भड़क गई. वर्तमान स्थिति से बातचीत और वचनबद्धता के ज़रिए क़ायदे से निपटना होगा, बजाए इसके कि लोगों के बीच असुरक्षा का भाव पैदा किए जाएं. मुस्लिम समुदाय को इस बात के लिए उत्साहित करना चाहिए कि वे ईसाई समुदाय से बातचीत करे और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराए. स्पेन के मुस्लिम समुदाय इसका एक बेहतरीन उदाहरण हैं और मलेशियाई मुसलमानों को इसका अनुसरण करना चाहिए. कॉमन वर्ड, एक वैश्विक प्रयास है जिसे 2007 में शुरू किया गया था. इसने विश्व के 130 प्रमुख मुस्लिम विद्वानों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचा है. इस प्रयास ने मुसलमानों और ईसाइयों के बीच भाईचारा बनाने और शांति तथा समृद्धि से जीवन जीने का रास्ता ढूंढ़ निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्रधानमंत्री नजीब रजाक के शपथ लेने के समय से ही मलेशिया की अंतरराष्ट्रीय ख्याति को धक्का पहुंच रहा है. राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के बजाय नजीब के शासन में मुस्लिम युवाओं द्वारा महिलाओं पर शराब पीने के आरोप में कोड़े बरसाए जा रहे हैं, मंदिर बनाने के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर गाय की कटी सिर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं. योगाभ्यास करने वाले मुसलमानों या इस्लाम स्वीकार कर चुके लोग यदि अपनी पुरानी आस्थाओं की ओर लौटते हैं तो उनके साथ ख़राब व्यवहार होता है. आख़िर नजीब इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं? मलेशिया भ्रष्टाचार की सूची में आगे ही बढ़ता जा रहा है. हमारा पर्यटन उद्योग दिन प्रति दिन ख़राब होता जा रहा है.

यह सब कुछ ऐसे मलेशियाई लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, जिनकी प्रतियोगिता तेज़ी से हो रहे सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण वाले वर्तमान दौर से है. आम मलेशियाई कुछ लोगों के हितों की बलि नहीं चढ़ सकते. बहरहाल, ऐसी राजनीति पुरानी हो गई है और अब यह साफ़ हो गया है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह सिर्फ सत्ता पर एकाधिकार बनाने के लिए कर रहे हैं. अधिसंख्यक मलेशियाई जनता इस तरह की सोच को नकारती है. वे महसूस करते हैं कि हम आज जिन चुनौतियों – जैसे मंदी, शिक्षा का गिरता स्तर और बढ़ती आपराधिक घटनाएं– का सामना कर रहे हैं, उससे हमें ख़ुद ही पार पाना होगा. साथ ही साथ निष्पक्षता और सभी के लिए न्याय के सिद्धांत को भी धरातल पर उतारना है.

(लेखक मलेशिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जस्टिस पार्टी के सदस्य हैं. फिलहाल वह नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं.)

भारत में भी कम ही लोग जानते हैं कि भारत की अपनी अलग अंकगणित है और उसका नाम है वैदिक अंकगणित. भारत के स्कूलों में वह शायद ही पढ़ाई जाती है.

जानने का अधिकार, जीने का अधिकार

चौथी दुनिया ने अपने पाठकों एवं आम लोगों के लिए एक नई पहल की है. इस कॉलम के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है सूचना का अधिकार कानून. कैसे आप इस कानून का इस्तेमाल कर बदल सकते हैं अपनी जिंदगी और सिखा सकते हैं भ्रष्ट अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को सबक. चौथी दुनिया आपको बताएगा कि कैसे करें इस कानून का इस्तेमाल और कैसे बनाएं आरटीआई आवेदन. अगर आपको इस कानून के इस्तेमाल से संबंधित कोई परेशानी हो या कोई सुझाव चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. हम करेंगे आपका मार्गदर्शन.

क्या है सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ. यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों/रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है. जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ कर भारत के सभी भागों में यह अधिनियम लागू है. सरकार के संचालन और अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन के मद में खर्च होने वाली रकम का प्रबंध भी हमारे–आपके द्वारा दिए गए करों से ही किया जाता है. यहां तक कि एक रिक्शा चलाने वाला भी जब बाज़ार से कुछ खरीदता है तो वह बिक्री कर, उत्पाद शुल्क इत्यादि के रूप में टैक्स देता है. इसलिए हम सभी को यह जानने का अधिकार है कि उस धन को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है. यह हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है.

किससे और क्या सूचना मांग सकते हैं

सभी इकाइयों/विभागों, जो संविधान या अन्य कानूनों या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन बने हैं अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किए जाते हों, वहां से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है.

- सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं.
- सरकारी निर्णय की प्रति ले सकते हैं.
- सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं.
- सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं.
- सरकारी कार्य के पदार्थों के नमूने ले सकते हैं.

किससे मिलेगी सूचना और कितना आवेदन शुल्क

इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन/लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के पद का प्रावधान है. आरटीआई आवेदन इनके पास जमा करना होता है. आवेदन के साथ केंद्र सरकार के विभागों के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ता है. हालांकि विभिन्न राज्यों में अलग–अलग शुल्क निर्धारित हैं. सूचना पाने के लिए 2 रुपये प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देने पड़ते हैं. यह शुल्क विभिन्न राज्यों के लिए अलग–अलग है. आवेदन शुल्क नकद, डीडी, बैंकर चेक या पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा किया जा सकता है. कुछ राज्यों में आप कोर्ट फीस टिकटें खरीद सकते हैं और अपनी अर्ज़ी पर चिपका सकते हैं. ऐसा करने पर आपका शुल्क जमा माना जाएगा. आप तब अपनी अर्ज़ी स्वयं या डाक से जमा करा सकते हैं.

आवेदन का प्रारूप क्या हो

केंद्र सरकार के विभागों के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है. आप एक सादे कागज़ पर एक सामान्य अर्ज़ी की तरह ही आवेदन बना सकते हैं और इसे पीआईओ के पास स्वयं या डाक द्वारा जमा कर सकते हैं. (अपने आवेदन की एक प्रति अपने पास निजी संदर्भ के लिए अवश्य रखें)

सूचना प्राप्ति की समय सीमा

पीआईओ को आवेदन देने के 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए. यदि आवेदन सहायक पीआईओ को दिया गया है तो सूचना 35 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए.

सूचना न मिलने पर क्या करे

यदि सूचना न मिले या प्राप्त सूचना से आप संतुष्ट न हों तो अपीलीय अधिकारी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक अपील दायर की जा सकती है. हर विभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है. सूचना प्राप्ति के 30 दिनों और आरटीआई अर्जी दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं.

द्वितीय अपील क्या है?

द्वितीय अपील आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अंतिम विकल्प है. द्वितीय अपील सूचना आयोग के पास दायर की जा सकती है. केंद्र सरकार के विभागों के विरुद्ध केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य सरकार के विभागों के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग. प्रथम अपील के निष्पादन के 90 दिनों के भीतर या उस तारीख के 90 दिनों के भीतर कि जब तक प्रथम अपील निष्पादित होनी थी, द्वितीय अपील दायर की जा सकती है.

यदि आपने सूचना कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना नीचे लिखे पते पर भेजें, हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई–मेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन –201301
ई–मेल: rti@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

विदेशों में वैदिक विधि पर ज़ोर

भारत में गणित की वैदिक विधि कम ही लोग जानते हैं, लेकिन विदेशों में लोग मानने लगे हैं कि इस विधि से गणित के सवाल हल करने में न केवल मजा आता है, बल्कि इससे आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति में बढ़ोत्तरी भी होती है.

जर्मनी में सबसे कम समय का एक नियमित टेलीविज़न कार्यक्रम है विसन फोर अख्त, जिसका अर्थ है आठ के पहले ज्ञान की बातें. देश के सबसे बड़े रेडियो और टेलीविज़न नेटवर्क एआरडी के इस कार्यक्रम में हर शाम आठ बजे प्रसारित होने वाले मुख्य समाचारों से पहले भारतीय मूल के विज्ञान पत्रकार रंगा योगेश्वर केवल दो मिनटों में ज्ञान–विज्ञान से संबंधित किसी दिलचस्प प्रश्न का सहज–सरल उत्तर देते हैं. कुछ दिन पहले रंगा योगेश्वर बता रहे थे कि भारत की क्या अपनी कोई अलग गणित है? वहां के लोग क्या किसी दूसरे ढंग से सवाल हल करते हैं. भारत में भी कम ही लोग जानते हैं कि भारत की अपनी अलग अंकगणित है और उसका नाम है वैदिक अंकगणित. भारत के स्कूलों में वह शायद ही पढ़ाई जाती है. यहां के शिक्षाशास्त्रियों का भी यही विश्वास है कि असली ज्ञान–विज्ञान वही है, जो इंग्लैंड–अमेरिका से आता है.

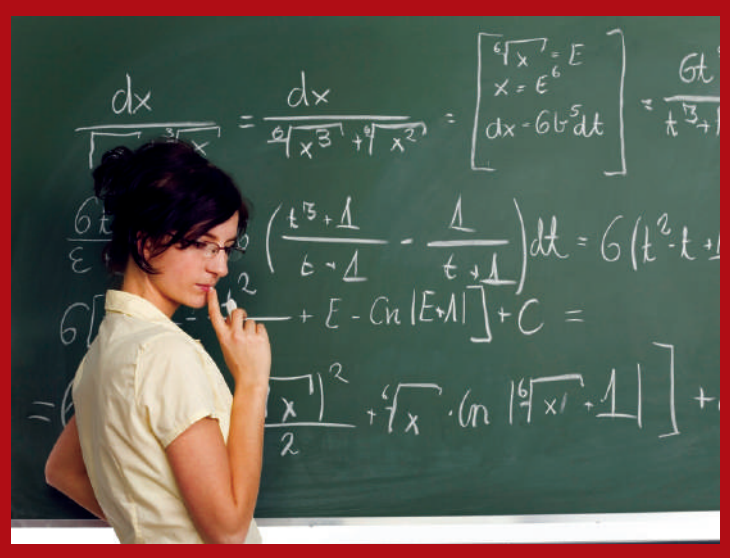

जर्मनी के आन गांव वाले अब भारत की वैदिक अंकगणित पर चकित हो रहे हैं और उसे सीख रहे हैं. बिना काग़ज़–पेंसिल या कैल्क्युलेटर के मन ही मन हिसाब लगाने का उससे सरल और तेज तरीक़ा शायद ही कोई है. रंगा योगेश्वर ने जर्मन टेलीविज़न पर दर्शकों को एक उदाहरण के द्वारा समझाया.

उन्होंने कहा मान लें कि हमें 889 में 998 का गुणा करना है. प्रचलित तरीक़े से यह इतना आसान नहीं है. भारतीय वैदिक तरीक़े से उसे ऐसे करेंगे कि दोनों का सब से नज़दीकी पूर्णांक एक हज़ार है. उन्हें एक हज़ार में से घटाने पर मिले 111 और 2. इन दोनों को आपस में गुणा करने पर 222 मिलेगा. अपने मन में आप इसे दाहिने तरफ़ लिखें. अब 889 में से उस दो को घटाए, जो 998 को एक हज़ार बनाने के लिए जोड़ना पड़ा. उसे घटाने पर हमें 887 मिला. इसे मन में 222 के पहले बायीं ओर लिखें. यानी 887 222 सही गुणनफल है.

वैदिक विधि से बड़ी संख्याओं का जोड़–घटाना और गुणा–भाग ही नहीं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल निकालना भी संभव है. इस बीच इंग्लैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बच्चों को वैदिक गणित सिखाने वाले स्कूल भी खोले गए हैं.

एक्यूपंक्चर से गर्भावस्था अवसाद का इलाज

अक्सर गर्भावस्था के दौरान महिलाएं तनावग्रस्त हो जाती हैं. यह मां और बच्चे दोनों के लिए घातक है, लेकिन एक नए शोध के मुताबिक़, इस अवसाद को एक्यूपंक्चर पद्धति से दूर किया जा सकता है. शोध में शामिल डॉ. शइनर के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान अवसाद चिंता का विषय है, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव मां और बच्चे के साथ–साथ पूरे परिवार पर पड़ता है.

बकौल डॉ. शइनर, इस दौरान 150 गर्भवती महिलाओं पर शोध करके उनका वर्गीकरण तनाव के आधार पर किया गया. उनमें से एक तिहाई महिलाओं को तनाव से मुक्त रखने के लिए उनका एक्यूपंक्चर पद्धति से इलाज किया गया. दूसरे वर्ग का इलाज एक्यूपंक्चर पद्धति से मिलती–जुलती पद्धति से किया गया और तीसरे वर्ग का इलाज मालिश द्वारा किया गया. ग़ौरतलब है कि आठ सप्ताह में सभी वर्गों का 12 तरीक़ों से इलाज किया गया.

वे महिलाएं, जिनका असली एक्यूपंक्चर पद्धति से इलाज किया गया, अन्य वर्गों की तुलना में उनके लक्षणों में काफ़ी कमी आई. इस प्रायोगिक समूह में काफ़ी महिलाओं को एक्यूपंक्चर पद्धति से इलाज के लिए सलाह दी गई. शोध के अनुसार, उन मरीजों, जिनका नक़ली एक्यूपंक्चर पद्धति और मालिश से इलाज किया गया, ने भी असली एक्यूपंक्चर पद्धति से इलाज के लिए हामी भरी.

यह शोध काफ़ी महत्वपूर्ण है. इसे सोसाइटी फॉर मेटर्नल फेटल मेडिसिन मीटिंग के दौरान पेश किया गया.

राशिफल

22 फरवरी–28 फरवरी 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी. आर्थिक योजना को बल मिलेगा. पारिवारिक कार्य में व्यस्तता रहेगी. किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता अधिक रहेगी. अधीनस्थ कर्मचारी या पड़ोसी से तनाव मिल सकता है. स्वास्थ्य के मामले में संयम रखें. सर्दी, जुकाम या मौसमी रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं. व्यवसायिक मामलों में जोख़िम न उठाएं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. धन, पद, प्रतिष्ठा की दिशा में प्रगति होगी. व्यवसायिक मामलों में जोख़िम न उठाएं. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है. नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
विरोधी सक्रिय रहेंगे. पारिवारिक जनों से तनाव मिल सकता है. व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रहेंगे और भागदौड़ अधिक रहेगी. शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में अधिक परिश्रम करने से ही सफलता मिलेगी. व्यवसायिक मामलों में जोख़िम न उठाएं.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आर्थिक प्रगति होगी. धन, यश एवं कीर्ति में वृद्धि होगी. किसी कार्य के संपन्न होने से आपका प्रभाव एवं वर्चस्व बढ़ेगा. आर्थिक प्रदर्शन हितकर न होगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
उपहार और सम्मान मिल सकता है. निजी सुख में वृद्धि होगी. व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी. भौतिक दिशा में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे. धन, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. शासन–सत्ता का सहयोग रहेगा. व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होंगे. निजी संबंधों में निकटता आएगी.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
धन, सम्मान, परिवार में वृद्धि के योग हैं. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक सफलता मिलेगी. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे. धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव एवं वर्चस्व में वृद्धि होगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है. निजी संबंधों में निकटता आएगी. सामाजिक कार्य की दिशा में प्रगति होगी.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं. धन, सम्मान की दिशा में प्रगति होगी. यात्रा– देशाटन का लाभ मिलेगा. रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. संबंधों में निकटता आएगी. यात्रा–देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद होगी. किसी कार्य के संपन्न होने से आपका प्रभाव और वर्चस्व बढ़ेगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ओबामा प्रशासन द्वारा ताइवान को हथियार बेचने के फ़ैसले पर चीन ने उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन उसकी अधिकांश प्रतिक्रिया सांकेतिक ही रही है.

आक्रामक कूटनीति की समस्याएं

लंबी तनावपूर्ण चुप्पी के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान को सचिव स्तरीय वार्ता की पेशकश की गई. इस पेशकश का स्वागत तो हुआ, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताते हुए बयानबाजी करने से नहीं चूके. भारत आतंकवाद को केंद्र में रखना चाहता है तो पाकिस्तान राग कश्मीर का आलाप खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा.

डॉ. मलीहा लोढ़ी

पाकिस्तान के साथ सचिव स्तर की बातचीत के लिए भारत की पेशकश से दोनों देशों के बीच गतिरोध दूर होने की संभावना है. लेकिन, तत्काल चुनौती यह है कि बातचीत का रास्ता कैसे शुरू हो?

भारत ने पहले बातचीत के सभी दरवाज़े बंद कर दिए थे, लेकिन अब उसकी इस नीति में बदलाव आया है. शांति प्रक्रिया की वापसी की दिशा में यह एक आगे बढ़ने वाला क़दम होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान इसके लिए कितना तैयार है. यह उसके लिए एक खुला प्रश्न है. हालांकि यह वार्ता 2004 में शुरू हुई थी और इसे समग्र वार्ता का नाम दिया गया था, जिसे 2008 में मुंबई पर आतंकी हमलों के बाद रद्द कर दिया गया. दो सप्ताह पहले भारतीय विदेश सचिव निरूपमा राव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सलमान बशीर को दिल्ली में बातचीत के लिए फोन किया. इस्लामाबाद ने इस बातचीत की पेशकश का स्वागत किया, लेकिन उसने बैठक की शर्तों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा. इसके बाद से ही दोनों देशों की ओर से राजनयिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं. दोनों देश इस बैठक के लिए समय और समझौते के उद्देश्य को तय करने में लग गए हैं. बातचीत न करने के भारत के रुख़ में बदलाव तनाव भरे 14 महीनों के बाद आया है. बातचीत की यह प्रक्रिया शिथिल सी हो गई थी और भारतीय बयान से इसमें और भी तनाव का इज़ाफ़ा हुआ. जबकि भारतीय जनरलों ने एक उत्तेजक माहौल को जन्म दिया और सेना ने सीमाओं पर अभ्यास करना शुरू कर दिया. भारतीय राजनेताओं ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि यदि मुंबई जैसे हमले फिर दोहराए गए तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सैनिक कार्रवाई होनी चाहिए. दिसंबर में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर के बयान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल अशफ़ाक़ कयानी को भी प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाया.

हाल में दोनों ओर की सीमाओं पर तनाव देखने को मिला. इसकी वजह थी लाहौर और सियालकोट क्षेत्र में सीमाओं के उल्लंघन की घटना. इसकी एक वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की बढ़ती घटनाएं भी हैं. हालांकि दिल्ली ने पाकिस्तान द्वारा बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश को ठुकरा दिया था, जबकि पाक किसी भी शर्त पर वार्ता शुरू करने के लिए तैयार था. भारत के रुख़ में आया यह बदलाव कई सवाल खड़े करता है. आख़िर इसके रवैये में किस हद तक बदलाव आया है? अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या यह बदलाव रणनीति है अथवा वास्तविक पहल? क्या यह राजनयिक कोशिश बातचीत की प्रक्रिया को सशक्त करने में लाभदायक होगी? यदि इन सवालों के जवाब तलाशे जाएं तो तीन कारकों पर ध्यान देना काफी अहम होगा. इससे पता चल सकता है कि आख़िर भारत के कूटनीतिक रवैये में बदलाव की वजह क्या है? पहली बात यह कि भारत ने आक्रामक कूटनीति का रास्ता अपनाया, लेकिन इसकी असफलता या इसके बीच आने वाली समस्याएं इसकी वजह हो सकती हैं. वर्ष 2001–02 में भारतीय संसद पर हमले के बाद आक्रामक कूटनीतिक रवैया अपनाना भारत के लिए उल्टा दांव पड़ा था. इस बार भी यही हुआ. यह दिल्ली का अपना आकलन हो सकता है कि एक ही बात पर अड़े रहने से पाकिस्तान से किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद नहीं की जा सकती है. इन सबके बावजूद इस क़दम से अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति और सहयोग खोने का ख़तरा बना रहा, जो उस समय भारत के पास था. पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक रिश्तों को बंद करने का यह मतलब भी हो सकता है कि पाकिस्तान इस मक़सद में कामयाब रहा कि उसने इस क़दम को भारतीय सफलता नहीं बनने दिया. यानी भारत के लिए मामला जैसे को तैसा हो गया. बातचीत न करने की मुद्रा से बाहर आने के साथ ही दिल्ली ने कूटनीतिक संपर्क के विकल्प को चुनने का फ़ैसला लिया. जैसा कि कुछ भारतीय अधिकारियों ने बताया कि अपनी स्थिति फिर से मज़बूत करने के लिए ही भारत ने यह फ़ैसला लिया. बातचीत के लिए दिल्ली द्वारा नरम रवैया अपनाने की दूसरी वजह यह है कि अमेरिका सारा खेल परदे के पीछे से खेल रहा है. क्योंकि, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को लगता है कि भारत–पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से अफ़ग़ानिस्तान में उसकी रणनीतिक नीतियों पर पानी फिर सकता है. हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों ने तनाव कम करने और बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए काफी दबाव बनाया, ताकि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने में सारा ध्यान अपनी पश्चिमी सीमा पर दे सके. अमेरिकी रक्षामंत्री रॉबर्ट गेट्स ने भी जनवरी में इस इलाक़े में अपने दौरे के समय बातचीत की बहाली के लिए काफी दबाव बनाया. हालांकि उनके इस बयान से पाकिस्तान में विवाद का माहौल बना रहा कि यदि भारत में मुंबई जैसे हमले दोबारा होते हैं तो यह उसके बर्दाश्त के बाहर की बात होगी. पाकिस्तान के साथ भारत की बातचीत की पेशकश से अंतरराष्ट्रीय दबाव को अच्छी तरह से कम किया जा सकता है. ख़ासकर उस समय में, जब पश्चिमी अधिकारियों को यह लगता है कि अफ़ग़ानिस्तान में उनकी परियोजना बेहद नाज़ुक दौर में पहुंच चुकी है. अमेरिकी अधिकारियों ने इस नए घटनाक्रम पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच इन उत्साही क़दमों का हर तरह से समर्थन करता है. वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि उसने अपनी नीतियों पर पूरी तरह यू टर्न लेते हुए अपने घुटने टेक दिए हैं.

भारतीय विदेश सचिव निरूपमा राव

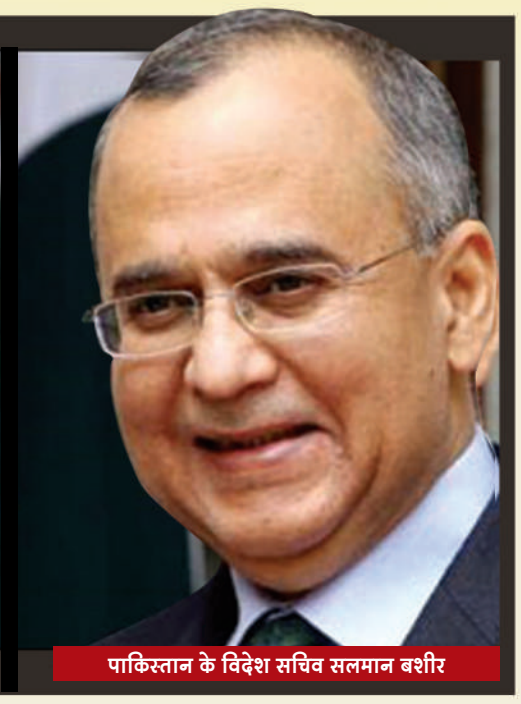

पाकिस्तान के विदेश सचिव सलमान बशीर

इस मसले से जुड़ी तीसरी बात यह है कि अफ़ग़ानिस्तान में तेज़ी से बदल रहे घटनाक्रम ने दिल्ली की चिंताएं बढ़ा दी हैं. ख़ासकर, उस घटनाक्रम ने, जो लंदन कॉन्फ्रेंस के समय उभर कर सामने आया. अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका की वापसी की बात ने बेशक़ भारत की दुविधा बढ़ा दी है. इन घटनाओं से अनिश्चितता बढ़ी है. और, मुमकिन है कि पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में केंद्रीय भूमिका निभा रहा हो, ताकि वह द्विपक्षीय वार्ता के बीच में आने वाले रोड़े को दूर कर सके. इस तरह कूटनीतिक प्रभाव को बरकरार रखने के लिए रणनीतिक परिदृश्य में बदलाव की यह कोशिश हो सकती है.

भविष्य के लिए यह सवाल उठता है कि क्या यह समझौता दोनों मुल्कों के बीच वार्ता के स्तर तक पहुंच सकता है, ताकि दोनों मुल्कों के कई मुद्दों को सुलझाया जा सके. पाकिस्तान ने यह साफ़ कर दिया है कि वह समग्र वार्ता चाहता है. यह ध्यान देने वाली बात है कि इस समग्र वार्ता को पांच दौर तक चलने के बाद 2008 में स्थगित कर दिया गया. लेकिन संकेत यह मिल रहा है कि दिल्ली अभी इस पर अपना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहेगी. और, वह चाहेगी कि सारा मसला आतंकवाद के इर्द–गिर्द ही केंद्रित रहे. सूत्रों के हवाले से भारतीय मीडिया में यह बात कही गई है कि दिल्ली एक सीमा तक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वह समग्र वार्ता नहीं चाहती. वह चाहती है कि आतंकवाद के मुद्दे को पहली प्राथमिकता दी जाए.

बातचीत की एकतरफ़ा कोशिश इस वार्ता को ग़ैर लाभकारी और अस्थाई बनाएगी. यदि यह समझौता कश्मीर समेत दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है, तो इस्लामाबाद उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया देने को प्रतिबद्ध हो जाएगा. पाकिस्तानी अधिकारियों ने पहले यह संकेत दिए हैं कि वे पहले की बातचीत की प्रक्रिया की तरह तैयार नहीं हैं. यानी वह नतीजा चाहते हैं.

शर्म अल शेख समेत पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अधिकारियों ने समग्र वार्ता की उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने संकेत दिए हैं कि भविष्य में बातचीत का मुद्दा आतंकवाद के इर्द–गिर्द ही होगा. भारतीय मीडिया में आई ख़बरों ने यही बात साबित की है. लेकिन, इन चुनिंदा और खंडित मुद्दों पर बातचीत से शांति प्रक्रिया टिकाऊ नहीं हो सकती है. भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक परिदृश्य में बातचीत की प्रक्रिया 1997 में शुरू हुई और यह लगभग 12 वर्षों तक चली. इस दौरान दोनों मुल्कों के विभिन्न मुद्दों और प्राथमिकताओं, जिनमें कई विवाद भी शामिल थे, पर वार्ता हुई.

वार्ता की इन प्रक्रियाओं ने शानदार सफलता हासिल नहीं की, लेकिन दोनों मुल्कों के कई मंत्रालयों के बीच बातचीत के रास्ते खोले. तात्कालिक सफलता के लिए इस रूपरेखा को नकारने से सिर्फ़ एक ही पक्ष को फ़ायदा होगा, जो कि व्यवहारिक नहीं है. आख़िरकार भविष्य की बातचीत का क्या अंजाम होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों मुल्क अपने मतभेद और पहचान को कितनी जगह दे सकते हैं. पहले कश्मीर, न्यूक्लियर–मिलिट्री मुद्दे और अफ़ग़ानिस्तान को शामिल करना होगा. उसके बाद व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और आतंकवाद से साझा ख़तरे के मुद्दे को शामिल करना होगा. दोनों मुल्कों के बीच लगातार वार्ता से ही आपसी संबंधों में मजबूती आएगी. इसी से दोनों के बीच आपसी अविश्वास की भावना दूर होगी. यदि ऐसा नहीं हुआ तो मौजूदा कोशिश को एक बार फिर ग़लत शुरुआत के तौर पर माना जाएगा, न कि एक नई शुरुआत के तौर पर.

(लेखिका अमेरिका एवं ब्रिटेन में राजदूत रह चुकी हैं और द न्यूज़ की पूर्व संपादक हैं.)

अमेरिका और चीन एक-दूसरे की ज़रूरत हैं

हाल में अमेरिका और चीन के संबंधों में काफ़ी उथल–पुथल देखने को मिली. इसके बावजूद दोनों देशों के पास एक–दूसरे को सहयोग करने की बेहद ठोस वजह है. यह घटनाक्रम पिछले दो दशकों में विकसित हुआ है. इस बात को दोनों मुल्क स्वीकार करते नज़र आ रहे हैं. ओबामा प्रशासन द्वारा ताइवान को हथियार बेचने के फ़ैसले पर चीन ने उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन उसकी अधिकांश प्रतिक्रिया सांकेतिक ही रही है. इसकी तुलना 1992 की घटना से करने पर सारी बातें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं. उस समय जब बुश सीनियर प्रशासन ने ताइपेई को हथियार दिए थे, तो उसके तुरंत बाद चीन ने पाकिस्तान को मिसाइलें बेची थीं. इसके अलावा चीन ने ईरान के साथ आण्विक सहयोग के लिए समझौता किया. इस बार चीन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अमेरिकी कंपनियों से है, जो हथियारों की ख़रीद–फरोख्त में शामिल हैं. चीन उन फर्मों को निशाना बनाना चाहता है, जो लंबे समय से ताइपेई को हथियारों की आपूर्ति कर रही हैं. मसलन रेथियॉन, क्योंकि इस वजह से चीनी बाज़ारों पर बुरा असर पड़ा है. हालांकि इन समझौतों में शामिल तीन बड़ी अमेरिकी कंपनियों बोइंग, जेनरल इलेक्ट्रिक और यूनाइटेड टेक्नोलॉजी को बीजिंग दंडित नहीं करना चाहेगा.

ठीक इसी तरह राष्ट्रपति ओबामा ने दलाई लामा से मिलने का फ़ैसला किया तो इस पर भी चीन का उग्र रवैया महज़ दिखावा भर ही था. चीनी सरकार को इस बात से ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ होगा. यदि पिछले कुछ समय की स्थितियों पर एक नज़र डालें तो हाल में जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं, उन सभी ने दलाई लामा से मुलाक़ात की है. और, ओबामा ने प्रत्यक्ष तौर पर चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ से कहा कि वह तिब्बती नेता से मिलने जा रहे हैं. वहीं वाशिंगटन के नज़रिए से देखें तो चीन में इंटरनेट की आज़ादी को लेकर हिलेरी क्लिंटन ने चीन की आलोचना की. साथ ही राष्ट्रपति ओबामा ने भी यह बात कही कि वह करेंसी के मसले पर चीन के साथ सख्ती से पेश आएंगे. उक्त सभी बयान हालिया गतिविधियों से मेल नहीं खाते हैं. अमेरिका के तरकश में कई तीर हैं. और, अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है कि बीजिंग में जनता की सलाह बिरले ही सुनी जाती है. दरअसल, दोनों मुल्क यह खेल अच्छी तरह खेल रहे हैं. जनता के गुस्से को शांत करने के लिए ही वे ऐसा कर रहे हैं. लेकिन इसमें दो बातें हो सकती हैं. पहली बात यह कि चीन में यह धारणा बढ़ रही है कि वह पश्चिमी मुल्कों पर अब अधिक निर्भर नहीं रहा. और, ख़ास तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका पर, जैसा कि वह पहले था. 1980 के दशक में डेंग ज़ियोपिंग ने चीन के दरवाज़े विदेशी निवेश के लिए खोल दिए. चीन की इस रणनीति ने जापान और दक्षिण कोरिया की निर्यात आधारित नीति को प्रभावित किया. लेकिन, चीनी विद्वान मिनज़ीन पेई यह तर्क देते हैं कि यह सब कुछ मुक्त बाज़ार वाली पूंजीवादी विचारधारा में परिवर्तन नहीं था. सांस्कृतिक क्रांति द्वारा बर्बादी के बाद बीजिंग को पश्चिमी प्रबंधन गुर सीखने की ज़रूरत थी, ताकि वह जान सके कि अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए तकनीक और पूंजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. आज चीन पूंजी के मामले में काफी संपन्न है. इसकी स्थानीय कंपनियां शीर्ष पर हैं और इस साल पहली बार चीन के विकास की पहली धुरी इसका घरेलू बाज़ार रहा है, न कि निर्यात. यदि चीन अपने आंतरिक बाज़ार का विस्तार करता है तो यह इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिहाज़ से काफ़ी अहम होगा.

राष्ट्रपति ओबामा ने दलाई लामा से मिलने का फ़ैसला किया तो इस पर भी चीन का उग्र रवैया महज़ दिखावा भर ही था. चीनी सरकार को इस बात से ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ होगा. यदि पिछले कुछ समय की स्थितियों पर एक नज़र डालें तो हाल में जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं, उन सभी ने दलाई लामा से मुलाक़ात की है.

यही हक़ीकत विदेश नीति में भी लागू होती है. माओ ने अमेरिका के साथ संबंध बरकरार रखे तो कुछ मायनों में इसलिए कि वह सोवियत संघ के सहयोगी के तौर पर ख़ुद को भुना सकें. चीन को एक राजनीतिक सहयोगी के तौर पर अमेरिका की ज़रूरत थी. अमेरिका के साथ जियांग ज़ेमिन की तल्खी भी एक रणनीति का ही हिस्सा थी. उसका मक़सद बेहद ही ठोस था, विश्व व्यापार संगठन में सदस्यता हासिल करना. आज पूरी दुनिया में चीन की इज्ज़त है. यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को लेकर बेहद आश्वस्त है. इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है. लेकिन बीजिंग के इस नए अहं को व्यापक परिदृश्य में नहीं देखा गया. यह मुल्क दुनिया में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है. अंतरराष्ट्रीय समिट में बीजिंग ने व्यापक तौर पर अपने संकीर्ण हितों पर अधिक ध्यान दिया है. उदाहरण के तौर पर, अप्रैल में जी–20 समिट में चीन ने प्रत्यक्ष तौर पर सिर्फ एक ही मुद्दे पर भागीदारी दिखाई. वह भी उस मुद्दे पर कि हांगकांग को तटीय टैक्स से दूर रखा गया और वह इसकी जांच कर रहा है.

चीन एक व्यापक भूमिका निभाएगा, वैश्विक स्तर पर ज़िम्मेदारी लेगा और व्यापक हितों के लिए सर्वसम्मति से फ़ैसला लेगा, इन सारी बातों की उम्मीद करना शायद जल्दबाज़ी होगी. लेकिन, इसने वैश्विक व्यवस्था में अपना प्रभाव छोड़ा है. कई मोर्चों पर यह घातक साबित हो सकता है. 1920 के दशक में अमेरिका का अलगाव समझा जा सकता था, लेकिन इसका भी पूरी दुनिया में बुरा असर पड़ा. दूसरी बात यह कि दोनों मुल्कों के बीच तनाव अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था की तक़दीर को ख़तरे में डाल सकता है. फ़िलहाल तो ख़तरा यही है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट ही दर्ज़ हो रही है. यदि अमेरिकी राजनेता अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से प्रतिस्पर्धी बनाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं और बीजिंग यह मानने लगता है कि वह एक कमज़ोर हो रही महाशक्ति के साथ काम कर रहा है तो बुनियादी तौर पर चीन और अमेरिका के रिश्तों में बदलाव आएंगे. इसमें कोई शक़ नहीं कि यदि ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए और भी चिंता बढ़ जाएगी.

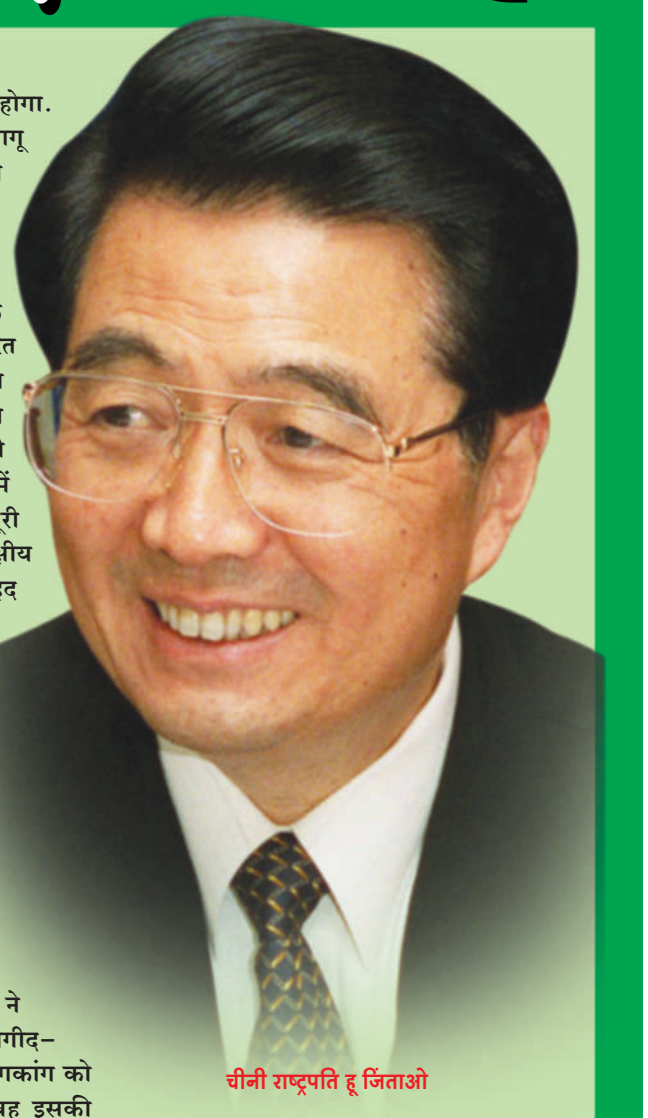

चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साई कृपा से कुछ पल के लिए राधेश्याम पर वशीकरण का प्रयोग भी नकाम हो गया. राधेश्याम ने जब शिल्पा से उसकी कुंडली के बारे में पूछा तो वह शेरनी की तरह दहाड़ उठी और राधेश्याम को भला-बुरा कहना शुरू कर दिया, परंतु तब-तक राधेश्याम की आंखें खुल चुकी थीं.

साई बाबा सारे विश्व में पूजनीय हैं-अनिल शर्मा

विकास कपूर

जिस आयु में लड़के अपने भविष्य की चिंता भी नहीं करते, उस आयु में अनिल शर्मा ने लाइट, कैमरा और एक्शन बोलना शुरू करके अपना स्वर्णिम भविष्य निश्चित कर लिया था. के सी शर्मा के होनहार सुपुत्र अनिल शर्मा ने युवावस्था की दहलीज़ पर क़दम रखते हुए अपने ज़माने की सुपर स्टार राखी गुलज़ार को लेकर एक फ़िल्म बनाई- श्रद्धांजलि (1981). फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई. इस फ़िल्म के बाद अनिल जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. हुकूमत, ऐलान-ए-जंग, फरिश्ते, तहलका, सुहाग, गदरः एक प्रेम कथा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो और अपने आदि उनकी फ़िल्में हैं. इन दिनों अनिल जी की सलमान ख़ान के साथ नई फ़िल्म वीर बॉक्स ऑफिस पर सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रही है. एक फ़िल्मकार के रूप में अनिल शर्मा की जितनी प्रशंसा की जाए कम है. किसी दृश्य को विज़्वलाइज़ करने की जो अनूठी प्रतिभा अनिल जी के भीतर है, वह शायद किसी अन्य निर्देशक में देखने को नहीं मिलती. ब्रजभूमि से संबंध रखने वाले अनिल जी राधारानी और बांके बिहारी के अनन्य भक्त हैं, परंतु शिरडी के साईबाबा में भी उनकी गहरी आस्था है. पिछले दिनों विकास कपूर ने अनिल जी से उनके अंधेरी स्थित निवास पर साईबाबा के बारे में विस्तृत बातचीत की. यहां प्रस्तुत हैं उसके कुछ अंश.

सबसे पहले आपको, मेरी और चौथी दुनिया परिवार की ओर से फ़िल्म वीर के लिए शत-शत शुभकामनाएं.

आप सबको भी मेरी और वीर की टीम की ओर से ॐ साईराम और धन्यवाद.

शिरडी के साईबाबा के बारे में आपकी अपनी सोच और आस्था क्या है?

साईबाबा अब केवल शिरडी के नहीं, सारे विश्व के पूजनीय हैं. मैं शूटिंग के सिलसिले में जहां भी जाता हूं, वहां लोग मुझसे बाबा के बारे में पूछते हैं. लोगों के मन में बाबा के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा है. शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जहां साईबाबा का मंदिर न हो.

बाबा की भक्ति का जितनी तेज़ी से प्रचार-प्रसार हुआ, उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं?

साईबाबा आज के समाज की ज़रूरत हैं. सारे विश्व के धर्मगुरुओं, अवतारों और पैगंबरों में साईबाबा अकेले ऐसे चरित्र हैं, जो अपने अनुयायियों को किसी जात-पात, धर्म-मज़हब के दायरे में नहीं बांधते. उनका दरबार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए समान रूप से खुला है. उनके जीवन का सारा दर्शन उनकी इसी घोषणा में छिपा है कि सबका मालिक एक है. समाज ने उनके इस दर्शन को बहुत जल्दी समझा और स्वीकार भी कर लिया. एक बात और, आदमी वहीं शीश नवाता है, जहां से उसे कृपा प्राप्त होती है. मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के पास जाकर कोई भक्त ख़ाली हाथ नहीं लौटता.

अनिलजी, साईबाबा पर कई फ़िल्में बनी है और सफल भी रही हैं. एक सफल फ़िल्मकार होने के नाते कभी आपके मन में साईबाबा पर कोई फ़िल्म बनाने का ख़्याल नहीं आया?

बिल्कुल आया और मैं बनाना चाहता भी हूं, केवल साईबाबा ही नहीं, मैं तो वेद-पुराणों के कई चरित्रों पर भव्य फ़िल्मों का निर्माण करना चाहता हूं. हमारी धार्मिक पुस्तकों में कथा कहने का जो अंदाज़ है, वह अन्य धर्मों की पुस्तकों में नहीं मिलता. यह मेरा संकल्प है कि मैं समय आने पर इन फ़िल्मों का निर्माण अवश्य करूंगा.

आपकी दृष्टि में साईबाबा का अब-तक का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है?

चमत्कारों में मेरा विश्वास थोड़ा कम है. मैं कर्म की थ्योरी को ही श्रेष्ठ मानता हूं और चमत्कार मुझे भाग्यवाद की तरफ ले जाता है. परंतु जहां तक साईबाबा के चमत्कार की बात है तो 1918 में महासमाधि लेने वाले साईबाबा केवल 90-92 साल के भीतर सारे विश्व के पूजनीय हो गए, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? लेकिन साईभक्तों को इस बात का अन्वेषण अवश्य करना चाहिए कि साईबाबा कौन थे? उनका जन्म कहां हुआ था? कहां से चलकर वह शिरडी पहुंचे थे? हालांकि बाबा की सच्चरित्रता इन सारे प्रश्नों का खंडन करती है फिर भी समाज के लिए यह सारी खोज अनिवार्य और आवश्यक है. ॐ साईराम.

अगले अंक में
सुरेश वाडकर के साई अनुभव

भक्ति की शक्ति

बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की निर्मल वर्मा और उनके पति राधेश्याम की साईचरणों में पूरी आस्था थी. परंतु पिछले कुछ दिनों से राधेश्याम का विश्वास डगमगाता जा रहा था. साईकृपा से निर्मल के घर हर ख़ुशी थी, केवल एक औलाद को छोड़कर. राधेश्याम को लगता था, जब बाबा हमारे मन की मुराद पूरी नहीं कर सकते तो इनकी पूजा ही क्यों की जाए. उसने अपनी क़सम देकर निर्मल को भी साईपूजन से रोक दिया. निर्मल इससे काफ़ी परेशान थी. उन्हीं दिनों उसे शिल्पा नाम की एक लड़की के बारे में पता चला जो तंत्र-मंत्र का प्रयोग करके लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा किया करती थी. निर्मल को देखते ही शिल्पा ने उन्हें सिर्फ़ उनकी परेशानी ही नहीं बताई, उपचार की घोषणा भी कर दी. शिल्पा से मिलने के बाद निर्मल को अपने घर-आंगन में बच्चों की किलकारी सुनाई देने लगी. तभी शिल्पा ने उसे बताया कि औलाद पाने के लिए उन्हें एक अमावस से दूसरी अमावस तक हर रात अपने पति राधेश्याम को उसके पास भेजना होगा. पहले तो राधेश्याम तैयार नहीं हुआ, फिर निर्मल का मन रखने के लिए वह शिल्पा के पास चला गया. तांत्रिक शिल्पा ने वशीकरण आदि मंत्रों का प्रयोग करके राधेश्याम को अपने चक्कर में फंसा लिया. उसने राधेश्याम को निर्मल की झूठी कुंडली दिखा कर समझा दिया कि निर्मल कभी मां नहीं बन सकती. उसके मातृत्व पर दैत्यशक्तियों का अधिकार है. अब राधेश्याम अपनी जान से भी प्यारी पत्नी निर्मल की उपेक्षा करने लगा. उसने निर्मल को हमेशा के लिए छोड़कर शिल्पा से शादी करने का निश्चय कर लिया. घटनाओं के चक्रव्यूह में उलझ चुकी निर्मल के पास साईबाबा की शरण में जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था. साईबाबा तो अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए तत्पर ही रहते हैं. निर्मल की व्यथा का अंत करने के लिए शिल्पा के साथ शादी की तैयारियों में लगे राधेश्याम के हाथ तक बाबा ने शिल्पा की असली कुंडली लगवा दी. इस कुंडली को देखते ही कुंडलियों के जानकर राधेश्याम को आभास हुआ कि शिल्पा के गण राक्षस हैं और वह मैली विद्या का अनुष्ठान करती है. साईकृपा से कुछ पल के लिए राधेश्याम पर वशीकरण का प्रयोग भी नकाम हो गया. राधेश्याम ने जब शिल्पा से उसकी कुंडली के बारे में पूछा तो वह शेरनी की तरह दहाड़ उठी और राधेश्याम को भला-बुरा कहना शुरू कर दिया, परंतु तब-तक राधेश्याम की आंख खुल चुकी थी. उसने शिल्पा को ठुकरा दिया. जब वह निर्मल के साथ अपने गुनाहों की माफी मांगने साई मंदिर पहुंचा तो उन्हें एक भिखारी मिला. उसने भिक्षा लेने के स्थान पर उन्हें सीख दी कि इस दुनिया में कितने स्त्री-पुरुष हैं जो औलाद के लिए तड़पते हैं, लेकिन कभी यह सोचा कि कितने ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो मां-बाप के लिए तड़पते हैं. उस भिखारी को बाबा मानकर राधेश्याम और निर्मल ने एक बच्ची को गोद ले लिया. अब उनके घर-परिवार में ख़ुशियां ही ख़ुशियां हैं.

feedback@chauthiduniya.com

हमारी भक्ति

साईबाबा के जीवन व दर्शन और आपकी भक्ति से संबंधित किसी एक विषय पर यहां परिचर्चा आयोजित की जाएगी और श्रेष्ठ विचार भेजने वाले साईभक्त के विचार यहां प्रकाशित किए जाएंगे.

पिछले सप्ताह का विषयः साईबाबा ने सबका मालिक एक क्यों कहा?

आपके जवाबः

1. हमारा समाज अनेक शताब्दियों से ऊंच-नीच और जात-पात के बंधनों से जकड़ा रहा है. अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरी जातियों का दमन करने की परंपरा पर अंकुश लगाने के लिए ही साईबाबा ने सबका मालिक एक है, कहा.

- *संतोष बादल*, पटना, बिहार (सर्वश्रेष्ठ विचार)

2. सबका मालिक एक है, कहकर साईबाबा सारे समाज को यह संदेश देना चाहते थे कि मनुष्य-मनुष्य में कोई अंतर नहीं, सभी एक परमात्मा की संतान हैं और सबका स्वामी एक ही है.

- *त्रिवेणी खत्री*, जमशेदपुर, झारखंड

3. सबका मालिक एक है कहकर साईबाबा हमारे समाज को प्रेम और प्यार से रहने की शिक्षा देना चाहते थे. इस शब्द का अर्थ यही है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, फिर भाई-बंधु होकर भी आपस में शत्रुता क्यों?

- *मिनी चड्ढा*, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

इस सप्ताह का विषयः

श्रद्धा और सबुरी कहकर साईबाबा हमें क्या सिखाना चाहते थे?

आप अपने विचार sai4world@gmail.com **पर अपने नाम और पते के साथ मेल करें अथवा *शिरडी साईबाबा फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नम्बर-17517, मोतीलाल नगर नंबर-1, गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई-58 के पते* पर डाक द्वारा भेजें. इसके अलावा शिरडी साईबाबा फाउंडेशन का सदस्य बनने के लिए** 09999989421 पर संपर्क कर सकते हैं.

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj
Sai Hills
Sai Vihar Township
Spiritual Home...

- Fully Furnished and Spacious Studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Fumished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

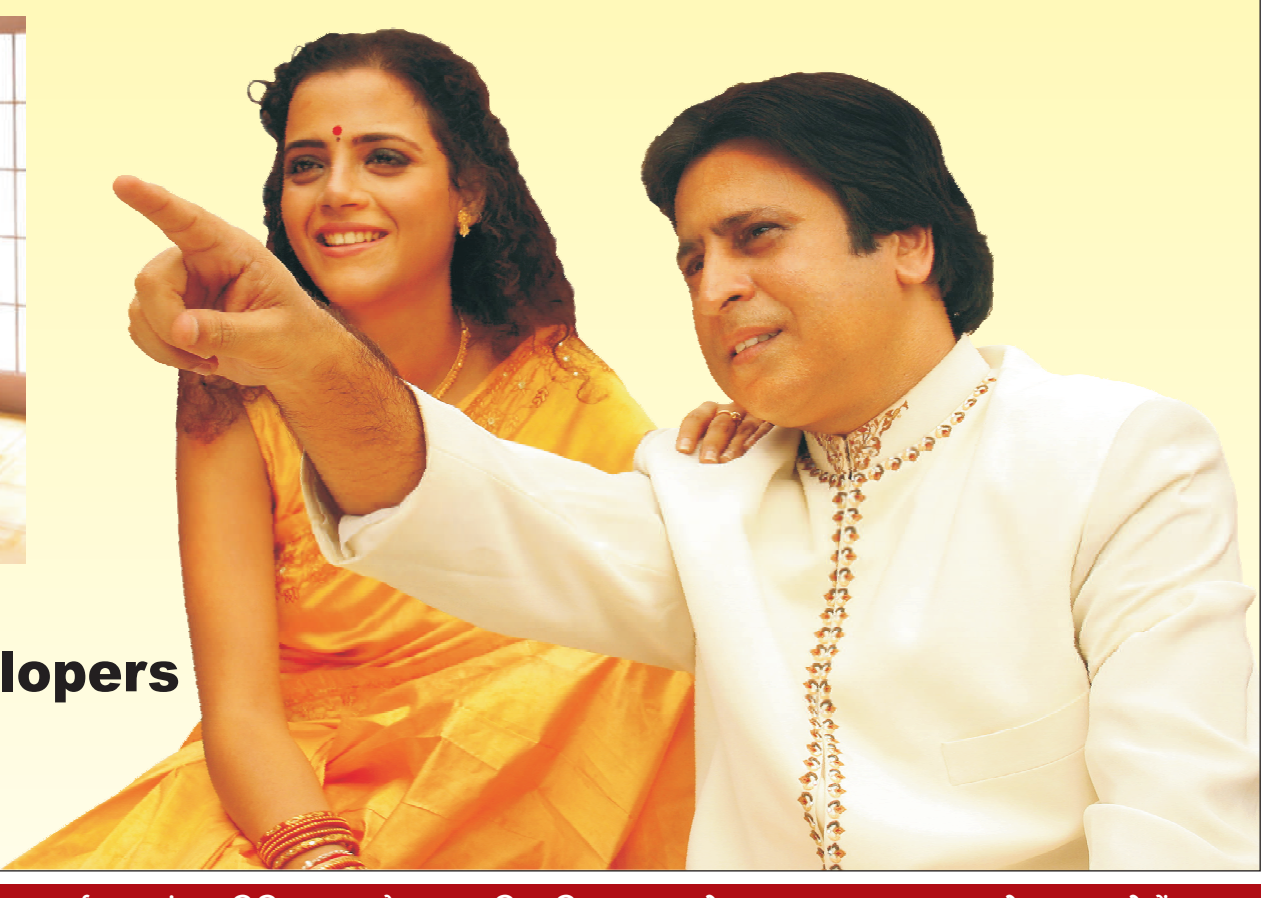

AUM Infrastructure & Developers

Aum Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.girirajsaihills.in

एक ओर मंडलेश्वर उपाधि पाने वाले संत को पेशवाइयों एवं शाही जुलूसों में अपने वैभव प्रदर्शन का अवसर मिलता है, दूसरी ओर अखाड़ों को उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त होती है.

युवाओं की भागीदारी से प्रकाशक गदगद

अनंत विजय

दिल्ली में आयोजित उन्नीसवां पुस्तक मेला ख़त्म बीती सात फरवरी को संपन्न हो गया. इस पुस्तक मेले में कई दिलचस्प बातें हुईं. पिछले विश्व पुस्तक मेले से मैंने कवि मित्र और कला प्रेमी यतींद्र मिश्र के साथ जामिनी राय की कई बेहतरीन पेंटिंग्स ख़रीदी थी, जो कि मेरी पत्नी को काफ़ी पसंद आई थी. वह पिछले दो साल से इस पुस्तक मेले का इंतज़ार कर रही थी. जामिनी राय की पेंटिग्स की तलाश में वह मेरे साथ इस उम्मीद के साथ पुस्तक मेले में गई कि इस बार वहां से कई सारी पेंटिंग्स ख़रीद लाएगी. लेकिन पूरे हॉल के दो चक्कर लगाने के बावजूद हमें कोई स्टॉल नहीं दिखा, जहां पेंटिंग्स की बिक्री हो रही हो. इस बीच हमने तय किया कि मेला के आयोजक नेशनल बुक ट्रस्ट के पूछताछ काउंटर पर जाकर इस बारे में पता लगा लिया जाए. मैंने काउंटर पर पहुंचकर वहां बैठी सुंदर सी लड़की से पूछा कि क्या किसी स्टॉल पर पेंटिंग्स की बिक्री हो रही है. उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप किसकी पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, जामिनी राय. यह नाम सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर यह भाव आया मानों जवाब देने का सूत्र उसके हाथ लग गए हों. उसने फौरन पुस्तक मेले की डायरेक्ट्री पलटी और चंद पल के बाद ही मुझसे कहा कि नहीं, इस बार जामिनी राय नहीं आए हैं और उनका कोई स्टॉल भी मेले में नहीं लगा है. इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरी पत्नी ने मुझे रोक लिया और कहा, जब इनको इतना तक पता नहीं कि जामिनी राय कौन थे, तो इनसे उनके बारे में पूछने का कोई मतलब नहीं रह जाता है. हम लोग हंसते हुए पूछताछ काउंटर से वापस हॉल की तरफ़ चल पड़े. मेला का आयोजन करने वाली संस्था नेशलन बुक ट्रस्ट को इतनी फुरसत नहीं कि वहां पहुंचने वाले पाठकों की वह मदद कर सकें.

मेला ख़त्म होने के बाद अख़बारों में नेशनल बुक ट्रस्ट के मुखिया बिपान चंद्रा का एक बयान छपा है. बिपान चंद्रा ने बताया कि इस बार के मेले में ट्रस्ट की पुस्तकों की बिक्री पिछले साल के मुक़ाबले दुगुनी हो गई है और वह इसकी वजह किताबों के प्रति युवाओं की बढ़ती दीवानगी मानते हैं. लेकिन आगे वह बिक्री अधिक होने का राज ख़ुद ही खोल देते हैं– अभी तक ट्रस्ट की पुस्तकों के मुख्य ख़रीदार दक्षिण भारतीय राज्य हुआ करते थे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से पुस्तकों की ख़रीद के जो ऑर्डर मिले हैं, उससे साबित हो गया है कि किताब पढ़ने की भूख अभी ख़त्म नहीं हुई है. बिपान चंद्रा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार और विद्वान हैं. लेकिन किताबों की बिक्री के आंकड़ों पर वह जो तर्क दे रहे हैं, वह गले से नीचे नहीं उतरती है. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के ऑर्डर से यह साबित होता है कि पढ़ने की भूख कम नहीं हुई है. इस बयान पर यही कहा जा सकता है कि लगता है बिपान चंद्रा को सरकारी ख़रीद का पूरा खेल मालूम नहीं है या अगर मालूम है तो नेशनल बुक ट्रस्ट का मुखिया होने की वजह से वह इसे ज़ाहिर नहीं करना चाहते हैं. सरकारी ख़रीद पुस्तकालयों और ग़ैर सरकारी संगठनों को अनुदान देने के लिए की जाती है. हमारे देश में पुस्तकालयों की हालत पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. सरकारी ख़रीद के लिए जो अधिकारी ज़िम्मेदार होते हैं, उन्हें साहित्य और स्तरीय किताबों से कुछ लेना देना नहीं होता है. वास्तव में होता यह है कि जो प्रकाशक इन अधिकारियों को जितना ख़ुश कर सकता है, उसकी उतनी ज़्यादा किताबें ख़रीदी जाती हैं. सरकारी थोक ख़रीद के आधार पर यह कहना कि युवाओं में पढ़ने की भूख कम नहीं हुई है, ग़लत होगा.

पुस्तक मेले में एक स्टॉल पर पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम

यह बात अलहदा है कि इस बार के पुस्तक मेले में युवाओं की जमकर भागीदारी रही. मेले के दौरान कई प्रकाशकों से काफ़ी देर तक पुस्तकों की बिक्री और मेले में पाठकों के उत्साह को लेकर चर्चाएं हुईं. प्रकाशकों की मानें तो इस बार बिक्री के आंकड़े भी उत्साहजनक रहे हैं. लगभग दर्ज़नभर प्रकाशकों से हुई बातचीत से जो एक बात कॉमन निकली वह यह कि इस बार के पुस्तक मेले में युवाओं ने जमकर शिरक़त की. प्रभात प्रकाशन के मालिक पीयूष कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में पुस्तक के प्रति युवाओं की ख़ासी रुचि प्रकाशन जगत के लिए शुभ संकेत है. उनके मुताबिक़, आज के युवा प्रेरणादायी पुस्तकें ज़्यादा ख़रीद रहे हैं. इसके अलावा इस बार प्रभात प्रकाशन से चेतन भगत की हिंदी में अनुदित किताबें भी ख़ूब बिकीं. वाणी प्रकाशन के कर्ता–धर्ता अरुण माहेश्वरी के स्टॉल पर इस बार जमकर पुस्तकों का लोकार्पण हुए. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से लेकर इरफान ख़ान तक वहां पहुंचे. मेले के अंतिम दिन पत्रकार प्रदीप सौरभ की चर्चित किताब मुन्नी मोबाइल का लोकार्पण भी हुआ. राजकमल प्रकाशन के स्टॉल पर भी लोकार्पणों की धूम रही. ममता कालिया से लेकर वंदना राग तक की किताबों का विमोचन हुआ. विमोचन की सबसे उत्तम व्यवस्था राजकमल प्रकाशन के स्टॉल पर थी. लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गीता प्रेस, गोरखपुर के स्टॉल पर सबसे ज़्यादा भीड़ और ख़रीदार जुटे थे.

एक और बात महत्वपूर्ण है. पुस्तक मेला के आयोजकों को प्रगति मैदान में लगनेवाले प्रवेश शुल्क का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए. पुस्तक मेला में शामिल होने के लिए पुस्तक प्रेमियों को प्रत्येक दिन बीस रुपये का टिकट लेना पड़ता था. यह रक़म कोई बड़ी नहीं है, लेकिन टिकट ख़रीदने के लिए जो लंबी कतार लगती है, वह पुस्तक मेले में भाग लेने की इच्छा रखने वालों के उत्साह को कम करती है. एनबीटी को भविष्य में इस बात का ध्यान रखना चाहिए. या तो पुस्तक मेले में प्रवेश शुल्क समाप्त कर दिया जाना चाहिए या फिर टिकट बिक्री की व्यवस्था शहर में अलग– अलग जगहों पर की जानी चाहिए.

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

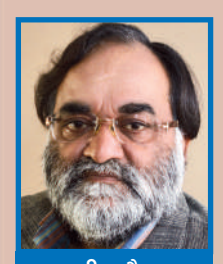

प्रदीप सौरभ

शहआलम राहत शिविर में यह कथा सिर्फ़ खालिद की ही नहीं है. यहां रहने वाले हर आदमी की कहानी कुछ ऐसी है कि जानने वाले लोगों की नींद उड़ जाए. शिविर में कोई भी मर्द औरत साबुत नहीं है. किसी की टांग कटी है. किसी को गोली लगी है. कोई आधा जला है तो कोई पूरा. हर शख़्स के चेहरे पर दहशत छाई है. हलकी सी आहट भी उन्हें चौंका देती है. बचने के बाद कई रातों से उन्हें नींद नहीं आ रही है.

शिविर के एक कोने में निढाल पड़ी महबूब बीबी की आंखें पथरा गई हैं. आठ लोगों के परिवार में बस आठ साल की बेटी बची है. पूछने पर कुछ नहीं बोलती. शिविर में कारसेवा कर रहे राजा भाई कहानी सुनाते हैं और बीबी सिर हिलाती जाती है, ममां का सिर फोड़ दिया. बहन के साथ बलात्कार किया. आठ साल की भांजी और सात साल के दो भतीजों को बांधकर आग में फेंक दिया. धू–धू कर बीबी की आंखों के आगे जल गए.

पास में खड़ी बीबी जरीना अपना कटा हुआ हाथ दिखाते हुए बिलख पड़ती है, दंगाइयों में हमारे इलाक़े का विधायक भी था. पुलिस से भी हमें कोई मदद नहीं मिली. मिलती भी कैसे? पुलिस तो उनके साथ थी. आधे से ज़्यादा जली अफ़साना अपना इलाज करा अभी अभी शिविर में आई है. वह सुधबुध खो चुकी है. वापस घर जाने के सवाल पर न की मुद्रा में सिर हिलाती है. शिविर में घर वापसी के सवाल पर सभी एकमत हैं. सब यही कहते हैं कि उनका सब बर्बाद हो गया है.

ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां आयशा, रहमान भाई, नूरजहां, अब्दुल्ला, जुलेखा बानो, कबीर अली, हनीफ बीबी, शबाना आदि आदि की है. शिविर में हर शख़्स का अफ़साना एक–सा है. यही नहीं, भेदभाव की इंतहा तो यह है कि इन राहतशिविरों में सरकारी मदद भी सांप्रदायिक आधार पर हो रही है. गोली लगने और पत्थर की चोट खाने वालों, दोनों को दो हज़ार मुआवज़ा. शिविर में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्हें यह मदद भी नहीं मिली है. बिना मुआवज़ा दिए अधिकारियों ने पीड़ितों से रेडकार्ड भरवाए और उन्हें घर जाने के लिए मजबूर किया. अव्यवस्था का आलम यह है कि शौच के लिए पर्याप्त शौचालय नहीं है. तमाम बदइंतज़ामी के बाद

सच यह है कि यहां से कोई अपने घर वापस नहीं जाना चाहता. वे अपने को अपने आशियाने से ज़्यादा यहां महफ़ूज़ महसूस कर रहे हैं.

देश में जब गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका को लेकर हो–हल्ला मचा तो इसी शिविर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे. उन्होंने भावुक तकरीर दी. सुनने वालों को लगा कि अब मोदी सरकार चेतेगी. वाजपेयी ने कहा, अब से कुछ देर बाद मैं विदेश यात्रा के लिए रवाना होने वाला हूं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मुंह लेकर वहां जाऊं. अपने ही घर में लोग शरणार्थी हो गए हैं. वाजपेयी ने मोदी को राज धर्म पालन करने की सलाह भी दी. वाजपेयी की तकरीर ख़त्म हो चुकी थी. मोदी अपना सा मुंह लिए उनके बगल में छिपे खड़े थे. तभी भीड़ में से एक महिला गुस्से में मोदी की ओर इशारा करते हुए बोली, ममोदी हत्यारा है. वह वाजपेयी को सत्य बताना चाह रही थी. राजनीति के आगे सब सच बेकार होते हैं. वाजपेयी के विचारों के बाद सबको यह लगा कि मोदी को जाना ही पड़ेगा. मोदी के इस्तीफ़े का दबाव बनने लगा.

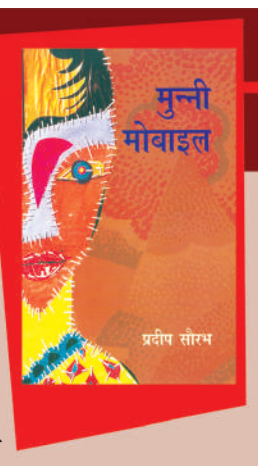

थोड़े दिन बाद गोवा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी थी. इस्तीफ़े के लिए मोदी को मना लिया गया था. लेकिन बाजपेयी वहां पहुंचते ही पलट गए. बोले, गोधरा में आग किसने लगाई? इस सवाल का जवाब तो चाहिए. कार्यकारिणी के बाद मोदी और मज़बूत होकर गुजरात लौटे. उन्हें वाजपेयी का आशीर्वाद मिल चुका था.

feedback@chauthiduniya.com

कुंभ विरक्ति का नहीं, वैभव का प्रदर्शन

डॉ.कमलकांत बुधकर

कोई ज़माना था, जब कुंभ के अवसर पर निकलने वाली पेशवाइयों का रूप आज निकलने वाली पेशवाइयों से बहुत भिन्न हुआ करता था. आज तो पेशवाई नगर से नगर में प्रवेश होकर रह गई है. लेकिन, पहले पेशवाई वह विशेष दिन और वह विशेष अवसर होता था, जब देश भर में फैले विभिन्न अखाड़ों के साधु–संन्यासी किसी कुंभनगर में पहली बार प्रवेश करते थे. यानी दूसरे शब्दों में कहें तो देश भर के अन्य नगरों, गांवों, वन–प्रांतों और दूरदराज के पर्वतीय स्थानों से अपने–अपने तंबू–डेरे उखाड़ कर आए साधु–संतों को कुंभ स्नान से पहले कुंभपर्व के लिए नगर प्रवेश करवाने को ही पेशवाई कहने की परंपरा रही है. इन पेशवाइयों से पहले अखाड़ों के रमता पंच कुंभ नगरों में आकर अपने डेरे डालते थे. फिर ये लोग पूर्व निश्चित दिन में दल–बल सहित अखाड़ों की कुंभ छावनियों में प्रवेश करते थे. तब इन पेशवाई या प्रवेशाई जुलूसों में तंबू–शामियाने और खूंटे–रस्से ही नहीं, बल्कि हंडे, कढ़ाहे, जाजम, दरियां, अनाज के बोरे आदि ढेर सारा सामान भी बैलगाड़ियों, ऊंटगाड़ियों और खच्चरों पर लाद कर छावनियों में लाया जाता था. नागा संन्यासी अपने शस्त्रास्त्रों के साथ उनका प्रदर्शन करते हुए इन जुलूसों में चलते थे. वे संख्या में भी अधिक होते थे और भौतिक आकर्षणों से भी दूर हुआ करते थे.

ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है. हरिद्वार में 1974 एवं 1986 के कुंभों तक यह दृश्य ख़ूब दिखाई पड़े हैं, पर बाद में स्थितियां बदलीं और उनके अनुरूप दृश्य भी बदलते गए. इन पंक्तियों के लेखक को वे दिन याद हैं, जब किसी दर्शक या पत्रकार के हाथों में कैमरा देखकर साधु–संन्यासी लड़ने–मारने पर उतारू हो जाते थे, लेकिन अब तो साधु–संन्यासी पोज़ देकर फोटो उतरवाते ही नहीं, उनके हाथों में भी कैमरे देखे जा सकते हैं. अब साधु–संन्यासी भी समय के साथ–साथ चल रहे हैं. पर पेशवाई का वह पुराना स्वरूप और दृश्य अब दुर्लभ होता जा रहा है. अब पेशवाइयां शोभा यात्राओं में बदल गई हैं. कमोबेश स्नान दिवसों पर निकलने वाली शाहियों यानी वैभवपूर्ण स्नान जुलूसों और पेशवाई जुलूसों में अब कोई अंतर नहीं रह गया है. वही दर्ज़नों बैंडवालों के दल, वही एकाध हाथी, दर्ज़न भर घोड़े, कभीकभार ऊंटों की कतारें और स्कूल–कॉलेज के बच्चों एवं अध्यापकों के साथ विभिन्न सांस्कृतिक नर्तकों के दलों को एकत्र कर पेशवाइयां निकाली जाती हैं. अपनी–अपनी क्षमता के अनुसार अखाड़े अपने पेशवाई जुलूसों पर हेलीकॉप्टरों से पुष्पवर्षा तक का ख़र्चीला प्रबंध करवाते हैं. इस बार हरिद्वार में महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़ों की पेशवाइयों के अवसर पर दर्शकों ने हेलीकॉप्टरों से पुष्पवर्षा के दृश्यों का आनंद लिया.

दरअसल, अब हरिद्वार में जमातों के पड़ावों की भूमि भी धीरे–धीरे कम होती जा रही है. पक्के निर्माणों का बोलबाला है, इसीलिए डेरों–तंबुओं में धूनी रमाकर रहने वाले साधुओं की संख्या भी कम होती जा रही है. नागा संन्यासियों की कमी पर अख़बारों में टिप्पणियां छपीं कि इस बार अब तक की पेशवाइयों में नागा संन्यासी कम आए हैं. इस पर चिंता की जाए या संतोष, यह विषय तो बहस का हो सकता है, पर सच्चाई यही है कि युग परिवर्तन ने नागा बनने और वनों– कंदराओं में साधना करने की प्रवृत्ति पर भी असर डाला है. यही वजह है कि कुंभ में विरक्ति का अभाव दिख रहा है और वैभव का विस्तार.

अब पेशवाइयां और शाहियां बड़े–बड़े गद्दीधारी श्रीमहंतों और मंडलेश्वरों के वैभव प्रदर्शन के अवसर के रूप में उभर रही हैं. 2010 के हरिद्वार कुंभ से पूर्व अनेक अखाड़ों ने नवनवीन मंडलेश्वरों का अभिषेक कर उन्हें अपनी जमात में शामिल किया है. बड़े वैभवशाली स्थानधारी साधुओं को अपनी जमात में शामिल करके

चर्चा कुंभनगर की

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

अखाड़े अपनी श्रीशोभा और आर्थिक स्तर दोनों में वृद्धि करते हैं. यह दोहरे लाभ का अवसर होता है. एक ओर मंडलेश्वर उपाधि पाने वाले संत को पेशवाइयों एवं शाही जुलूसों में अपने वैभव प्रदर्शन का अवसर मिलता है और दूसरी ओर अखाड़ों को उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त होती है.

आज के मीडिया और प्रदर्शन से आक्रांत इस युग में साधु और उनके संप्रदाय भी इनसे अछूते नहीं हैं. इसलिए भी कि जिनके जलवे ज़्यादा हैं, भीड़ भी उन्हीं के पीछे चलती है. भीड़ के पीछे ही मीडिया है और मीडिया के पीछे–पीछे समाज. कुल मिलाकर वैभव का महत्व है, विरक्ति का नहीं. विरक्ति अगर कहीं है भी, तो वह वैभव की चेरी है. कुंभ जैसे अवसरों पर वह विरक्ति वैभव की अनुगामिनी बनकर चलती है.

समाज में जब जहां वैभव प्रदर्शन की बात होगी, वहां होड़ होगी, प्रतियोगिता होगी, एक–दूसरे से आगे बढ़ने की लालसा होगी. इस होड़ से साधु–संतों के आश्रम–अखाड़े भी अछूते नहीं हैं. बल्कि कहें कि इस होड़ में पीछे नहीं हैं. कुंभ जैसे अवसरों पर यह होड़ अनेक प्रकार से सामने आती है. आज हरिद्वार में साधु–संतों के चित्रों वाले बड़े–बड़े होर्डिंग्स की होड़ है, उनके कुंभ शिविरों के विज्ञापनों की होड़ है, किसके आश्रम–शिविर में कौन वीआईपी या वीवीआईपी आ रहा है, इस बात की होड़ है. इसी होड़ से कुंभ नगरों का कुंभ प्रशासन भी प्रभावित होता आया है. इस बार का हरिद्वार का कुंभ प्रशासन इसलिए भी साधु–संतों के अधिक दबाव में है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है. भाजपा साधु–संतों के प्रति अधिक उदार और अधिक समर्पित है. नतीजा यह है कि सरकार की नीति एवं कुंभ प्रशासन की रीति दोनों मिलकर अखाड़ों और साधु–संतों के वैभव प्रदर्शन में सहायक ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके वैभववर्द्धन, शक्तिवर्द्धन और सुविधावर्द्धन में सीधे–सीधे सहायक हो रहे हैं.

एक और बात जो हर कुंभ का हिस्सा हो जाती है, वह है कुछ बातों को लेकर विवाद. विवादों और कुंभों का प्राय: चोली–दामन का साथ रहा है. इस बार एक शंकराचार्य और एक अखाड़े ने ब्रह्मकुंड का विवाद फिर उठा दिया है. उनका कहना है कि असली ब्रह्मकुंड गंगा पार नील पर्वत की तलहटी में दक्षिण काली मंदिर के निकट गंगा की मुख्य धारा में है. वर्तमान हरकी पौड़ी और ब्रह्मकुंड तो कॉटले की गंगनहर में हैं. पर ऐसा कहने वाले अपने पक्ष में कोई ठोस प्रमाण न पहले दे पाए हैं और न ही आज दे पा रहे हैं. उलटे वे इस तथ्य को ज़बरदस्ती नकारते दिखते हैं कि कर्नल प्रॉबी टी कॉटले द्वारा 1854 में निकाली गई वर्तमान गंगनहर से पहले मुख्य गंगा का विस्तार ही नील पर्वत से बिल्व पर्वत के बीच था. और, तब भी हरकी पौड़ी और ब्रह्मकुंड वहीं थे, जहां आज हैं. ऐसे अनेक चित्र इस बात के प्रमाण हैं. पर कुछ लोग विवाद के लिए ही विवाद को ज़िंदा रखने में यक़ीन रखते हैं. साधु संप्रदाय में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है.

दूसरा विवाद हाल ही में जन्मा है. सात संन्यासी अखाड़ों के अलावा बैरागी, उदासी और निर्मलों के छह अखाड़े चाहते हैं कि वे 30 मार्च को एक और शाही स्नान करें. परंपरानुसार कुंभ के शाही स्नान सर्वत्र तीन ही होते आए हैं. हरिद्वार में पहला स्नान अकेले संन्यासी अखाड़े करते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे शाही स्नान में तेरह अखाड़े शामिल होते हैं. हरिद्वार में मुख्य कुंभ स्नान के बाद एक दिन अकेले बैरागियों के स्नान की भी परंपरा है, पर उसे शाही स्नान की मान्यता नहीं है. इस बार संन्यासेतर छहों अखाड़े चाहते हैं कि उनका एक शाही स्नान अलग से घोषित हो. अगर शासन–प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो वे कोई शाही स्नान नहीं करेंगे. यानी यह एक ज़बरदस्त धमकी है अपने वर्चस्व और शक्ति प्रदर्शन की. अब देखना यह है कि प्रशासन इस धमकी को कितनी गंभीरता से लेता है.

kk@budhkar.in

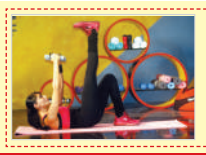

बिपाशा की इस डीवीडी में 25 मिनट का वर्कआउट वीडियो है, जो लड़कियों को बिपाशा जैसी बॉडी पाने का सपना पूरा कर सकता है.

गेमर्स के लिए लैपटॉप

कंप्यूटर, लैपटॉप एवं मोबाइल आदि अब लोगों के लिए संचार की ज़रूरत से अधिक ख़ालीपन को दूर करने की चीज़े हो गई हैं. बोरियत महसूस हो तो इन पर गेम्स खेलना आजकल लोगों का फेवरिट टाइमपास हो गया है. गेम्स खेलने के शौक़ीन लोगों को कई बार अपने लैपटॉप में गेम्स एक्सेस करने में परेशानी होती है. यह परेशानी चाहे ग्राफिक्स लोड होने की हो या हैवी फाइल्स एक्सेस होने की, लेकिन ऐसी तकनीकी परेशानियां गेमर्स का मूड ज़रूर ख़राब कर देती हैं. ऐसे ही स्मार्ट गेमर्स के लिए एमएसआई ने गेमिंग नोटबुक्स लांच की हैं. एमएसआई के अल्ट्रा पावरफुल इंटेल कैलपेला फीचर्स के साथ जी-सीरीज़ की जीटी-640 और जीटी-740 नोटबुक्स फ्लैट स्क्रीन 15.4 इंच और 17 इंच मॉनीटर में उपलब्ध हैं. इंटेल कोर प्रोसेसर सी आई-7 क्वाडको प्रोसेसर के साथ जुड़ा एनवीडिया जीई फोर्स जीटीएस 250 एम थ्री डी ग्राफिक्स इनेबल फीचर इसे विश्व की सबसे बेहतरीन गेमिंग नोटबुक बनाता है. विश्वस्तरीय मल्टीमीडिया इंटरफेस से लैस यह नोटबुक लाल रंग से हाइलाइटेड डब्ल्यूएएसडी की-बटन से काफ़ी अलग और स्टाइलिश लगती है. इसमें एक पतली ब्रस्ड एल्युमिनियम अलॉय केस ख़ास है. पॉलिस्ड मेटालिक थ्री डी स्पीकर एवं हाइटेक टच एक्टिवेटेड इंटरफेस बोर्ड चमकदार और नए ढंग का है. ये दोनों नोटबुक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज-7 के अनुकूल बनाई गई हैं. एमएसआई के इन दोनों मॉडलों में इनबिल्ट थ्री डी इमेज प्रोसेसिंग के आर-पार समायोजन की सुविधा दी गई है, जिससे नए गेमर्स को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती. कंपनी ने इन ख़ास मॉडलों जीटी- 640 और जीटी-740 की क़ीमत क्रमश: 1,20,000 और 1,30,000 रुपये तय की है.

दिल्ली स्थित राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के डा. ए. के दीवान, डा.रजनी मुटनेजा और डा.जयगोपाल शर्मा

जागरूकता की पहल

बीती चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली स्थित राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट (आरजीसीआई) द्वारा कैंसर उन्मूलन जागरूकता अभियान हेतु एक बुकलेट-कैंसर से संबंधित आपके 100 प्रश्नों का जवाब और एक वीडियो फ़िल्म डीवीडी-जीवन की ओर लांच की गई. मरीजों को जागरूक एवं शिक्षित करने के उद्देश्य से कैंसर उन्मूलन जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की गई. इस अवसर पर डॉ. ए के दीवान (वरिष्ठ सलाहकार, सर्जिकल ऑनकोलॉजी, आरजीसीआई) ने कहा कि प्रति वर्ष लगभग 250 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और 76 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं. यदि समय रहते उचित क़दम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2030 तक विश्व भर में कैंसर के 260 लाख नए रोगी होंगे, जिनमें से 170 लाख मौत के मुंह में समा जाएंगे. उनमें भारत के अलावा मध्यम एवं निम्न आय वर्ग वाले देशों की संख्या अधिक होगी.डॉ. दीवान ने बताया कि कैंसर को 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक रोका जा सकता है. यह तभी संभव है, जब तंबाकू, मदिरापान, मोटापे, गतिहीन जीवनशैली एवं वायरल संक्रमण से होने वाले कैंसरों को परहेज और स्वस्थ व्यवहार से कम किया जाए. राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट भारत के अग्रणी स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है, जिसने शुरुआती दौर में कैंसर का पता लगाने वाले एक पूर्ण विभाग की स्थापना की. संस्थान की कैंसर निवारक प्रमुख डॉ. रजनी मुटनेजा के अनुसार, यदि शुरुआती दौर में ही स्क्रीनिंग की मदद ले ली जाए तो कैंसर की रोकथाम की जा सकती है. लोगों के बीच कैंसर के प्रति भयरहित माहौल तभी बनाया जा सकता है, जबकि समाज में पर्याप्त जागरूकता हो. इसके लिए सबको पील करने की ज़रूरत है.

रोशनी क़ायम रहे

बिजली कटौती की समस्या से आज देश का लगभग हर शहर-गांव परेशान है. शहरों में कई घंटों तो गांवों में कई-कई दिनों के लिए बिजली गुल हो जाती है. इस समस्या के निदान के लिए सेंडर इलैक्ट्रिक ने लेड आधारित इन डिया लाइटिंग सिस्टम लांच किया है. यह हाई इंड वैरियंट 90 लेड सोलर होम लाइटिंग सिस्टम बिजली गुल हो जाने पर आठ से 14 घंटे का बैकअप देता है. इसे एक बिजली आउटपुट से जोड़ने पर यह 11 वॉट की सीएफएल से 50 प्रतिशत और 60 वॉट के बल्ब से 90 प्रतिशत कम ऊर्जा खींचता है. इसे आसानी से दीवार पर टांगा जा सकता है और यह एक सामान्य कमरे को रोशन करने के लिए काफ़ी है. इसका हाई एंड वर्जन सीएफएल आधारित लाइटिंग सिस्टम से भी सस्ता होता है और लगभग 50,000 घंटों की लाइटिंग व्यवस्था देता है. यह लाइटिंग लैंप बाज़ार में नौ अलग-अलग वैरायटी में उपलब्ध है. 45 लेड आधारित बेसिक मॉडल की क़ीमत 550 रुपये है. यह एक बाहरी चार्जेबल बैट्री से संचालित होता है. मौक़े पर उपस्थित कंपनी के मार्केटिंग एवं अलायंस डायरेक्टर बर्नार्ड गोलस्टीन कहते हैं कि इन डिया देश के ग्रामीण घरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह बिजली कटने पर आठ से पंद्रह घंटों का बैकअप देगा. कंपनी ने आर एंड डी और निर्माण क्षमता को ख़ास तरीक़े से इस्तेमाल करके कम दामों पर बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है. सेंडर इलैक्ट्रिक के सीईओ एवं प्रेसिडेंट जीन पसकल ट्रिकॉयल कहते हैं कि इन डिया देश के विकास में अहम रोल अदा करेगा. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 500 मिलियन लोगों के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा.

लव योर सेल्फ

अपनी फिटनेस, स्मार्टनेस और सेक्सी ग्लैम बॉडी की बदौलत बॉलीवुड पर राज कर रही बिपाशा ने अपने फिटनेस मंत्र को अपने फैंस के साथ एक डीवीडी के ज़रिए शेयर किया है. बिपाशा की इस फिटनेस डीवीडी-लव योरसेल्फ की तरह शिल्पा शेट्टी की योग संबंधित सीडी कुछ समय पहले रिलीज़ हुई थी. ऐसा लगता है, बॉलीवुड के ड्रेसिंग सेंस, ज्वेलरी इमिटेशन के बाद फिटनेस और शेप्ड बॉडी का यह ट्रेंड आम लड़कियों को ख़ास बनाने के लिए जारी किया गया है.

आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अगर हम एक दिन बिपाशा जैसी फिट एवं स्मार्ट लड़कियों को अपने आसपास देखें. यह कहना ग़लत नहीं होगा कि यदि लड़कों के सिक्स पैक ऐब्स के ट्रेंड के स्टार आइकन हैंडसम जॉन अब्राहम हुए हैं तो लड़कियों में फिट एंड फैब्यूलस बॉडी का श्रेय उनकी गर्लफ्रेंड बिपाशा को जाएगा. बिपाशा की इस डीवीडी में 25 मिनट का वर्कआउट वीडियो है, जो लड़कियों को बिपाशा जैसी बॉडी पाने का सपना पूरा कर सकता है.

बिपाशा कहती हैं कि उक्त वर्कआउट्स लड़कियों के साथ लड़कों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं. अच्छा खाना एवं टाइम्ड वर्कआउट ही बॉडी की अच्छी शेप और फिटनेस का राज है. इसका अमल करके कोई भी फिट एंड फैब्यूलस हो सकता है. छह साल पहले के अपने अनुभवों को याद करते हुए बिपाशा कहती हैं कि सही मार्गदर्शन न होने की वजह से उन्होंने कई ग़लत एक्सरसाइज़ कर ली थीं, जिनकी वजह से उन्हें कई तरह की तक़लीफ़े होने लगी थीं. इसलिए लोगों से उनका कहना है कि वे किसी इंस्ट्रक्टर की देखरेख में वर्कआउट करें. जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या आर्थिक मजबूरियों की वजह से जिम या हेल्थ क्लब नहीं जा सकते हैं, उनके लिए बिपाशा ने ख़ासतौर से वर्कआउट डीवीडी रिलीज़ की है.

ई-बाइक्स में नया धमाल

इन दिनों महंगाई आसमान छू रही है और दूसरी चीज़ों के साथ-साथ पेट्रोल की क़ीमतों में भी दिन-प्रतिदिन उछाल दर्ज़ की जा रही है. ऐसे में यातायात महंगा होता जा रहा है. इसलिए सभी चाहते हैं कि उन्हें महंगाई की मार से बचाने वाला कोई वाहन विकल्प के रूप में मिले. ऐसी ही मांग के मद्देनज़र बाइक बनाने वाली विभिन्न कंपनियों ने कई श्रेणियों में ई-बाइक्स लांच की. उसी क्रम में अब लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज ने नई ई-बाइक ओमा स्टार लांच की है. इसकी ख़ासियत है कि यह प्रदूषण रहित है. कई चालकों, ख़ासकर लड़कियों को हेलमेट, लाइसेंस आदि चीज़ों से परेशानी महसूस होती रही है. इस ई-बाइक के साथ किसी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट आदि की बाध्यता नहीं है. लोहिया इंडस्ट्रीज की स्थापना कार्यसाधक, विश्वसनीय एवं सस्ते वाहन बनाकर शहरी और ग्रामीण इलाक़ों में यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से की गई थी. लांच की गई ई-बाइक स्कूली बच्चों, कामकाजी व घरेलू महिलाओं एवं वृद्ध लोगों के लिए एक आरामदायक और भय रहित वाहन है. जीरो एमिशन फीचर वाली यह ई-बाइक गैस या तेल के इस्तेमाल के बग़ैर सिर्फ़ बिजली द्वारा चार्ज कर देने से ही चलती है. 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने वाली ओमा स्टार से पहले कंपनी ओमा एवं फेम नाम से दो ई-बाइक पहले बाज़ार में उतार चुकी है. ओमा स्टार एरोडायनमिक स्टाइलिंग में बनी, स्लीक लाइंस एवं चलाने के सहज अंदाज़ के कारण आरामदायक और स्टाइलिश भी है. कंपनी ने भारतीय बाज़ार में ग्राहकों के लिए इसकी क़ीमत मात्र 25,999 रुपये तय की है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

पाकिस्तान में क्रिकेट की बदहाली का यह नया दौर है. खिलाड़ी से लेकर पदाधिकारी तक सभी इस बदहाली के विवाद में उलझे हुए हैं.

पाकिस्तानी क्रिकेट में भूचाल

लगातार नौ मैचों में हार. यह किसी भी टीम के मनोबल को पस्त करने के लिए काफ़ी है. यही कहानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है. अभी हाल में पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, जहां उसे तीन टेस्ट, पांच एकदिवसीय और एक टी–20 मैच खेलना था. यानी कुल नौ मैच. इन सभी मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को धूल चटा दी. पाकिस्तान की टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई. इसके बाद तो पाकिस्तानी क्रिकेट में जो भूचाल आया, वह बिल्कुल ही तयशुदा था. सबसे पहले चयनकर्ता इक़बाल क़ासिम को अपना पद छोड़ना पड़ा. इसके बाद अधिकारियों की विदाई शुरू हो गई. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के महानिदेशक जावेद मियांदाद ने भी अपने पद से इस्तीफ़ा देने की धमकी दे दी. यही नहीं, अब तो इस्तीफ़ा देने की धमकी देने वालों की जमात में पाक टीम के गेंदबाज़ी कोच वक़ार यूनिस भी शामिल हो गए हैं. इन सभी का मानना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की कद्र कोई नहीं करना चाहता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के जो कर्ताधर्ता हैं, सारी बातें वही तय करते हैं. पीसीबी अध्यक्ष वही बनता है, जिस पर सरकार का वरदहस्त होता है. यानी पाकिस्तान में क्रिकेट को खिलाड़ी या पीसीबी नहीं, बल्कि वहां की सरकार चला रही है. इन्हीं वजहों से सभी लोग अपने पद से इस्तीफ़ा देने की धमकी दे रहे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट के साथ विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहा. कंगारुओं के साथ आख़िरी एकदिवसीय में कप्तानी का ज़िम्मा स्टार बल्लेबाज़ शाहिद अफरीदी को सौंपा गया. मैच जीतने के चक्कर में अफ़रीदी ने गेंद चबाना शुरू कर दिया. यानी मामला बॉल टेंपरिंग का बन गया. अफरीदी पर दो टी–20 मैच की पाबंदी भी लगाई गई. ऑस्ट्रेलियाई शृंखला के लिए बनाए गए कप्तान मोहम्मद युसूफ ने अफ़रीदी की इस हरकत को देश को बदनाम करने वाली हरकत करार दिया.

पाकिस्तानी टीम किसी शृंखला में एक भी मैच न जीत पाए, ऐसे में खिलाड़ियों में फूट न पड़े, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है. पिछला इतिहास भी कुछ इसी तरह का रहा है. फ़िलहाल ऑस्ट्रेलियाई दौरे से वापसी के बाद मोहम्मद युसूफ ने एक पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू दिया. युसूफ ने बताया कि *पाक टीम के कई खिलाड़ी टीम का साथ नहीं दे रहे थे और टेस्ट मैच में हार के बाद कुछ खिलाड़ी ख़ुद को कप्तान के तौर पर पेश करने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि मैं (युसूफ) कप्तान नहीं रह पाऊंगा.* इन बातों ने पाकिस्तानी क्रिकेट में आए भूचाल में इज़ाफ़ा ही किया. इसके अलावा कंगारुओं से बुरी तरह मुंह की खाने के बाद कई पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी कहते नज़र आ रहे हैं कि यह पाकिस्तानी टीम की अभी तक की सबसे बड़ी हार है. लेकिन मसला पाकिस्तानी टीम की हार तक ही सीमित नहीं है. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और बोर्ड की जो दुर्दशा हुई है, उसकी नींव बहुत पहले ही पड़ चुकी थी. दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाने के पहले यूनिस खान को कप्तान के पद से हटाया गया. ग़ौरतलब है कि यूनिस ने ही पाक को टी–20 के विश्वकप का खिताब दिलाया. लेकिन पीसीबी में चल रही अंदरूनी राजनीति की वजह से उन्हें श्रीलंका दौरे के बाद कप्तानी से इस्तीफ़ा देना पड़ा. यानी इन सभी विवादों ने पाकिस्तान की तरह पाकिस्तानी क्रिकेट को भी काफ़ी नुक़सान पहुंचाया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

हॉकी विश्वकप में भारत से कितनी उम्मीद?

भारतीय हॉकी टीम ने कोच बदलने के साथ ही अपनी खेल शैली भी बदल ली है. कोच ब्रासा भारतीय टीम को आधुनिक शैली के हिसाब से हॉकी के गुर सिखा रहे हैं. यानी वह पारंपरिक भारतीय शैली के अलावा भारतीय खिलाड़ियों को यूरोपीय शैली के हिसाब से भी प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि यूरोपीय देशों को भारतीय टीम करारा जवाब दे सके. लेकिन, इतने कम समय में खिलाड़ी ख़ुद इस मुताबिक़ कितना ढल पाए हैं, यह तो शृंखला शुरू होने के बाद ही पता चलेगा. इसके साथ ही यह सवाल भी सामने आता है कि आख़िर भारतीय टीम विश्वकप के लिए कितना तैयार है? क्योंकि विश्वकप मुक़ाबलों में भारतीय हॉकी टीम का रिकॉर्ड बेहद घटिया रहा है.

वर्ष 1975 में भारत ने हॉकी विश्वकप का ख़िताब अपने नाम किया था. यह वह दौर था, जब हॉकी में भारत की तूती बोलती थी. लेकिन, उस शानदार जीत को 35 बरस हो चुके हैं और दोबारा विश्वकप ख़िताब भारत की झोली में नहीं आ सका है. अब एक बार फिर हॉकी का विश्वकप 28 फरवरी से शुरू होने वाला है. दुनिया की 12 दिग्गज टीमें मैदान में होंगी और दांव पर होगा विश्वकप का ख़िताब. भारतीय हॉकी के स्वर्णिम इतिहास की वजह से सभी की उम्मीदें भारत पर टिकी हुई हैं. ऐसे में यह ध्यान देना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय टीम की तैयारियां इस विश्वकप के लिए कैसी हैं? क्या भारत इस बार अपनी ज़मीन पर 35 साल के लंबे वनवास को ख़त्म कर पाएगा? भारतीय हॉकी में आया हालिया भूचाल काफी कुछ कह जाता है.

विश्वकप के शुरू होने के पहले भारतीय हॉकी ने कई मुश्किलों का सामना किया. खिलाड़ियों की बग़ावत और कोच को लेकर हुई किचकिच से भारतीय हॉकी की ख़ूब किरकिरी हुई. जब यह दोनों मामले शांत हुए तो कप्तानी को लेकर खींचतान होने लगी. कोच ब्रासा प्रभजोत सिंह को कप्तान के तौर पर चाहते थे, जबकि हॉकी इंडिया ने विश्वकप के लिए कप्तान के तौर पर राजपाल सिंह के नाम की घोषणा की. यानी भारतीय टीम ने विश्वकप की तैयारियों की अपेक्षा ज्यादा वक्त विवादों में उलझे रहने में गंवाया. अब जबकि विश्वकप शुरू होने में थोड़ा समय बचा है तो कोच से लेकर हॉकी टीम के पदाधिकारी तक इन विवादों से हुए नुक़सान की भरपाई में लग गए हैं. भरपाई का रास्ता भी उन्होंने बेहद दिलचस्प निकाला है. टीम की तैयारियों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चाहे कोच हों या खिलाड़ी सभी कहने लगे हैं कि टीम विश्वकप मुक़ाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है.

खैर, भारतीय हॉकी टीम 35 साल के विश्वकप खिताब के वनवास को ख़त्म कर पाती है या नहीं, यह उसके प्रदर्शन और विश्वकप शुरू होने पर ही पता चल पाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 22 फरवरी–28 फरवरी 2010

शाहिद और करीना आख़िरी बार फ़िल्म *जब वी मेट* में दिखाई दिए थे. इसी फ़िल्म के दौरान दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ था. अब दोनों जल्द ही फ़िल्म *मिलेंगे मिलेंगे* में दिखाई देंगे.

कॉपी कैट नहीं हूं: जेनेलिया

जाने तू या जाने ना की कामयाबी का जो फ़ायदा इमरान खान को मिला, वह शायद जेनेलिया डिसूजा को नहीं मिला. हालांकि दोनों ही इस फ़िल्म से लाइम लाइट में आए, दोनों को ही बड़ी-बड़ी फ़िल्में मिलीं, पर *लाइफ़ पार्टनर* और *डांस पे चांस* की असफलता से एक बार फिर जेनेलिया का संघर्ष का दौर शुरू हो गया है. हाथ में ज़्यादा फ़िल्में न देख उन्होंने विज्ञापनों में क़िस्मत आज़माना शुरू कर दिया. मानों इतना ही काफी नहीं था, कंगाली में आटा गीला की तर्ज़ पर एक और विवाद ने उन्हें परेशान कर रखा है. यह विवाद है उनकी ड्रेस को लेकर. दरअसल हुआ यह कि हाल ही में एक पार्टी के दौरान जेनेलिया हूबहू वैसी ही ड्रेस पहन कर पहुंच गईं, जो एक मैगज़ीन के कवर पर छपे फोटो में प्रियंका चोपड़ा ने पहन रखी थी. फिर क्या था! वहीं पर एक मीडियाकर्मी ने तपाक से उनसे पूछ लिया कि वह प्रियंका चोपड़ा की कॉपी क्यों कर रही हैं? इस बात से वह झेंप गईं और उन्हें सफ़ाई देनी पड़ी कि वह जानबूझ कर ऐसा नहीं कर रही हैं. इससे पहले भी उनके हेयर स्टाइल और लुक में प्रियंका से काफ़ी समानता दिखती रही है. अब सच्चाई चाहे जो भी हो, आप इसे मात्र संयोग ही समझें!

मेरे और प्रियंका चोपड़ा के लुक और हेयर स्टाइल में समानता हो सकती है, पर मैं कॉपी कैट नहीं हूं.

रिमी को दमदार स्क्रिप्ट का इंतज़ार

फ़िल्म *बागवान* में छोटी सी भूमिका निभाकर करियर की शुरूआत करने वाली चुलबली बंगाली बाला रिमी सेन ने थोड़े समय में ही बॉलीवुड में अपनी ख़ास जगह बना ली है. लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी रिमी हिंदी और बांग्ला, दोनों ही भाषा की फ़िल्मों में काम कर रही हैं. पेश है चौथी दुनिया संवाददाता *रीतिका सोनाली* से हुई बातचीत के कुछ अंश:-

अक्षय कुमार, जॉन, अभिषेक और अमिताभ बच्चन के साथ फ़िल्में करने के बाद भी आप सहायक भूमिकाओं के दायरे में सिमट कर रह गई हैं. ऐसा क्यों?

मैंने वैसी ही फ़िल्में की हैं, जिनमें मेरा किरदार अच्छा है. मेरी भूमिका को लोगों ने पसंद भी किया है. दमदार स्क्रिप्ट वाली फिल्मों का अभी इंतजार कर रही हूं. मिला तो मेरे क़दम भी अवश्य ही आगे बढ़ेंगे.

आपकी ज़्यादातर फ़िल्में हंसी मजाक वाली हैं? क्या कॉमेडी फ़िल्मों से ही जुड़े रहने की ख्वाहिश है?

नहीं, दरअसल अच्छी स्क्रिप्ट वाली मेरे पास अब तक जितनी भी फ़िल्मों के ऑफर आए, ज़्यादातर कॉमेडी ही थे. इसलिए इससे अलग करने का मौक़ा ही नहीं मिला. इस इमेज से निकलने की कोशिश में *जॉनी गद्दार* फ़िल्म में मैंने नेगेटिव शेड का कैरेक्टर प्ले किया. आगे भी अलग अगल तरह के किरदार निभाने की मेरी कोशिश जारी रहेगी.

खाली वक़्त में क्या कर रही हैं?

हाल के दिनों में किताब पढ़ने में मेरी दिलचस्पी बढ़ी है. फ़िलहाल सिडनी शेल्डन की बुक स्टार शाइन डाउन पढ़ रही हूं. इसके अलावा बोरियत महसूस होने पर घूमने निकल जाती हूं. स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड की कुछ जगहों पर जाना मुझे बेहद पसंद है. मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी पसंद हैं.

आप बंगाली पृष्ठभूमि से हैं. बॉलीवुड में करियर शुरू करने के दरम्यान भाषा संबंधी परेशानी नहीं हुई?

बिल्कुल, बल्कि आज तक होती है. फरार्टेदार हिंदी बोलने में मुझे आज भी कठिनाई होती है. लेकिन स्क्रीन पर यह कमी नज़र नहीं आती है. दरअसल वह हमारे काम का हिस्सा होता है, और उस पर काफ़ी मेहनत की गई होती है.

शाहिद करीना मिलेंगे-मिलेंगे

आजकल हर जगह सैफीना यानी सैफ और करीना के रोमांस के चर्चे हैं. शाहिद-करीना की जोड़ी को लोग भुला चुके हैं. जब कभी भी शाहिद और करीना का किसी कार्यक्रम में सामना हुआ तो वे मीडिया की नज़रों से बचते रहे. आख़िरी बार दोनों फ़िल्म *जब वी मेट* में दिखाई दिए थे. उसी फ़िल्म के दौरान ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था. तब शायद ही किसी ने सोचा था कि दोनों फिर कभी एक साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते दिखाई देंगे. लेकिन, अब ऐसा होने जा रहा है. *जब वी मेट* की यह जोड़ी जल्द ही फ़िल्म *मिलेंगे-मिलेंगे* में इश्क़ लड़ाती नज़र आएगी. सतीश कौशिक की यह फिल्म रोमांटिक ड्रामा है. आप सोचेंगे कि एक बार फिर से शाहिद और करीना में कुछ पक रहा है, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है. छोटे नवाब और करीना के बीच सब ठीकठाक चल रहा है. दरअसल *मिलेंगे- मिलेंगे* काफ़ी समय से अटकी हुई थी. यह फ़िल्म दोनों ने तब साइन की थी, जब दोनों का रोमांस परवान पर था. पर बोनी कपूर की इस फ़िल्म में कई समस्याओं के चलते देरी होती रही और फ़िल्म लटकती चली गई. अब अच्छी ख़बर यह है कि फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा हो चुका है और दोनों ही लीड स्टार प्रमोशन के लिए तैयार भी हैं. अब भले ही रियल लाइफ में दोनों अलग हो चुके हों, पर रील लाइफ में तो *मिलेंगे-मिलेंगे* न!

कैटरीना का एनिमेटेड अवतार

बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन कैट अर्थात कैटरीना के जलवे आपने हिंदी फ़िल्मों में ख़ूब देखे होंगे, लेकिन जल्दी ही आप उन्हें बच्चों की एनिमेशन फिल्म में नखरीली गुड़िया के किरदार में देखेंगे. अनिल गोयल द्वारा निर्देशित थ्री डी प्रारूप में 26/11 पर आधारित ऐनिमेटेड फ़िल्म *कैकर्स* में नन्ही गुड़िया कैटरीना सी दिखेंगी. इस एनिमेशन फ़िल्म में उन्होंने काफ़ी प्रयोग किए हैं. यह पहली ऐसी ऐनिमेशन फ़िल्म है, जो पूरी तरह से भारत में बनाई जाएगी. इसकी कहानी 26/11 के हमले के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें एक 15 साल का बच्चा मुख्य किरदार निभा रहा है, जिसे सुपर पावर से लैस दिखाया गया है. यह सुपर ब्वॉय अपने सुपर पावर से 26/11 के हमलावरों के छक्के छुड़ा देता है. फ़िल्म की हीरोइन कैटरीना की ऐनिमेटेड रूपांतरण है, जिसे निर्देशक अनिल गोयल ने कैटरीना को ध्यान में रखकर बनाया है. उनका कहना है कि कैटरीना बड़ों के साथ बच्चों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हैं. यही वजह है कि उन्होंने अपनी हीरोइन कैट को कैटरीना जैसा लुक देने की कोशिश की है. उनका कहना है कि अभी तक हमारे बच्चे सिर्फ़ विदेशी कैरेक्टर ही कार्टून में देखते रहे हैं, लेकिन इस बार वे देशी कैरेक्टर के साथ अपने देश की कहानी भी देखेंगे. अनिल गोयल चाहते थे कि फ़िल्म की हीरोइन कैट के कैरेक्टर को चेहरे के साथ कैटरीना की आवाज़ भी दी जाए, पर कैटरीना की व्यस्तता की वजह से बात नहीं बन सकी. जब इस बाबत कैटरीना से बात की गई तो वह चहकते हुए बोलीं कि यह सब मेरे लिए सपने जैसा है. बचपन में मैं हमेशा अपनी बहनों के साथ कार्टून कार्यक्रम देखने के लिए लड़ती रहती थी. हम सब लोगों में कार्टून और एनीमेशन को लेकर गहरा क्रेज़ था. किसी गेम या कार्टून में मेरा भी एनीमेशन बनेगा, ऐसा मैने कभी सोचा नहीं था. हालांकि उन्हें इस बात का अफ़सोस है कि वह अपने कैरेक्टर के लिए आवाज़ नहीं दे पाएंगी. फ़िलहाल *कैकर्स* की कैट को फ़िल्म *कलयुग* की हीरोइन स्मायली सूरी अपनी आवाज़ दे रही हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अब स्टार का बहनें सीरियल

स्टार प्लस चैनल अभी तक सास-बहू थीम पर आधारित धारावाहिकों के जरिए टीवी इतिहास में कई रिकॉर्ड कायम कर चुका है. लेकिन, इन धारावाहिकों को ज़रूरत से ज़्यादा खींचे जाने की वजह से दर्शकों ने इनसे पीछा छुड़ाना ही बेहतर समझा. इसी बीच कलर्स और एनडीटीवी इमेजिन जैसे नए चैनल कई नए कांसेप्ट लेकर धारावाहिकों के बाजार में उतरे. इन सबके प्लॉट सास-बहू वाले न होकर *बेटियां, लाडली, लाडो* एवं *बालिका वधू* जैसे थे, जिनमें लड़कियों और बच्चों को केंद्र में रखकर कहानियां लिखी गई थीं. इनसे अच्छी टीआरपी भी मिली. बस इसी की देखादेखी स्टार प्लस भी चार बहनों पर आधारित सीरियल लेकर आ रहा है. इसका नाम *बहनें* है. स्टार इंडिया के कार्यकारी वाइस प्रेसिडेंट अनुपम वासुदेव के अनुसार, बहनों का कथानक सम्मोहक है. इसमें चार बहनों की जिंदगी में आने वाली खुशियों, पीड़ा और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई है. इन चार बहनों की भूमिकाएं शिजु कटारिया, अदा खान, ओजस्वी ओबेराय एवं अलीशा खान ने निभाई हैं. इस शो का निर्माण जेडी मजीठिया के हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस द्वारा किया गया है. देखते हैं, स्टार का यह नया प्रयोग क्या रंग लाता है!

फ़िल्म प्रीव्यू

अतिथि तुम कब जाओगे

सत्यजीत रे की एक बंगाली फ़िल्म थी *आगंतुक*. इस फ़िल्म में उत्पल दत्त एक ऐसे मेहमान की भूमिका में थे, जो अचानक कई सालों बाद अपनी दूर की भतीजी के यहां डेरा डाल देता है, जबकि परिवार के बाक़ी सदस्यों को उसके आ जाने से परेशानी होती है. उसी थीम पर अश्विन धीर ने मॉडर्न कॉमिक वर्जन *अतिथि तुम कब जाओगे* बनाया है. फ़िल्म में अजय देवगन, परेश रावल, कोंकणा सेन शर्मा प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आएंगे. इस कॉमेडी फ़िल्म में उत्पल दत्त का किरदार निभाया है परेश रावल ने. परेश अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस हैं. वहीं अजय देवगन एवं कोंकणा सेन उस विवाहित युगल के रोल में हैं, जो इस अनचाहे मेहमान के आने से परेशान है. पुनीत एक लेखक है, जो टेलीविजन के लिए लिखता है और एक दिन फ़िल्मों के लिए लिखने के अवसर का इंतजार कर रहा है. वह मुंबई में अपनी पत्नी मुनमुन एवं बच्चे के साथ रहता है. तभी अचानक उसे एक फ़िल्म के लिए लिखने का मौक़ा मिल जाता है. पूरा परिवार खुशी मनाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि उसी वक़्त पुनीत के दूर के चाचा जी (लंबोदर वाजपेयी) की इंट्री होती है. यह कोई आम रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ घर में डेरा जमाने आए होते हैं. अपने देशी रहन-सहन और अंदाज़ से वह सब पर भारी हैं. उन्हें घर से जल्दी विदा करने के लिए पुनीत एवं मुनमुन रोज नए तरीक़े अपनाते हैं और चाचा बड़ी होशियारी से उनकी कोशिशों पर पानी फेर देते हैं. इसी अंदर-बाहर के खेल में कई हास्यास्पद उठापटक होती है. कहानी में हास्य के साथ-साथ आज के आधुनिक दौर में रिश्तों की बदलती परिभाषा का चित्रांकन भी किया गया है. वाइड फ्रेम, वार्नर ब्रदर्स के बैनर तले बनी इस फ़िल्म का संगीत दिया है प्रीतम ने. हिमेश के एक साल में सबसे ज़्यादा फ़िल्मों में संगीत देने के रिकॉर्ड को तोड़ने की वह क़सम खा चुके हैं. गीत हैं इरशाद कामिल के. यह मॉडर्न फेमिली कॉमिक ड्रामा 5 मार्च को सिनेमाघरों में आएगा.

रोड मूवी

अभय देओल ने छोटे से करियर में अपना एक खास फैन ग्रुप बना लिया है. उनकी फिल्मों में भले ही कमर्शियल मैटर न मिले, पर सिनेमाई संतुष्टि ज़रूर होती है. 5 मार्च को रिलीज हो रही *रोड मूवी* भी लीक से परे एक ऐसी ही फ़िल्म है. कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुकी इस फ़िल्म की कहानी एक लापरवाह युवक विष्णु (अभय) की है, जो अपने पिता के डूबते बिजनेस को बचाने के लिए एक एंटिक पीस बेचने के लिए निकलता है. जिस ट्रक में वह सफर कर रहा होता है, उसमें पुराने ज़माने के सिनेमा का साजोसामान है. इस सफ़र में एक पुराना आर्टिस्ट (सतीश कौशिक) और तनीशा भी शामिल है. सारे लोग रेगिस्तान में पानी एवं एक मेले की तलाश में पुलिसवालों और माफिया के चंगुल में फंस जाते हैं. अब उनके बचने का एक ही रास्ता है और वह है, उनके ट्रक में पड़ा पुराना फ़िल्म प्रोजेक्टर एवं फ़िल्में. शर्त भी दिलचस्प है. अगर फ़िल्म उन माफियाओं को पसंद आई तो वे ज़िंदा रहेंगे और अगर बोरिंग हुई तो सामने मौत है. इसी अजीबोग़रीब स्थिति में फंसे लोगों की अनोखी कहानी है रोड मूवी. यह पहली भारतीय फ़िल्म है, जिसका विंटर गार्डेन थिएटर में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है. निर्देशन देव बेनेगल ने किया है और संगीत माइकल ब्रूक का है.

चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

दिल्ली, 22 फरवरी-28 फरवरी 2010

प्रवेशांक

आयकर छापामारी के बाद बरामद रुपये.

स्वर्णिम नहीं, भ्रष्टतम राज्य कहिए

मध्य प्रदेश के लिए यह दुःख की बात है कि उसका नाम भ्रष्ट प्रदेशों की सूची में सबसे अव्वल है. शीर्ष पदों पर रहे अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं. सरकार की बदनामी हो रही है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर ज़रा भी चिंतित नज़र नहीं आती है. ऐसे में प्रदेश के भविष्य का तो बस भगवान ही मालिक है.

संध्या पांडेय

मध्य प्रदेश में प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के बीच जन्म लेता है, भ्रष्टाचार के बीच ही पलता और बड़ा होता है और भ्रष्टाचार को भोगते हुए मर भी जाता है. लेकिन मरने के बाद भी भ्रष्टाचार से उसका पीछा नहीं छूटता. यह किसी दार्शनिक का चिंतन वाक्य नहीं है, बल्कि मध्यप्रदेश के नागरिकों का भोगा हुआ यथार्थ है.

ट्रासपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया के अध्ययन और सर्वेक्षण में वर्ष 2007 के बाद से हर साल मध्य प्रदेश को देश के चार भ्रष्टतम राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाता रहा है. इसकी जानकारी सरकार और समूचे तंत्र को है. सत्ता विरोधी दल इसका जमकर प्रचार भी करते रहे हैं. लेकिन हाल ही में जब आयकर विभाग ने दो बड़े आईएएस और कुछ दूसरे आला अधिकारियों के घरों और दूसरे ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों रुपयों की अघोषित नकद राशि, अकूत सोना, चांदी और जेवरात तथा भारी लेन-देन के काग़ज़ात ज़ब्त किए और देशभर में भ्रष्टाचार के लिए मध्य प्रदेश की बदनामी होने लगी, तो राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ी मासूमियत से कहा कि राज्य के प्रशासन की छवि बदलनी होगी. यह पहला अवसर नहीं है जब भारत सरकार के आयकर विभाग ने राज्य सरकार के किन्हीं अफ़सरों के यहां छापामार कर करोड़ों रुपये की धन संपत्ति का पता लगाया है. इस घटना के कुछ माह पूर्व ही राज्य के डॉ. योगीराज शर्मा, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं और उनके सहयोगियों पर भी आयकर विभाग की छापामारी हुई थी और इन छापों में भी करोड़ों रुपये तिज़ोरियों से निकलकर उजाले में आए थे, लेकिन आश्चर्यजनक तरीक़े से डॉ. शर्मा फिर से पदासीन होने में सफल हो गए. यह अलग बात है कि बाद में उन्हें फिर से पद से हाथ धोना पड़ा.

दो आईएएस अधिकारी, कुछ बड़े इंजीनियर और स्वास्थ्य विभाग के संचालक तो पकड़ में आ गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का साम्राज्य इतना व्यापक और मज़बूत है कि यह पूरे राज्य प्रशासन का ऊपर से नीचे तक अपने क़ब्ज़े में कर रखा है. भ्रष्टाचार की जड़ें गहराई तक जमी हुई हैं. नगरीय संस्थाओं से जन्म प्रमाण पत्र लेने, स्कूलों में नामांकन कराने, पढ़ाई करने, व्यवसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी और पदोन्नति पाने, स्थानांतरण कराने, राशन कार्ड बनवाने, मकान बनवाने और अस्पताल में इलाज कराने से लेकर मृत्यु तक आम आदमी को इस राज्य में जगह-जगह भ्रष्टाचार के पोषक देवताओं को भेंट चढ़ानी होती है. यहां तक कि मृत्यु के बाद सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी अफ़सर बाबू को नकद नारायण देनी होती है. सरकारी अमला इतना निर्दयी और भ्रष्ट हो गया है कि अपने किसी साथी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा या बच्चों से भी रिश्वत वसूले बिना मृतक कर्मचारी की फैमिली पेंशन या अनुकंपा नियुक्ति के मामले नहीं निपटाए जाते हैं. सरकारी अस्पतालों में प्रसव सुविधा की व्यवस्था है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के कारण गर्भवती महिलाओं को दाख़िल ही नहीं किया जाता है. ऐसी हालत में कई बार ग़रीब महिलाओं ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया है. मीडिया में इस बारे में ख़बरें आने पर कभी-कभी मामूली कार्रवाई भले हुई हो, लेकिन इससे व्यवस्था में कोई सुधार नहीं देखने को मिला.

हालत इतनी ख़राब है कि शासन ने जिन्हें चौकीदारी सौंपी थी, वे ही चोर निकले. मुख्यमंत्री मासूम बनकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मुख्य सचिव भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोगों को धमकियां दे रहे हैं और जनता हैरान परेशान है. यह भाजपा शासित मध्यप्रदेश का हाल है, जहां अफ़सरों और राजनेताओं पर मामले दर्ज़ किए जाते हैं, करोड़ों रुपये उनके घरों से बरामद किए जाते हैं और बाद में मामला रफ़ा-दफ़ा भी कर दिया जाता है. मध्यप्रदेश भ्रष्टाचार के अलावा आपराधिक मामलों में भी भारत में अपनी बदनाम छवि बनाए हुए है. इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और उसके मुख्यमंत्री स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का प्रचार करने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करते हैं.

मध्यप्रदेश के आईएएस अफ़सरों के बैंक लॉकर से हाल के दिनों में करोड़ों रुपये की नकदी और जेवरात की बरामदगी हो चुकी है. जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी इन अधिकारियों ने कल्याण कार्यक्रमों से ही इतना अर्जित कर लिया, जितना संभवत: मध्य प्रदेश सरकार के किसी एक विभाग का वार्षिक बजट होगा. राज्य के 50 से अधिक अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें राज्य शासन के पास वर्षों से लंबित हैं. शिकायतों के बावजूद सरकार इन अधिकारियों को पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के बाद के सभी लाभ देती है.

वर्तमान में राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीनू जोशी और अरविंद जोशी के घर पड़े आयकर विभाग के छापे ने मध्यप्रदेश के भ्रष्टाचार को फिर से सार्वजनिक कर दिया. टीनू जोशी महिला एवं बाल विकास विभाग में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत पोषण आहार कार्यक्रम में ठेकेदारों के माध्यम से करोड़ों रुपये का घोटाला करा पाने में सफल रही. इस प्रकरण में टीनू जोशी पर तो कार्रवाई हुई पर उनकी सहयोगी संस्था मध्यप्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन पर शिकंजा अभी तक नहीं कसा जा सका है. टीनू जोशी की अवैध कमाई का रास्ता एग्रो कॉरपोरेशन से होकर ही गुज़रता था, पर राज्य शासन अभी तक एग्रो निगम के प्रबंध संचालक और उनके अधिकारियों पर मेहरबान क्यों हैं, यह समझ से परे है.

शिवराज चौहान
(मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश)

अवनि वैश्य
(मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश)

"भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए बनाए गए तंत्र में कई कमज़ोरियां हैं. किसी भी राजनेता या अफ़सर के विरुद्ध व्यायालय में चालान प्रस्तुत किए जाने के पहले शासन की अनुमति अनिवार्य मानी जाती है. शासन कभी भी इसकी अनुमति नहीं देता है."

अरविंद जोशी ने जल संसाधन विभाग में पांच वर्ष की लंबी अवधि कैसे गुज़ार ली, यह जांच का विषय हो सकता है. जोशी की तरह राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग में पदस्थ एक अधीक्षण अभियंता भी लंबे समय से एक ही स्थान, भोपाल, में जमे हुए है. शासन को उनकी करतूतों के बारे में भी पूरी ख़बर है, परंतु अभी तक ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की इच्छा राज्य सरकार की नज़र नहीं आती.

मध्य प्रदेश वर्ष 1998 के बाद से ही भ्रष्टाचार के मामलों में अव्वल है. इस दौरान राज्य का राजनैतिक तंत्र अफ़सरशाही के साथ मिलकर एक नए कॉरपोरेट कल्चर में काम करना सीख चुका था. 1998 से 2003 तक मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले आयकर, ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की छानबीन के दौरान बार-बार सामने आते रहे. मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाली उमा भारती ने भ्रष्टाचार की इस अपसंस्कृति का विकेंद्रीकरण प्रारंभ कर दिया. यह अपसंस्कृति वर्ष 2010 तक आते-आते ग्राम पंचायत के स्तर तक फैल गई. प्रशासन के विकेंद्रीकरण के लिए जिस पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, वह व्यवस्था मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण का सशक्त माध्यम बन गई है. भारत सरकार और राज्य सरकार गांवों के विकास और ग्रामीणों के उत्थान के लिए हर साल करोड़ों रुपये पंचायतों के माध्यम से ख़र्च करती है, लेकिन शायद ही कोई गांव ऐसा हो, जहां विकास कार्यों और जनकल्याण के कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार न हुआ हो. राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पोषण आहार कार्यक्रम, स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम सभी में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है. इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा ज़िला प्रशासन सभी स्वीकार करते हैं. लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने और जनता के धन का जनता के लिए उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए कहीं कोई प्रयास होता दिखाई नहीं दे रहा.

राज्य में लोकायुक्त, पुलिस, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई जैसी संस्थाएं भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तैनात हैं. हर साल सैकड़ों मामले पकड़ में आते हैं और कार्रवाई भी होती है, लेकिन सारा कुछ भ्रष्टाचार के महासागर में छोटी मछलियों का शिकार करने के मनोरंजक खेल जैसा ही है. पटवारी, पुलिस का सिपाही, दफ़्तर का क्लर्क, सब इंजीनियर जैसे तीसरे और चौथे दर्ज़े के वे कर्मचारी भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं, जिनके ऊपर प्रशासन और राजनीति में कोई गॉड फादर नहीं होता है. लेकिन मगरमच्छ तो पूरी बिरादरी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर तिज़ोरी भरते रहते हैं. कमाई वाले विभागों के प्रमुख सचिव, अपने मातहत विभागों के विभाग प्रमुख से लेकर ज़िला प्रमुख तक की नियुक्ति अपने हिसाब से अपने लोगों को उपकृत करते हुए करता है और फिर मुख्यमंत्री और मंत्री से मेलजोल करके वर्षों अपने पद पर जमा रहता है.

भ्रष्टाचार के इन मामलों की जांच के लिए बनाए गए इस तंत्र में कई कमजोरियां हैं. किसी भी राजनेता या अफ़सर के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए जाने के पहले शासन की अनुमति अनिवार्य मानी जाती है. शासन कभी भी इसकी अनुमति नहीं देता है और भ्रष्टाचार के विरूद्ध चलने वाली कोई भी मुहिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाती है.

अशोक कुमार राय, एम ए ख़ान, महेंद्र सिंह भिलाला, संजय दुबे, एल के त्रिवेदी कुछ ऐसे नाम हैं, जिनके विरूद्ध मामले विचाराधीन हैं. एन के शुक्ला, एस के जग्गी, राजमणि शुक्ला, बीबी खरे, पीपी श्रीवास्तव, जेपी खिंची, जालमसिंह, श्रीराम मेश्राम, ओपी चौधरी, राज्य प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों में शामिल हैं जिनकी जांच उनके रिटायरमेंट के बाद भी जारी है. इसके अतिरिक्त वर्तमान मंत्री परिषद के आधे से अधिक सदस्य राज्य शासन के आधा सैकड़ा से अधिक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में लिप्त पाए गए हैं. मध्यप्रदेश का दुर्भाग्य है कि सुशासन का दावा करने वाली सरकारें राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर पाने में नाकाम रहीं.

भ्रष्टाचार को राजनैतिक सत्ता ही बढ़ावा देती है. राजनीति में धनबल के बढ़ते प्रभाव के कारण हर नेता पैसा कमाना अपना प्रथम कर्तव्य मानता है. चूंकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अधिकारियों की पदस्थापना का अधिकार है, इसलिए वे अपने अनुकूल और अपने लिए सुविधाजनक अधिकारी को मनचाहे पद पर नियुक्त करने के लिए नियम, परंपरा की खुली अवेहलना करते हैं. मध्यप्रदेश में यही हो रहा है. जिन वरिष्ठ अधिकारियों की जनता के बीच ईमानदार, न्यायप्रिय और कठोर प्रशासक की छवि रही है, उन्हें दरकिनार कर, भ्रष्ट लोगों को मुख्य सचिव, महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, ज़िला कलेक्टर आदि पदों पर नियुक्त किया गया है. इस बार तो हद ही हो गई, जब मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए नियम और परंपरा को अंगूठा दिखाते हुए शासन ने 1974 बैच के आईएएस अफ़सरों की वरीयता की अनदेखी कर 1975 बैच के एक जूनियर अधिकारी को मुख्य सचिव बना दिया. आईएएस एसोसिएशन में भी भ्रष्टाचार को लेकर चिंता व्यक्त की गई है. एसोसिएशन प्रशासनिक अधिकारियों की छवि बिगड़ने को लेकर शर्मसार है. तमाम आईएएस अफ़सरों को शासन से भी शिकायत है कि अपने लाभ के लिए राजनेता नियम क़ायदों और परंपरा को धता बताकर मनमानी करते हैं. इससे प्रशासन का अनुशासन भंग होता है और भ्रष्टाचार भी फलता-फूलता है.

feedback@chauthiduniya.com

कहां गया 17 हज़ार क्विंटल अनाज?

आदिवासी बहुल ज़िला उमरिया में अनाज घोटाले का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है. यहां विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के निमित्त आया लगभग 17 हज़ार क्विंटल अनाज वितरण के बजाय ग़ायब कर दिया गया. इस अनाज की क़ीमत एक करोड़ रुपये बताई जाती है. हालांकि मामले की प्रारंभिक जांच में दो लिपिकों को दोषी पाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इस घोटाले में कई अन्य और ज़िम्मेदार लोगों के शामिल होने की आशंका व्यक्त की जा रही है.

उमरिया में वर्ष 2003–04 और वर्ष 2005–06 में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का 16754 कुंतल गेहूं और चावल आश्चर्यजनक रूप से ग़ायब हो गया. इसमें 13778 क्विंटल चावल और 2972 क्विंटल गेहूं था. मालूम हो कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, सूखा राहत और काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के तहत पंचायतों को सीधे अनाज उपलब्ध कराया जाता है. गायब हुआ अनाज उपरोक्त कार्यक्रमों से संबंधित था. जांच में पता चला कि अनाज रखने के लिए अमिलिया गांव में ग्राम पंचायत भवन के दो कमरों को गोदाम बनाया गया और उनमें 48 ट्रक अनाज रखने के काग़ज़ात तैयार किए गए. जांच टीम ने जब इन दो कमरों को देखा तो उसके सदस्यों को आश्चर्य हुआ कि इन दो कमरों में बमुश्किल दो ट्रक अनाज रखने की क्षमता है. तो ऐसे में 48 ट्रक अनाज इनमें कैसे समा गया? इसी तरह आलमपाली गोदाम के दो कमरों में 64 टन अनाज रखने के मामले का ख़ुलासा हुआ. अनाज घोटाले की यह ख़बर जब मीडिया के ज़रिए हर तरफ़ आम हो गई तो संभाग आयुक्त ने मामले की जांच कराई. जांच में बुनियादी शिकायत तो सही पाई गई, लेकिन घोटाले के लिए कौन ज़िम्मेदार है, इसका ख़ुलासा नहीं हो सका. बाद में शहडोल के संभाग आयुक्त ने अधिकारियों की एक और टीम बनाकर मामले की दोबारा जांच कराई, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट ज़िला कलेक्टर एवं संभाग आयुक्त को नहीं मिली है. इसी बीच दो बाबुओं को ज़िम्मेदार मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है. सूत्रों का कहना है कि इस अनाज घोटाले की जड़ें काफ़ी गहरी हैं. निलंबित लिपिक इसके एक छोटे हिस्सेदार हैं, मोटी मलाई तो बड़े लोगों के पेट में गई है. कहा तो यह भी जा रहा है कि उक्त अनाज कथित गोदामों में आने के बजाय आला अफसरों की मिलीभगत से खुले बाज़ार में बेच दिया गया.

जांच टीम को पता चला कि एक बाबू ने भारतीय खाद्य निगम के कटनी स्थित गोदाम से 64 ट्रक अनाज उठाया था और गोदाम से अनाज ले जाने संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए थे. जब जांच हुई और उस बाबू से पूछताछ की गई तो उसने केवल 20 ट्रक अनाज उठाने व ले जाने की बात स्वीकार की. पाली गोदाम के प्रभारी सूर्यभान सिंह एवं अमिलिया गोदाम के प्रभारी एस बी मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने खाद्य निगम के कटनी गोदाम से अनाज उठाने के लिए फ़र्ज़ी बाउचर बनाए और वितरण के फ़र्ज़ी दस्तावेज तैयार किए थे. जांच के दौरान जो दस्तावेज ज़ब्त किए गए, उनसे पता चला कि विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं सचिवों के नाम से फ़र्ज़ी पावती बनाई गई. उसके लिए उनके जाली दस्तख़त भी इन्हीं बाबुओं ने किए. पूछताछ के दौरान संबंधित पंचायतों के सरपंचों एवं सचिवों ने अनाज उठाने और पावती के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर से साफ़ इंकार किया है.

ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीबों को रोज़गार उपलब्ध कराने और छोटे निर्माण कार्यों की विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर साल पर्याप्त धन और अनाज उपलब्ध कराती है. उमरिया ज़िले की पाली ग्रामसभा में 2003–04 और 2005–06 में गांव में केंद्रीय योजनाओं के तहत काम होना बताया गया है. इन तीन वर्षों के भीतर इस जनपद में 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी आए और चले गए, फिर भी किसी ने पाली एवं अमिलिया गांव में चल रहे अनाज और सरकारी धन के घोटाले की कोई सुध नहीं ली. जब जांच दल ने उमरिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर पी सिंह, रामानुज टोप्पो, के के पांडेय, एम पी शुक्ला एवं शर्मा से इस बारे में लिखित जानकारी मांगी और पूछताछ की तो इन सभी के जवाब संतोषजनक नहीं मिले. पता चला है कि पाली और अमिलिया के गोदामों से दो स्तरों पर हेराफेरी की गई है. वर्ष 2005–06 में लगभग 6200 क्विंटल अनाज स्टॉक रजिस्टर में दर्ज़ ही नहीं किया गया. इसके बाद फ़र्ज़ी बाउचर के ज़रिए 10554 क्विंटल अनाज पंचायतों में वितरित दिखा दिया गया. इस बारे में अधिकारी जांच दल को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके. इससे लगता है कि इस घोटाले की जड़ें काफ़ी गहरी हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन का फ़र्ज़ीवाड़ा

मध्य प्रदेश में चारो ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है. निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज भी इससे अछूते नहीं हैं. केपीटेशन शुल्क या दान के नाम पर वहां घड़ल्ले से प्रवेश का कारोबार चल रहा है. इस बात को लेकर सरकार भी चिंतित रही है. शासन ने इस पर रोक लगाने के भरसक प्रयास भी किए, लेकिन अब तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ही प्रवेश के लिए सौदेबाज़ी होने लगी है और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वर्ष बुंदेलखंड के सागर नगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो की, लेकिन स्थापना के साथ ही इस कॉलेज में मेडिकल शिक्षा का व्यापार पनपने लगा. इस कॉलेज में नौ छात्रों ने फ़र्ज़ी सीट एलॉटमेंट ऑर्डर के आधार पर प्रवेश ले लिया और जब वे पकड़े गए, तो उनके ख़िलाफ़ भोपाल के एम.पी. नगर थाना में प्रकरण भी दर्ज़ हो गया, लेकिन मामला दर्ज़ हुए एक माह से ज़्यादा समय बीत गया है, फिर भी फ़र्ज़ी तरीक़े से एडमिशन लेने वाले छात्रों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है.

इसके बाद हाल ही में एक छात्रा के पिता ने अपनी बेटी को सागर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए 5.50 लाख रुपये में सीट ख़रीदने का अपराध क़बूल करके इस कॉलेज में जारी गोरखधंधे को उजागर किया है. मामला इस प्रकार है कि भारतीय स्टेट बैंक में सहायक प्रबंधक नीरज श्रीवास्तव अपनी बेटी को मेडिकल कॉलेज सागर में एडमिशन दिलाने पहुंचे. वहां नीरज ने कॉलेज के डीन डॉ. एस.सी. तिवारी को मध्यप्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग संचालनालय का सीट एलॉटमेंट लेटर दिया. इस पत्र में नीरज की पुत्री को एडमिशन देने का उल्लेख था, लेकिन डीन को इस पर संदेह हुआ और उन्होंने अपने कॉलेज के अधिकारियों से इस पत्र की जांच करने को कहा. छानबीन और जांच के बाद अधिकारियों ने पाया कि यह एडमिशन लेटर एकदम फ़र्ज़ी है, क्योंकि कॉलेज की काउंसलिंग समिति में इस छात्रा का कहीं कोई नाम नहीं था. इसके बाद काउंसलिंग समिति के सदस्यों से भी पूछताछ की गई और डीन ने मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने नीरज श्रीवास्तव और काउंसिलिंग समिति के सदस्यों से पूछताछ की तो पता चला कि समिति की ओर से भोपाल के एक व्यक्ति से साढ़े पांच लाख रुपये लिए गए हैं और फ़र्ज़ी एलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया. इस मामले में नीरज श्रीवास्तव की निशानदेही पर चार व्यक्तियों को संदेह के घेरे में लिया गया है और भोपाल तथा सागर में इस मामले की छानबीन की जा रही है. इस प्रकार सागर मेडिकल कॉलेज में फ़र्ज़ी तरीक़े से एडमिशन लेने की यह दसवीं घटना है.

मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेना आसान नहीं है. एडमिशन के लिए कड़ी प्रतियोगी परीक्षा होती है. प्री–मेडिकल टेस्ट में सफल होने वाले छात्रों को मैरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है. परीक्षा में अधिक नंबर पाने वालों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलता है और शेष छात्रों को निजी कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फ़ीस 35 हज़ार रुपये वार्षिक है, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों में दो से तीन लाख रुपया तक वार्षिक फीस चुकानी पड़ती है. इसीलिए छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने को प्राथमिकता देते हैं. जब आसानी से और नियमानुसार एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो कुछ चालाक और संपन्न लोग भ्रष्टाचार के ज़रिए एडमिशन लेने में सफल हो जाते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

डॉ. पी.एस. हार्डिया – अद्भुत कौशल

विश्व के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रताप सिंह हार्डिया अपने सर्जरी कौशल के कारण जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय है। गिनीज बुक ऑफ बर्ल्ड रिकार्डधारी डॉ. हार्डिया ने लगभग 5 लाख 38 हजार से अधिक सफलतम ऑपरेशन किए है। रोगियों के बीच एक सहृदय बुजुर्ग एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व की तरह सम्मान पाते डॉ. हार्डिया इसे सेवा के रूप में लेते हुए प्रतिवर्ष शिविरों के माध्यम से निम्न वर्गीय एवं मध्यमवर्गीय लोगों का उपचार करते है।

शहर के 130 साल के चिकित्सा जगत के इतिहास में इन्दौर ने यू तो एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व दिये है, किन्तु अपने चिकित्सकीय ज्ञान से रोगियों के रोग पहचान कर अपने अद्भुत कौशल के कारण लोकप्रिय है। इन्हीं में से प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. पी.एस. हार्डिया जो अपने मानवीय व्यवहार एवं ऑखों की सर्जरी के विश्वस्तरीय कौशल के कारण जन प्रिय है। उनकी तमाम चिकित्सकीय उपलब्धियां और देश विदेश से मिले तमगे उस पिता की ऑखों से बहते हुए कृतज्ञता के ऑसुओं के सामने बेमानी हो जाते है। हाल ही में डॉ. हार्डिया को विश्व के टॉप सम्मान जनक व्यक्ति से नबाजा गया है।

उद्योग जगत – बाल्को

बालको की स्थापना 27 नवम्बर, 1965 को हुई थी। संयंत्र का निर्माण 1970 से शुरू हुआ जबकि यहां से उत्पादन 1975 से आरंभ हुआ। हंगरी और रूस के सहयोग से स्थापित संयंत्र में आठ सेल हाउस थे जिनमें स्थापित 408 इलेक्ट्रोलिटिक पॉट्स हर वर्ष दो लाख टन एल्यूमिना से लगभग एक लाख टन एल्यूमिनियम धातु बनाते थे। वर्तमान में सभी पुराने आठ सेल हाउस आधुनिकीकरण के उद्देश्य से बंद किए जा चुके हैं। विनिवेश के बाद स्टरलाइट और अब उसकी मातृ कंपनी वेदांत समूह ने बालको की विस्तार परियोजनाओं पर भारी निवेश किया है। स्टरलाइट ने लगभग 4,500 करोड़ रुपए के निवेश से 288 पॉट युक्त 2.50 लाख टन का स्मेल्टर और 540 मेगावॉट का विद्युत संयंत्र रिकॉर्ड समय में तैयार कर उत्पादन शुरू किया। विस्तार योजना के तहत वेदांत समूह ने बालको में साढ़े 6.5 लाख टन के नए स्मेल्टर की योजना बनाई है जिसके लिए अगस्त, 2007 में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समझौता भी हो चुका है। लगभग 8 हजार करोड़ रुपए की प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के बाद बालको की कुल एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता लगभग 10 लाख टन हो जाएगी।

मुनाफा – विनिवेश के बाद के दौर में बालको लगातार मुनाफा अर्जित करने में सफल रहा है। वर्ष 2001–02 में 18.76 करोड़ के मुनाफा से शुरू हुआ सफर वर्ष 2002–03 में 64.49 करोड़, वर्ष 2003–04 में 67.48 करोड़, वर्ष 2004–05 में 127.45 करोड़, वर्ष 2005–06 में 168.50 करोड़, वर्ष 2006–07 में 906.52 करोड़, वर्ष 2007–08 में 678.18 करोड़ तथा वर्ष 2008–09 मे 517.36 करोड़ रहा।

उत्पादन – वर्ष 2007–08 में गर्म धातु का रिकॉर्ड 3,62,296 मीट्रिक टन रहा। वर्ष 2007–08 में रॉड उत्पादन 1,01,317 मीट्रिक टन, रोल्ड उत्पादों का उत्पादन 61,227 मीट्रिक टन हुआ।वित्तीय वर्ष 2008–09 में वॉयर रॉड का उत्पादन 1,27,041 मीट्रिक टन हुआ। वर्ष 2007–08 में वायर रॉड का उत्पादन 1,01,183 मीट्रिक टन हुआ था।वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्री–बेक्ड तकनीक पर आधारित स्मेल्टर–2 से 2,51,180 मीट्रिक टन गर्म धातु का उत्पादन हुआ। यह संयंत्र की स्थापित क्षमता से 2.52 प्रतिशत अधिक है।

1. स्वास्थ्य सेवाएं–स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से 100 बिस्तरों का बालको चिकित्सालय स्थापित है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। बालको अस्पताल में कोरबा जिले के प्रथम बर्न यूनिट की स्थापना की दिशा में काम शुरू हो गया है। बर्न यूनिट में 4 बेड के अलावा अत्याधुनिक आई.सी.यू. होगा जिसमें अग्नि दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के इलाज की समस्त सुविधाएं होंगी। इसके अलावा ऑपरेशन थियेटर, फिजियोथैरेपी केंद्र एवं विशेष ड्रेसिंग रूम होंगे।
2. बालको की स्वास्थ्य सुविधाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर चिकित्सा शिविरों का आयोजन। हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित बालको की वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र परियोजना के अंतर्गत गांवों में चलित कैंसर जांच वाहन एवं प्रशिक्षित क्षेत्र पर्यवेक्षकों की मदद से कैंसर पीड़ितों की पहचान का कार्य शुरू किया गया है।
3. वर्ष 2009 में प्रबंधन ने कोरबा जिले के ग्राम चुईया में वेदांत ग्रामीण चिकित्सालय की जिसमे आसपास के 30 गांवों के लगभग 30,000 नागरिकों को केंद्र से लाभ मिल रहा है।
4. रायपुर के नए राजधानी क्षेत्र में विश्वस्तरीय वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना पर काम शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत लगभग 300 करोड़ रुपए के निवेश से चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की सुविधा होगी।शेष 2 चरणों में अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का विस्तार 350 बिस्तरों तक किया जाएगा।

1. सामुदायिक विकास– वित्तीय वर्ष 2008–2009 में बालको के सामुदायिक विकास कार्यों का दायरा 20 से 102 गांवों में विस्तारित हुआ।
2. शिक्षा व्यवस्था के लिए टाउनशिप परिसर में 15 स्कूल हैं जिनका संचालन बालको प्रबंधन की मदद से किया जाता है। लगभग 6000 बच्चे बालको की मदद से संचालित स्कूलों से लाभान्वित हो रहे हैं।
3. वर्ष 2007–08 में बालको प्रबंधन और नाबार्ड के संयुक्त तत्वावधान में 1000 हेक्टेयर भूमि पर वाटरशेड परियोजना शुरू हुई।
4. वर्ष 2009 मे कोरबा जिले मे राज्य के पहले केन्द्रीयकृत रसोइघर की स्थापना से लगभग 50,000 बच्चो को लाभ मिल सकेगा । रसोईघर के लिए आधारभूत संरचना के विकास पर बालको प्रबंधन 1.50 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है ।
5. वर्ष 2009–2010 मे 'ममता परियोजना' का लाभ 537 नए आंगनबाड़ियों तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ । कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र जिला है जहां आंगनबाड़ियों में बच्चों को गणवेश वितरित किए गए।
6. स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मैनपाट, कवर्धा और कोरबा के 6 गांवों में 1,050 शौचालय निर्मित किए गए। 'निर्मल ग्राम' के लिए चुईया, औंराकछार और जामबहार को राष्ट्रपति पुरस्कार ।

उपलब्धिया

1. बालको फ्यूज तकनीक के विकास के लिए आईडियाज यूके टेक्नोलॉजी ट्रॉफी और यूरोपियन एल्यूमिनियम स्पेशल प्राईज।
2. फास्ट एंड सुलिवैन की ओर से आइ.एम.इ.एण सिल्वर एर्वाड ।
3. श्रेष्ठ पर्यावरण प्रबंधन के लिये मैनपाट खदान को वर्ष 2008 का फिक्की जेम ग्रेनाइट पुरस्कार ।
4. सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, यू.के. का प्रतिष्ठित ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल पुरस्कार–2008।
5. केंद्रीय गैरेज और केंद्रीय अनुरक्षण को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा वर्ष 2008–09 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार।
6. 540 मेगावॉट विद्युत संयंत्र को वर्ष 2008 के लिए 'सृष्टि गुड ग्रीन गवर्नेंस अवार्ड'।
7. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्यों के लिए वर्ष 2008 में सी.आई.आई. पूर्व क्षेत्र द्वारा प्रशस्ति पत्र।
8. वर्ष 2008 के लिए व्ही.आर.एम. फाउंडेशन, छत्तीसगढ़ द्वारा 'उत्कृष्ट प्रदूषण निवारक उद्योग पुरस्कार'।
9. वर्ष 2008–09 के लिए मैनपाट खदान को आई.बी.एम. नागपुर क्षेत्र की ओर से रिक्लेमेशन एवं रिहैबिलिटेशन का द्वितीय और खनिज प्रबंधन का द्वितीय पुरस्कार।
10. वर्ष 2008–09 के लिए कवर्धा खदान को आई.बी.एम. नागपुर क्षेत्र की ओर से उपजाऊ मृदा प्रबंधन का द्वितीय पुरस्कार।
11. वर्ष 2008 में डी.जी.एम.एस. बिलासपुर क्षेत्र की ओर से पर्यावरण प्रबंधन व प्रदूषण नियंत्रण का द्वितीय पुरस्कार।
12. वर्ष 2008–09 के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, भारत की ओर से एल्यूमिना और सी.पी.पी.–1 को सुरक्षा नवाचार पुरस्कार।
13. वर्ष 2008–09 के लिए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से केंद्रीय गैरेज और स्मेल्टर–2 को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।
14. वर्ष 2008–09 के लिए स्मेल्टर–2 को सी.आई.आई. पूर्व क्षेत्र का ग्रीनटेक सेफ्टी गोल्ड अवार्ड।
15. गोल्डन पीकॉक हेल्थ एंड सेफ्टी कमेंडेशन अवार्ड।
16. राष्ट्रीय स्तर पर जहां टी.ई.आर.आई. (टाटा एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट) से बालको को सराहना मिली है वहीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर एड्स जागरूकता एवं रोकथाम अभियान के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार से बालको को सम्मान ।

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 22 फरवरी–28 फरवरी 2010

प्रशासन से संबंधित अधिकारी परमाणु संयंत्रों के लाभ को तो गिना रहे हैं, पर उससे होने वाली हानि या जनजीवन पर पड़ने वाले संकट के प्रति अभी भी अनभिज्ञ ही हैं.

गीत चोरी का आरोप कितना सच

प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका द्वारा गाई गई रचना– *गंगा तुम बहती हो क्यों*, उनकी मौलिक कृति नहीं है. उन्होंने संगीत रचना एवं गीत की भावनाएं अमेरिकी कलाकार की एक मशहूर रचना से कॉपी की थी. यह रहस्योघाट्न अमेरिका में रह रहे एक भारतीय मुकेश थामस ने पिछले दिनों दोनों संगीत प्रस्तुतियों के गहन अध्ययन के बाद किया है.

भूपेन हजारिका

वर्ष 1927 में अमेरिका के संगीतकार जूलियस ब्लेडसो की एक संगीत रचना *ओल्ड मेन रिवर ऑफ शो* वोट संगीत के इतिहास की एक अमर कृति है. इस कृति के जनक को इस संगीत रचना के लिए अमेरिका ही नहीं, समूचे यूरोप में हमेशा से स्मरण किया जाता रहा है. आज से डेढ़ दशक पूर्व इंटरनेट की सुविधा न होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों पर शोध कर पाना भारत में संभव नहीं था. भूपेंन हजारिका ने अपनी रचना–विस्तार है आपार, की प्रस्तुति के दौरान कभी भी किसी भी मंच पर यह घोषणा नहीं की कि गंगा उनकी मौलिक रचना नहीं है.

उन्होंने कभी भी अमेरिका के प्रख्यात संगीतकार जूलियस ब्लेडसो का नाम नहीं लिया. पूरे भारत में, गंगा तुम बहती हो क्यों रचना भूपेन हजारिका द्वारा लिपिवद्ध, संगीतवद्ध और गाई गई रचना के रूप में जानी जाती है. जूलियस के इस चर्चित गीत को अमेरिका के कई कलाकारों ने विभिन्न मंचों पर गाया है. इसके अलावा कई टीवी कार्यक्रमों में भी यह गीत उपयोग किया गया है. पालाबिंसन ने 1928, 1932 एवं 1936 में इस गीत को फिल्म में चित्रित किया है. बिंग क्रासवी, फ्रैड सिनड्रा, सैम कुक , अल जानसन, रेचार्ल्स, जिम क्रोस, जिमी रिक्स ने इसे अमेरिकी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गीत के रूप में स्वीकार किया था. मेल्विन फैडलिन ने तो इस गीत को कई महफिलों में गाया था. जुड़ी गारलैंड ने भी इस गीत को अपना स्वर दिया था.

मुकेश थामस के अनुसार, भूपेन हजारिका ने अपनी पीएचडी की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पूरी की थी. इस अध्ययन के दौरान वे पाल रॉबिंसन जैसे गायक के सहयोगी भी रहे थे. इस दौर में भूपेन हजारिका ने जो गीत सीखे उनका प्रदर्शन उन्होंने अपने शेष जीवन की संगीत रचनाओं में भारत में रहकर किया था. भूपेन हजारिका द्वारा गाई गई रचना– गंगा तुम बहती हो क्यों, भारत के संगीत जगत में एक नया अध्याय जोड़ने वाली कृति के रूप में याद की जाती है. स्वरों के उतार चढ़ाव और भाषा की मौलिकता इस गीत की ख़ूबी है. मूल रूप से गाई गई जूलियस ब्लेडसे की रचना भी मिसीसिपी नदी पर आधारित है. इस गीत के भाव को महसूस करने के बाद भूपेन की रचना चोरी की गई प्रतीत होती है.

मुकेश थामस इन दिनों अमेरिका में रह कर भारतीय संगीत पर यूरोपीय प्रभाव का व्यापक अध्ययन कर रहे हैं. उनका दावा है कि भूपेन हजारिका के बारे में इस तरह के ख़ुलासे से भारतीय संगीत प्रेमियों को आघात लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है.

चौथी दुनिया
feedback@chauthiduniya.com

दुर्लभ संजीवनी बूटी मिलने का दावा

मध्य प्रदेश के वन विभाग ने विंध्य के जंगलों में संजीवनी बूटी के मिलने का दावा किया है. रामायण में संजीवनी बूटी के बारे में यह उल्लेख है कि बाण लगने से मूर्छित लक्ष्मण को संजीवनी बूटी के प्रयोग से ही मूर्छित किया जा सका था. दावा किया जाता है कि रामायण में जिस संजीवनी बूटी का वर्णन हैं, वह वास्तव में कोई एक औषधि न होकर चार अलग–अलग औषधियों का मिश्रण है. इन चारों औषधियां के चार विभिन्न वनस्पतियों से प्राप्त होने की बात कही जाती है. इन वनस्पतियों के नाम हैं –मृत संजीवनी, विषल्यकरणी, संधानकरणी और सवर्ण्यकरणी. ये चारों ही दुर्लभ वनस्पतियां विंध्य क्षेत्र में उपलब्ध हैं. मृत संजीवनी से मृतप्राय व्यक्ति के हृदय और मस्तिष्क को सचेतन किया जाता है. विषल्यकरणी से शरीर के घाव भरे जाते हैं. संधानकारणी से त्वचा को जोड़ा जाता है और सवर्ण्यकरणी से त्वचा के रंग को मूल रूप में लाया जाता है. इस प्रकार इन चारों वनस्पतियों से तैयार औषधि से चोट लगने से गंभीर रूप से घायल और मृतप्राय व्यक्तियों को भी तेज़ी से स्वस्थ किया जा सकता है.

वनविभाग के सहायक वन संरक्षक पी.पी.एस. परिहार का कहना है कि विभाग ने अनेक दुर्लभ और औषधीय महत्व की वनस्पतियों की तलाश करने में सफलता पाई हैं और अब इनके पौधे नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं. अब तक वन विभाग की नर्सरी में एक लाख 24 हज़ार पौधे तैयार किए जा चुके हैं. वन विभाग ऐसे 13 लाख पौधे तैयार करने के लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है. अभी तक विभाग ने औषधीय महत्व की 80 से ज़्यादा दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सफलता पाई है.

चौथी दुनिया
feedback@chauthiduniya.com

बिजली मिलेगी, लेकिन बैगाओं पर तो गिरेगी

बैगा आदिवासी बहुल मंडला ज़िले में परमाणु संयंत्र की स्थापना से बैगा आदिवासियों के अस्तित्व पर ख़तरा मंडरा रहा है. लेकिन सरकार को तो बस बिजली उत्पादन की चिंता है.

असगर क़ुरैशी

मंडला ज़िले के चुटका नामक ग्राम में न केवल महाकौशल बल्कि पूरे मध्य भारत के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र स्थापित करने की तैयारियां चल रही हैं. यह भूभाग बैगा आदिवासियों का प्रमुख क्षेत्र है और पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है. वर्ष 1983 से इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे जिसे पिछले साल 2009 में स्वीकृति मिली है.

चुटका परमाणु संयंत्र की स्थापना की दिशा में प्रारंभिक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है. यहां थोरियम से बिजली बनाई जायेगी. भारत में थोरियम व्यापक रूप से उपलब्ध है. ऐसा अनुमान है कि यहां उपलब्ध थोरियम से 300 से 400 साल तक परमाणु ईंधन बनाए जा सकते हैं. इस परमाणु बिजली घर को 800 से 1000 क्यूसेक पानी पास में बह रही नर्मदा नदी से उपलब्ध कराई जाएगी.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर बहस कर रहे देशों के लिए चुटका परमाणु संयंत्र चिंता नहीं, विकास का मामला है. इससे पर्यावरण को होने वाली हानि और विस्थापन के आंकड़ों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. आसपास के ग्रामीण इस परियोजना को लेकर परेशान हैं. बरगी बांध के कारण एक बार पूर्व में विस्थापन का दर्द झेल चुके ग्रामवासियों का इस परमाणु संयंत्र के कारण फिर से विस्थापित होना तय है. बरगी बांध विस्थापितों के महासंघ के अध्यक्ष केहरसिंह मार्को इस मामले में आरपार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं. मार्को के अनुसार, इस संयंत्र के लिए विस्थापितों को मुआवज़े के तौर पर दो हज़ार रुपये प्रति एकड़ की राशि दी जा रही है. चुटका में स्थापित होने वाले दो संयंत्रों की क्षमता सात सौ मेगावाट प्रति संयंत्र है. मंडला ज़िले में जहां परियोजना स्थापित की जानी है वह इलाक़ा विलुप्ती की कगार पर पहुंची आदिम जाति बैगा का प्राकृतिक निवास स्थल है. बैगाओं का जीवन आज भी प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है. बैगा अभी तक विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़ नहीं पाए हैं. परमाणु संयंत्रों से होने वाली किसी भी प्रत्याशित या अप्रत्याशित हानि के बारे में वे न तो सजग हैं और न ही सचेत. संयंत्र को स्थापित करने के लिए 6663.22 हेक्टेयर वन भूमि और 76699.56 हेक्टेयर सरकारी भूमि से वनक्षेत्र को साफ़ करके ज़मीन का अधिगृहण किया जाएगा. अगर ऐसा हो गया तो पर्यावरण की सुरक्षा की ज़िम्मेवारी उठाना और स्थानीय नागरिकों को जीवन यापन के लिए उचित वातावरण दे पाना संभव नहीं हो पाएगा.

इस परियोजना के कारण 300 आदिवासी परिवारों, जिनमें 85 प्रतिशत बैगा परिवार हैं, को विस्थापित होना पड़ेगा. परमाणु संयंत्र कब तक बन पाएगा और कब तक बिजली का उत्पादन शुरू हो पाएगा इसकी कोई समय सीमा भी अभी तक निर्धारित नहीं की गई है. प्रशासन से संबंधित अधिकारी परमाणु संयंत्रों के लाभ को तो गिना रहे हैं, पर उससे होने वाली हानि या जनजीवन पर पड़ने वाले संकट के प्रति अभी भी भी अनभिज्ञ ही हैं. इस परमाणु संयंत्र की लागत 9000 करोड़ रुपये बताई जाती है. राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारी परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान खाली करने के लिए स्थानीय लोगों पर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं. दूसरी ओर केहरसिंह मार्को के नेतृत्व में चुटका विस्थापित महासंघ का गठन भी किया जा चुका है. आने वाले दिनों में परमाणु संयंत्र की स्थापना का दंश मंडला ज़िले के आदिवासियों को भुगतना ही होगा, यह बात तय है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 22 फरवरी-28 फरवरी 2010

www.chauthiduniya.com

जदयू के नाराज़ सांसदों और विधायकों की गोलबंदी तेज़

निशाने पर नीतीश

नीतीश कुमार

ललन सिंह

सरोज सिंह

पिछले चार सालों से अपनी मर्जी से सत्ता की राजनीति कर रहे नीतीश कुमार इस समय अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती से रूबरू हो रहे हैं. राहुल गांधी के दौरे के बाद तेज़ हुए विपक्षी हमलों और जदयू में जारी घमासान की वजह से वह उलझते जा रहे हैं. अलग-अलग कारणों से नाराज चल रहे कई सांसदों एवं दर्ज़नों विधायकों की गोलबंदी नीतीश और उनकी सरकार पर भारी पड़ रही है. ख़तरा यह भी है कि कई सांसद और विधायक उनका साथ छोड़ सकते हैं. नीतीश से खार खाए ऐसे सांसद, विधायक दिल्ली से लेकर पटना तक जोड़तोड़ में लगे हैं. राजद, लोजपा और कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हैं. अमर सिंह अगर बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी पका पाए तो नीतीश का संकट और बढ़ सकता है. चुनावी साल की इन चुनौतियों का एहसास नीतीश कुमार को भी है, इसलिए विरोधियों को पटकनी देने और पार्टी के नाराज़ सांसदों एवं विधायकों की गोलबंदी को ध्वस्त करने के मास्टर प्लान पर तेज़ी से काम शुरू हो गया है.

दरअसल नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ नाराज़ सांसदों और विधायकों का गुस्सा ललन सिंह के इस्तीफे के बाद काफी बढ़ गया है. आमतौर पर इस मामले में बात करने से कतराने वाले नेता अब खुलकर अपनी बात कहने लगे हैं. ऐसे नेता नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी में जी-जान से जुटे हैं. झटका देने का यह खेल कई मैदानों पर खेला जा रहा है. बेशक खिलाड़ी अलग-अलग हैं और फिलहाल रणनीति भी अलग-अलग, लेकिन सबके निशाने पर नीतीश कुमार हैं. उनका इरादा जदयू को कमज़ोर करने का है. पहला खेल जदयू संसदीय दल में टूट का चल रहा है. बताया जाता है कि टूट के लिए ज़रूरी चौदह सांसदों का जुगाड़ करने की कवायद चल रही है. ललन सिंह के इस्तीफे के बाद इस अभियान को बल मिला है. सूत्रों पर भरोसा करें तो जदयू संसदीय दल की टूट के खेल में कांग्रेस भी शॉट खेल रही है. पिछले दिनों शरद पवार की बाल ठाकरे से मुलाक़ात ने कांग्रेस को आने वाले ख़तरे का एहसास करा दिया. इसके अलावा महंगाई को लेकर ममता बनर्जी के तेवर ने भी कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं. इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा यह खेल अब गति पकड़ चुका है, लेकिन इंतजार बजट सत्र के बीत जाने और सांसदों की संख्या चौदह होने का किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, यह संख्या फिलहाल आठ से लेकर दस तक के बीच है. बताया जाता है कि ललन सिंह, जगदीश शर्मा, पूर्णमासी राम के अलावा कैप्टन जयनारायण निषाद, महेश्वर हजारी, मोनाजिर हसन, मंगनी लाल मंडल और राम सुंदर दास पर डोरे डाले जा रहे हैं. गोलबंदी की भनक लगते ही नीतीश कुमार ने कई सांसदों से बात कर उन्हें जदयू को मज़बूत करने के काम में जुटने के लिए कहा, लेकिन इस खेल का क्लाइमेक्स शरद पवार और ममता बनर्जी के अगले क़दम पर निर्भर करता है. अगर किसी भी कारण से इन दोनों में कोई एक भी मनमोहन सरकार का साथ छोड़ देता है तो नीतीश कुमार को अपने सांसदों को बचाने के लिए कड़ी मशक़्क़त करनी पड़ सकती है.

जहां तक बिहार का सवाल है तो सत्ता की राजनीति में पिछले चार सालों से उपेक्षा झेल रहे कई मंत्रियों और विधायकों को अब चुनावी टिकट कटने का भी डर सताने लगा है. आम शिकायत रही कि मंत्रियों एवं विधायकों की क्षेत्र में कोई नहीं सुन रहा और अफसर अपने हिसाब से फ़ैसले ले रहे हैं. अब चुनावी साल में आफत यह है कि बहुत सारे विधायकों के प्रति क्षेत्र के वोटरों का गुस्सा चरम पर है. कुछ विधायक तो अपने रवैये और कुछ लाचारी के कारण जनता से काफी दूर जा चुके हैं. विकास योजनाओं में कमीशन लेने के कारण कुछ विधायकों की छवि इतनी ख़राब हो गई है कि नीतीश कुमार के लिए ऐसे विधायकों को फिर से चुनावी अखाड़े में उतारना मुश्किल होगा. ऐसे विधायकों को भी आने वाले संकट का एहसास है. सूत्रों पर भरोसा करें तो लगभग दो दर्ज़न विधायक विधानसभा के बजट सत्र के बाद अपनी चुनावी सुविधा के अनुसार कांग्रेस, लोजपा एवं राजद का दामन थाम सकते हैं. बताया जाता है कि अजित कुमार, श्याम बिहारी प्रसाद, शिवजी राय, मीना देवी, जगमातो देवी, मनोरंजन सिंह, सुचित्रा सिन्हा, राजू सिंह, मुन्ना शुक्ला, शशि कुमार राय, गुड्डी देवी, अभय सिंह, रामेश्वर पासवान, कैलाश बैठा, मनेंद्र कुमार मंडल, अनंत कुमार सत्यार्थी, आर आर कनौजिया, जय कुमार सिंह, रेणु देवी, रणविजय सिंह, विश्वनाथ सिंह और गोपाल कुमार अग्रवाल आदि विधायक सत्ता में अब तक के अपने सफर से बहुत ख़ुश नहीं हैं. वे जदयू को मज़बूत तो बनाना चाहते हैं, पर अपनी शर्तों पर. ऐसा न होने पर उक्त विधायक कोई भी क़दम उठा सकते हैं. लगभग एक दर्ज़न मंत्री भी नीतीश कुमार से नाराज़ बताए जाते हैं. उत्पाद मंत्री जमशेद अशरफ ने तो खुलकर मुख्यमंत्री सचिवालय के कुछ अफसरों पर शराब के ठेके में पांच सौ करोड़ रुपये कमाने का आरोप लगाया है. अशरफ ने कहा कि विभाग में उनकी कोई नहीं सुन रहा है. यही कारण है कि कोई मंत्री अपने दूत के माध्यम से तो कोई ख़ुद अलग-अलग ठिकानों पर संपर्क में है. इंतजार बस उचित मौक़े का किया जा रहा है. बजट सत्र के बाद कुछ और मंत्रियों के खुलकर सामने आने की तैयारी है. इधर अमर सिंह भी बिहार में अपना राजनीतिक प्रयोग करना चाहते हैं. पिछले सप्ताह दिल्ली में अमर सिंह बिहार के कई बड़े नेताओं से मिले. एजेंडे में था तीसरे मोर्चे का गठन. अमर सिंह चाहते हैं कि जदयू के नाराज़ नेताओं के अलावा दूसरे दलों के भी कुछ बड़े नेताओं को एक मंच पर लाकर बिहार में एक नया विकल्प जनता को दिया जाए. अमर सिंह इसमें वामदलों का भी सहयोग ले सकते हैं. ददन पहलवान इस काम में काफी सक्रिय हैं. जनता का मिजाज भांपने के लिए 22 फरवरी को मधेपुरा में एक रैली का आयोजन भी ददन पहलवान करा रहे हैं. उत्तर बिहार में मज़बूत किलेबंदी के लिए आनंद मोहन, पप्पू यादव और किशोर कुमार मुन्ना से भी संपर्क साधा जा रहा है. सीमांचल में तस्लीमुद्दीन तो सारण में प्रभुनाथ सिंह को मोर्चे पर लगाने की तैयारी चल रही है. नीतीश विरोधी मोर्चा और बिहार में एक मज़बूत विकल्प बनाने के लिए बांका के सांसद दिग्विजय सिंह से भी राय ली जा रही है.

कहा जाए तो सबके निशाने पर नीतीश कुमार हैं, लेकिन वह इतना आसान शिकार नहीं हैं. तैयारी में नीतीश कुमार भी हैं. कुछ नाराज़ सांसदों और विधायकों को तो अपना रास्ता ख़ुद तय करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन पार्टी के लिए उपयोगी नेताओं को मनाने और समझाने का काम कई स्तरों पर जारी है. अति पिछड़ों एवं महादलितों को एकजुट कर बड़ी राजनीतिक ताक़त हासिल करने का अभियान भी शुरू है. प्रखंड से लेकर ज़िला स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए भी कार्यक्रम घोषित किए जा रहे हैं. नीतीश कुमार यह संदेश देना चाहते हैं कि कुछ नेताओं की नाराजगी से पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और विकास के नाम पर जनता ज़रूर उनका साथ देगी. जनसरोकार से जुड़ी योजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है. संभावित बाढ़ से निपटने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि अगर बाढ़ आए तो तबाही कम से कम हो. बजट में विकास एवं जनकल्याण की झलक दिखने के आसार हैं. देखा जाए तो शह और मात का खेल शुरू है, पर बाजी किसके हाथ लगेगी, यह बजट सत्र के बाद ही पता चलेगा.

feedback@chauthiduniya.com

इंतजार बजट सत्र के बीत जाने और सांसदों की संख्या चौदह होने का किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, यह संख्या फिलहाल आठ से लेकर दस तक के बीच है. बताया जाता है कि ललन सिंह, जगदीश शर्मा, पूर्णमासी राम के अलावा कैप्टन जयनारायण निषाद, महेश्वर हजारी, मोनाजिर हसन, मंगनी लाल मंडल और राम सुंदर दास पर डोरे डाले जा रहे हैं.

मोनाजिर हसन

जगदीश शर्मा

पूर्णमासी राम

किशोर कुमार मुन्ना

मंगनीलाल मंडल

आज वनवासी नगर के दलित अपने कर्म, विचार, मेहनत और समाजसेवा के लिए पूरे ज़िले में चर्चित हैं.

आलम यह है कि इस रेलखंड पर रात में सुरक्षाबल के जवान रेलगाड़ियों में मौजूद नहीं रहते. नक्सलियों के डर से रेलवे पुलिस स्वयं की सुरक्षा में ही लगी रहती है.

नक्सलियों के आगे रेलवे सुरक्षाबल नतमस्तक

रेल मंत्रालय सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये ख़र्च करता है. यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षाबल तैनात किया गया है, लेकिन जब सुरक्षाबल ही डर जाए तो ट्रेन में सफर करने वालों का क्या होगा? यह सौ फ़ीसदी सच्ची बात है. पूर्व मध्य रेलवे के हावड़ा–पटना रेलमार्ग पर जसीडीह–कियूल स्टेशन के बीच रेल यात्री भगवान भरोसे ही यात्रा करते हैं. आलम यह है कि इस रेलखंड पर रात में सुरक्षाबल के जवान रेलगाड़ियों में मौजूद नहीं रहते. नक्सलियों के डर से रेलवे पुलिस स्वयं की सुरक्षा में ही लगी रहती है. पिछले कुछ वर्षों से इस पूरे रेलखंड पर नक्सलियों का राज है. वे जब चाहते हैं, तब हिंसक घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और रेलवे पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है. 11 मार्च 2007 को दिनदहाड़े सैकड़ों नक्सलियों ने झाझा स्टेशन स्थित जीआरपी थाने पर हमला करके दर्ज़नों रायफलें लूट ली थीं. हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई थी. कई बार नरगंजों, सिमुलतल्ला एवं घोरपारा स्टेशनों पर लूटपाट, स्टेशन मास्टर को बंधक बनाने, रेल पटरियों और केबिन को बम से उड़ाने की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है. लेकिन, नक्सलियों की किसी भी कार्रवाई पर घटना के वक़्त रेलवे पुलिस प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई. नक्सलियों की हिम्मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष आधा दर्ज़न महिला नक्सलियों ने दिनदहाड़े हावड़ा–मोकामा पैसेंजर में सवार तीन पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उनकी रायफलें लूट लीं और फरार हो गईं. हालांकि नक्सलियों के इस हमले में जानमाल का नुक़सान नहीं हुआ. झाझा कांड के बाद रेल प्रशासन ने इस खंड पर रात में पुलिस गश्ती बंद कर दी. पुलिस बल ट्रेनों में नहीं रहता है. इसका फ़ायदा उठाकर अपराधियों ने बीते वर्ष 25 दिसंबर की रात में अप पंजाब मेल में लूटपाट की, जिसमें एक रेलयात्री की हत्या कर दी गई और दो अन्य जख्मी हो गए.

पिछले दो–तीन महीनों से लगातार रात में लंबी दूरी की ट्रेनों जैसे पंजाब मेल, विभूति एक्सप्रेस, लालकिला एक्सप्रेस एवं दानापुर–विलासपुर एक्सप्रेस को घने जंगलों में नरगंजों, घोरपारा और सिमुलतल्ला स्टेशनों के बीच चेन पुलिंग करके घंटों खड़ी रखने की घटनाएं हो रही हैं. इस बीच रेलयात्री काफ़ी भयभीत रहते हैं. रेलवे अधिकारी इस संबंध में कुछ भी कहने से कतराते हैं. उल्लेखनीय है कि इस रेलखंड का अधिकांश भाग घने जंगलों और पहाड़ी इलाक़ों में पड़ता है. जिन इलाक़ों में नक्सलियों का साम्राज्य है, वहां स्थानीय पुलिस किसी कार्रवाई की बात सोच भी नहीं सकती. बिहार और झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ज़िला पुलिस बल भी त्वरित कार्रवाई नहीं करता है. दोनों राज्यों के तीन ज़िलों जमुई, बांका और देवघर का इलाक़ा इस रेलखंड को छूता है. पिछले कुछ वर्षों से उक्त तीनों ज़िले नक्सलियों से त्रस्त रहे हैं. रेल सुरक्षाबल के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार एवं राजकीय रेल थाना प्रभारी अनंत आर्य कुछ भी कहने से कतराते हैं. ऐसी स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग गया है.

उत्तर बिहार : राजनीतिक घरानों में घमासान

उत्तर बिहार में राजनीतिक घरानों का घमासान शुरू हो गया है. सियासी पुनर्वास की जद्दोज़हद में लगे लोगों में कोई डाल से छूटा पक्षी है तो कोई कटी पतंग. सबका सिर्फ़ एक ही मक़सद है कि जिस सीट पर कभी पिता, ससुर एवं पति निर्वाचित हुए, उस पर फिर से परिवार का परचम लहराना है. घरानों के घमासान में इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी अग्निपरीक्षा होनी है. वर्ष 2009 के विधानसभा उपचुनाव में सांसदों एवं मंत्रियों के बेटों, पत्नी अथवा किसी अन्य उत्तराधिकारी को नीतीश ने प्रत्याशी नहीं बनाया. यूं कहें कि टिकट नहीं दिया, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजनेताओं के उत्तराधिकारियों की दावेदारी को कहां तक नकार पाते हैं. मधुबनी से निर्वाचित विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह कहते हैं कि कोई भी नेता बेरोज़गार नहीं होना चाहता है. जो पिछले चुनाव में जीते, उन्हें अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है. जो हारे, वे फिर से कुर्सी पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.

वीणा शाही

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर आहत पूर्व मंत्री वीणा शाही ने जदयू की सदस्यता ग्रहण तो कर ली, लेकिन यहां उनके राजनीतिक पुनर्वास का संकट पैदा हो गया है. जिस वैशाली विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने दो बार प्रतिनिधित्व किया और जहां से उनके ससुर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एल पी शाही और पति स्वर्गीय हेमंत शाही निर्वाचित हुए थे, उस सीट पर फ़िलहाल राज्य के ग्रामीण कार्य मंत्री वृषिण पटेल का क़ब्ज़ा है. उनका टिकट काटकर वीणा शाही को प्रत्याशी बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. इस कारण परेशान वीणा शाही ने वैशाली प्रवास के दौरान चिंतामणिपुर हाईस्कूल की सभा में नीतीश कुमार को बताया कि अपने मायके एवं सीता माता की जन्मभूमि सीतामढ़ी और ससुराल वैशाली (बुद्ध की कर्मभूमि एवं महावीर की जन्मभूमि) का उनके जीवन में बड़ा महत्व है. ऐसा कहकर वीणा शाही ने मुख्यमंत्री को बताना चाहा कि वैशाली से सीतामढ़ी के बीच उनका आधार है और वह इस बीच के ही किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहेंगी. वैसे वीणा शाही के नाम की चर्चा मुज़फ़्फ़रपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी हो रही है, मगर किसी दूसरे क्षेत्र से उनका पुनर्वास आसान नहीं होगा.

डॉ. जगन्नाथ मिश्र

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र धर्मसंकट में हैं. वह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि जदयू में बने रहें या फिर से कांग्रेस का दामन थाम लें. डॉ. मिश्र की नीतीश कुमार से नाराज़गी और उनके पुत्र नीतीश मिश्र के राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफ़े के बाद पार्टी से पिता–पुत्र के रिश्ते सामान्य नहीं रहे. हालांकि मधुबनी में हर्ट अस्पताल के उदघाटन के मौक़े पर नीतीश कुमार और डॉ. मिश्र एक मंच पर नज़र आए. नीतीश मिश्र ने झंझारपुर में नीतीश कुमार से पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमाओं का अनावरण कराया, लेकिन डॉ. मिश्र अभी अनिर्णय की स्थिति में हैं. नीतीश मिश्र पिछली बार मधुबनी के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे. झंझारपुर से पुन: जीतने के लिए उन्हें पिछड़ी जातियों के वोटों की ज़रूरत पड़ेगी. इस समीकरण को मज़बूत करने के लिए उन्होंने ललित–कर्पूरी की प्रतिमाओं का अनावरण कराया. मगर, इस मंच पर डॉ. जगन्नाथ मिश्र की अनुपस्थिति से सवाल उठ रहे हैं.

नीतीश मिश्र

हालांकि अख़बारों में डॉ. मिश्र ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के पक्ष में बयान देकर नए समीकरणों का संकेत दिया. इससे अनुमान लगाया जाता है कि डॉ. मिश्र पूर्व विधान पार्षद पदमाशा झा के माध्यम से सोनिया गांधी की ड्योढ़ी तक पहुंचने की कोशिश में हैं. बाईपास सर्जरी करा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद को अपनी ढलती उम्र की चिंता सताने लगी है. वह अपने बेटे अजय निषाद को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए बेचैन हैं. वर्ष 2005 में उन्होंने अपने बेटे को साहेबगंज से जदयू प्रत्याशी बनवाया, लेकिन सफलता नहीं मिली. दूसरे चुनाव में अजय निषाद कुढ़नी से राजद प्रत्याशी बने, पर यहां भी वह हार गए. कैप्टन निषाद मीनापुर, कुढ़नी अथवा औराई से बेटे को विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं. मगर, विधानसभा उपचुनाव में राजनेताओं के उत्तराधिकारियों को टिकट न देने वाले नीतीश कुमार के लिए अजय निषाद को टिकट देना आसान नहीं होगा. अगर टिकट मिल भी गया तो जीतने की गारंटी कौन देगा? क्योंकि, कुढ़नी एवं मीनापुर के वर्तमान विधायकों और औराई के दावेदारों का टिकट काटना संभव नहीं है. वहीं अगर अजय निषाद प्रत्याशी न बनाए गए तो कैप्टन निषाद दर्ज़नों सीटों पर संकट खड़ा कर सकते हैं. पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडेय ने तीन बार मुज़फ़्फ़रपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. उनकी बहू विनीता विजय वर्ष 2005 के लोकसभा चुनाव में मुज़फ़्फ़रपुर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाई गईं. साफ छवि वाली विनीता का शहर में अल्पसंख्यकों एवं अन्य जातियों ने खुलकर समर्थन किया. राज्य में अपने बूते चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस एक बार फिर विनीता को प्रत्याशी बनाना चाहेगी, लेकिन अगर भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश शर्मा को प्रत्याशी बना दिया तो वोटों के विभाजन का लाभ राजद को मिल सकता है. मुज़फ़्फ़रपुर में विजेंद्र चौधरी से लोहा लेना किसी प्रत्याशी के लिए आसान नहीं होगा. शहर के हर मुहल्ले में आज भी उनके पास अपने कार्यकर्ताओं की फौज है और समाज के हर वर्ग में उनकी गहरी पैठ है. राजद और लोजपा के लिए विजेंद्र मैच जिताने वाले खिलाड़ी साबित होंगे.

स्व. रघुनाथ पांडेय

कैप्टन जयनारायण निषाद

विनीता विजय

पूर्व मंत्री प्रो. शंभु शरण ठाकुर कांटी से निर्वाचित हुए थे. वह अपनी बेटी नीती सिन्हा को जदयू प्रत्याशी बनाना चाहते हैं. कांटी में जदयू प्रत्याशी बदले जाने की अटकलबाजी के बीच प्रो. ठाकुर सहित कई राजनेता सक्रिय हो गए हैं. पूर्व मंत्री स्व. महंथ राम किशोर दास ने वर्ष 1967 एवं 1971 में मीनापुर का प्रतिनिधित्व किया. वह बी पी मंडल सरकार में मंत्री भी रहे. उनके कनिष्ठ पुत्र विजय किशोर उर्फ पप्पू जी की सक्रियता बढ़ गई है, लेकिन अब मीनापुर के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं. कुरेदने पर विजय किशोर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं. अगर लालू प्रसाद कांटी, कुढ़नी, साहेबगंज और औराई जैसे क्षेत्रों में भूमिहार प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो एनडीए के जनाधार की पोल खुल जाएगी.

विजय किशोर

कद्दावर उम्मीदवार

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र एवं उनके पुत्र पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री एल पी शाही की बहू वीणा शाही, पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिन्हा के पुत्र अनुनय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद के पुत्र अजय निषाद, पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडेय की बहू विनीता विजय, पूर्व मंत्री महंथ राम किशोर दास के पुत्र विजय किशोर, विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी वीणा देवी, पूर्व सांसद सीताराम सिंह के पुत्र रणधीर कुमार, जदयू सांसद पूर्णमासी राम के पुत्र विजय राम, विधायक मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला, पूर्व मंत्री प्रो. शंभु शरण ठाकुर की पुत्री नीती सिन्हा, कांग्रेस विधान पार्षद डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह और पूर्व विधान पार्षद रामकुमार सिंह.

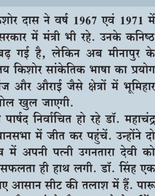

सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार विधान पार्षद निर्वाचित हो रहे डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह का सपना है कि वह एक बार फिर विधानसभा में जीत कर पहुंचें. उन्होंने दो बार साहेबगंज से क़िस्मत आजमाई. पिछले चुनाव में अपनी पत्नी उगनतारा देवी को औराई में कांग्रेस प्रत्याशी बनवाया, मगर हर बार असफलता ही हाथ लगी. डॉ. सिंह एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर भाग्य आजमाने के लिए आसान सीट की तलाश में हैं. पारू निर्वाचन क्षेत्र जैतपुर राजघराने की परंपरागत सीट रहा है. यहां से जैतपुर घराने के वीरेंद्र कुमार सिंह एवं उनकी पत्नी उषा सिन्हा भी चुनाव जीत चुकी हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिन्हा चाहती हैं कि इस सीट से उनके पुत्र अनुनय सिंह जीतकर जाएं. पुन: चुनावी जंग में कूदने के लिए ताल ठोक रहे अनुनय सिंह इस सीट पर एक बार 29 हज़ार वोट ला चुके हैं. वैसे पारू सीट पर पूर्व राजद विधायक मिथिलेश यादव की भी नज़र है. वह फरवरी 2005 के चुनाव में भी यहां से जीते, लेकिन इसी साल दूसरे चुनाव में हार गए.

कई बार तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत चुके रामकुमार सिंह पिछले चुनाव में मढ़ौरा से जदयू प्रत्याशी बने, लेकिन हार गए. मिलनसार एवं मृदुभाषी रामकुमार सिंह पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडेय के दामाद हैं और मुज़फ़्फ़रपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं. साधनसंपन्न जदयू विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह अपनी पत्नी एवं ज़िला परिषद की उपाध्यक्ष वीणा देवी को विधानसभा में भेजना चाहते हैं. उनकी नज़र गायघाट सीट पर है. फरवरी 2005 के चुनाव में वीणा देवी लालगंज से राजद प्रत्याशी थीं, लेकिन वह कांटे की टक्कर में मुन्ना शुक्ला से चुनाव हार गईं. इसी साल दूसरे चुनाव से ठीक पहले वीणा देवी जदयू में आ गईं. नीतीश कुमार उन्हें गायघाट से प्रत्याशी बनाना चाह रहे थे, मगर जॉर्ज फर्नांडीस के वीटो से टिकट अशोक कुमार सिंह को मिल गया. दिनेश प्रसाद सिंह ने अपने नेटवर्क की बदौलत अशोक सिंह का खेल बिगाड़ दिया. टिकट न मिलने पर पति–पत्नी राजद में लौट गए. लोकसभा चुनाव के बाद दिनेश सिंह एवं वीणा देवी ने एक बार फिर जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है और गायघाट सीट पर दावा ठोक रहे हैं. गोपालगंज के जदयू सांसद पूर्णमासी राम अपने पुत्र विजय राम को विधानसभा में भेजना चाहते हैं. इस कोशिश में वह पार्टी से निलंबित हो चुके हैं. वर्ष 2007 के विधानसभा उपचुनाव में नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण की बगहा (सु.) सीट पर पूर्णमासी राम के बेटे को प्रत्याशी नहीं बनाया तो विजय राजद प्रत्याशी बन गए. हालांकि वह जदयू के शिवजी राय से हार गए. सीताराम सिंह भी लोकसभा चुनाव में रमा देवी से हार गए. सीताराम सिंह अब अपने बेटे के पुनर्वास के लिए सक्रिय हैं. इसी तरह पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव औराई से जदयू, रमई राम बोचहां से जदयू, हिंद केसरी यादव मीनापुर से राजद या कांग्रेस, शीतलराम सकरा से राजद, बसावन प्रसाद भगत कुढ़नी या मीनापुर से जदयू या राजद, नवल किशोर शाही रून्नी सैदपुर से राकांपा या जदयू, पूर्व विधायक राज किशोर सिंह वैशाली से राजद और पूर्व विधायक रामकुमार यादव फुलपरास से जदयू के टिकट पर चुनावी जंग लड़ने को तैयार नज़र आ रहे हैं.

मुन्ना शुक्ला

वीणा देवी

पिछले तीन चुनावों में लालगंज सीट पर जीत हासिल करने वाले जदयू विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला धर्मसंकट में हैं. पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में न्यायालय ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है और वह जेल में हैं. ऐसी स्थिति में उनका चुनाव लड़ना संभव नहीं दिख रहा है. मुन्ना शुक्ला के पोस्टरों और ग्रीटिंग्स में उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला की तस्वीर छपने लगी है. अपनी सियासी हैसियत बरक़रार रखने के लिए मुन्ना अन्नू शुक्ला को लालगंज से जदयू प्रत्याशी बनवाना चाहेंगे. अगर नीतीश कुमार ने अन्नू शुक्ला को टिकट देने में आनाकानी की तो वह बागी बन सकती हैं. मुन्ना शुक्ला की तरह फुलपरास में विधायक देवनाथ यादव एवं उनके पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने से पिता–पुत्र की उम्मीदवारी ख़तरे में है. देवनाथ फ़िलहाल राजनीतिक ताक़त बरक़रार रखने के लिए अपनी पत्नी को फुलपरास से प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, लेकिन जदयू के कई मज़बूत दावेदार रोड़े खड़े कर सकते हैं. वैसे देवनाथ के परिवार से उम्मीदवारी तय मानी जा रही है और मुक़ाबला रोमांचक होगा. जदयू ने पिछली बार यहां पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल के पुत्र भरत मंडल को प्रत्याशी बनाया था. दूसरे स्थान पर रहे भरत मंडल को जदयू एक बार फिर अति पिछड़ा कोटे से आजमाना चाहेगा. मधेपुर क्षेत्र का लखनौर प्रखंड अब झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है. मधेपुर के राजद विधायक जगत नारायण सिंह अब झंझारपुर से चुनाव लड़ना चाहेंगे. पूर्व मंत्री रामावतार चौधरी का निधन हो चुका है. यहां पूर्व राज्यसभा सदस्य रामदेव भंडारी के पुत्र भी राजद के टिकट के बड़े दावेदार हैं. झंझारपुर से उम्मीदवारी तय करने के लिए लालू प्रसाद को ख़ासी माथापच्ची करनी पड़ेगी.

रमई राम

संगीता
feedback@chauthiduniya.com

श्रमदान से बंजर भूमि में आई बहार

मगध प्रमंडल के गया ज़िले के अतरी प्रखंड में नरावट पंचायत के साठ दलित परिवारों ने दृढ़ इच्छाशक्ति, सामूहिकता एवं एकता की जो मिसाल क़ायम की है, वह समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणाप्रद है. मुरली पहाड़ी की तलहटी में बसा है नरावट पंचायत का टोला वनवासी नगर.

इसके चारों ओर नक्सलियों का वर्चस्व और बसेरा है, लेकिन साठ घरों और एक सौ बीस दलित परिवारों का यह गांव नक्सलियों की सोच के ठीक विपरीत अहिंसा में विश्वास करके विकास के रास्ते पर चल रहा है. इस छोटे से टोले में कोई भी अंजान व्यक्ति पहुंचता है तो महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या सत्तर–अस्सी वर्ष का बुज़ुर्ग, हर कोई उसका स्वागत और अभिवादन जय जगत कहकर करता है. सिर्फ़ कहने से ही नहीं, टोले के लोग कर्म से भी सारे जगत का भला करना चाहते हैं. अपने परिवारों के बीच शराब बंदी कराने के अलावा सौ एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर टोले के लोग सामूहिक खेती कर रहे हैं. उन्होंने श्रमदान के ज़रिए तीन किलोमीटर सड़क, चार तालाबों–आहर और सामुदायिक भवन का निर्माण किया है. इन दलित परिवारों का एकमात्र दर्द यह है कि जिस भूमि पर वे क़रीब दो दशक से रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसका पर्चा पट्टा उनके नाम नहीं हुआ है. इसके लिए वे गांधीवादी जन संगठन एकता परिषद के माध्यम से संघर्षरत हैं.

> **इस छोटे से टोले में कोई भी अंजान व्यक्ति पहुंचता है तो महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या सत्तर–अस्सी वर्ष का बुज़ुर्ग, हर कोई उसका स्वागत और अभिवादन जय जगत कहकर करता है.**

गांव के मुखिया पैंतालिस वर्षीय रामदहीन मांझी बताते हैं कि 1990 के पहले नरावट में हमारी बहुत ख़राब स्थिति थी. यहां सिर्फ़ समस्याएं ही समस्याएं थीं, लेकिन लोक जागरण नामक संस्था ने हम लोगों को जगाया. गांधीवादी जन संगठन एकता परिषद के मार्गदर्शन और प्रयासों से हम लोग शांतिपूर्वक बेहतर जीवन जी रहे हैं. 1990 में हम सभी साठ परिवारों ने नरावट डीह गांव छोड़ दिया. एक ही दिन में अपनी झोपड़ी, कबाड़ और सामान लेकर गांव से कुछ दूर ख़ाली पड़ी बंजर भूमि पर आ बसे. यहां आकर हम लोगों ने बंजर पड़ी क़रीब सौ एकड़ भूमि को सामूहिक रूप से आबाद करने का निर्णय लिया. एकता परिषद ने इसके लिए पांच जोड़े बैल और दो हज़ार पेड़ दिए.

समय–समय पर अन्य सहयोग दिया और अधिकार के लिए अहिंसापूर्वक संघर्ष करने की प्रेरणा दी. आज वनवासी नगर के आसपास लहलहाती खेती और हरियाली नज़र आती है, जो दलित परिवारों की देन है. हालांकि इन दलितों को कई बार समाज और पुलिस का कोपभाजन भी बनना पड़ा, लेकिन अपने सही क़दम से यहां के दलित नहीं डिगे. नरावट गांव के किसानों ने इनके द्वारा उपजाऊ बनाई गई ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने का प्रयास किया, लेकिन वनवासी नगर की महिलाओं ने आगे आकर उन सभी को भागने पर मजबूर कर दिया. 2005 में नालंदा ज़िले के छबिलापुर एवं बैजनाथपुर गुमटी में नक्सलियों ने पुलिस पिकेट पर लूटपाट की. घटना से गुस्साई पुलिस ने दलितों के साथ मारपीट की और उनके प्रमुख रामदहीन को पकड़ कर अतरी थाने में बंद कर दिया. इस पर गांव के सभी लोगों ने अतरी थाने का घेराव कर पुलिस को बताया कि वे जल, जंगल और ज़मीन पर अपने अधिकार के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन नक्सली नहीं हैं. एकता परिषद ने भी पुलिस कार्रवाई का विरोध किया. सच्चाई जानने पर अतरी के थानेदार ने सभी से सामूहिक रूप से माफी मांगी.

बंजर भूमि को रहने लायक बनाया.

आज इस गांव के दलित परिवार एक से लेकर डेढ़ एकड़ भूमि प्रति परिवार बांटकर सामूहिक खेती करते हैं. सामूहिक रूप से पत्थर तोड़ कर कुछ राशि जमा करते हैं. इससे रोजी–रोटी की व्यवस्था होती है. वे मज़दूरी भी करते हैं. गांव में शराब पीना बंद है. कभी कोई व्यक्ति शराब पीकर आ गया तो उससे जुर्माना वसूला जाता है. वनवासी नगर में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और मतदान केंद्र न होने के कारण दलितों को काफ़ी परेशानी होती है. मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं. वनवासी नगर में स्कूल बनाने के लिए राशि का आवंटन हो चुका है, लेकिन वन भूमि होने के कारण स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया जा रहा है.

कहीं भी कोई समस्या हो, यहां के दलित परिवार श्रमदान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. 2006 में गर्मी के मौसम में जब गया शहर में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हुआ और जल जमात नामक संस्था ने शहर के प्राचीन तालाबों की खुदाई–सफाई शुरू की तो इस गांव के एक सौ आठ दलित क़रीब पचास किलोमीटर पैदल चलकर गया पहुंचे. और, उन्होंने सप्ताह भर वहां रहकर प्राचीन सरयू तालाब की खुदाई की. इस दौरान उन्होंने खाना–खुराकी की व्यवस्था भी स्वयं की. आज वनवासी नगर के दलित अपने कर्म, विचार, मेहनत और समाजसेवा के लिए पूरे ज़िले में चर्चित हैं. दलितों के सामूहिक प्रयास के कारण वनवासी नगर को सोशल एक्टिविटी के लिए 2005 का माजा कोईन अवार्ड मिल चुका है. गांव की एक और ख़ासियत है कि यहां किसी भी घर में ताला नहीं लगता. यहां के दलित अपने बच्चों को अधिकारों के लिए महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलकर संघर्ष करने की शिक्षा देते हैं.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

सेंटर फॉर रिसर्च इन इकनॉमिक डेवलपमेंट
बीमा एवं वित्तीय क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुभवी एवं उत्साही लोगों की ज़रूरत हैं
रोज़गार का नया अवसर

योग्य एवं इच्छुक
युवक-युवतियां अपने सी.वी., एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 के पते पर भेजे या
jobs@credindia.com पर मेल करें.

ब्लॉक प्रमुख
3,000 - 5,000 प्रति माह
जिला प्रमुख
10,000 - 15,000 प्रति माह

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 22 फरवरी–28 फरवरी 2010

बिहार में रणवीर सेना पर दर्जनों नरसंहारों, बलात्कार और चोरी का आरोप है. जुलाई 1995 में बिहार सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था.

किसान कंगाल बिचौलिए मालामाल

किसान ख़ून-पसीना बहाकर फ़सल उपजाते हैं, लेकिन जो क़ीमत उन्हें मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती. जब वह सरकारी ख़रीद केंद्र पर जाते हैं तो बिचौलिए उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेते हैं. इस तरह बिचौलिए बिना कुछ किए धरे ही चांदी काट रहे हैं और किसान अपने हक़ से वंचित हो रहे हैं.

धान के कटोरे के रूप में विख्यात रोहतास की धरती पर दिन-रात मेहनत करने वाले किसानों की कहानी देश के अन्य हिस्सों में खेती करने वाले किसानों से अलग होती जा रही है. जहां ऐन वक़्त पर खाद की किल्लत से किसानों की कमर लगातार टूटती जा रही है, वहीं सरकारी ख़रीद केंद्रों पर सक्रिय बिचौलिए किसानों का हक़ मार रहे हैं. 62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पंजाब की उपज के क़रीब पहुंच चुके रोहतास के किसान 58 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपजा कर भी अपने जीवन स्तर में कोई ख़ास बदलाव महसूस नहीं करते हैं. धान की यह उपज पिछले वर्ष 2009 में आंकी गई थी. तब कृषि विभाग ने उम्मीद जताई थी कि रोहतास जल्द ही पंजाब के रिकॉर्ड उत्पादन के समीप होगा. लगातार बढ़ती उपज, खेती में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों एवं अन्य संसाधनों के उपयोग के बाद भी यहां के किसान अपने जीवन स्तर में ख़ास सुधार नहीं कर पा रहे हैं. काफ़ी विचार मंथन के बाद जो बात उभर कर सामने आई, वह यह थी कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य न मिल पाना ही इस स्थिति की वजह है. रोहतास में जब भी धान या चावल की ख़रीदारी शुरू होती है तो वह कुछ बिचौलियों, एफसीआई कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आसपास केंद्रित हो जाती है. यहां के रैक प्वाइंट से लदने वाली चावल या धान से भरी बोरियां अपने गंतव्य तक पहुंचते-पहुंचते मिट्टी और बालू की बोरियों में तब्दील हो जाती हैं. सूचना मिलने पर कई बार काफ़ी हो-हल्ला हुआ, लेकिन मामला दबा दिया गया. पिछले वर्ष यहां चावल ख़रीदारी में गड़बड़ी के आरोप में एफसीआई के कई पदाधिकारियों पर गाज भी गिरी, लेकिन वही पदाधिकारी एवं कर्मचारी फिर से वर्ष 2010 की ख़रीदारी प्रक्रिया शुरू कराने के लिए सासाराम और डेहरी के केंद्रों पर आ गए हैं. इधर सहकारी संस्थाओं के संचालक एवं पैक्सों के अध्यक्ष यह कहकर उंगली उठा रहे हैं कि एक ख़ास संस्था से एफसीआई ने क्षमता से कई गुना ज़्यादा चावल की ख़रीदारी की, जबकि कई अन्य संस्थाओं के चावल लदे ट्रक एक महीने तक केंद्र के बाहर खड़े रहे. इससे लगभग 50 सहकारी संस्थाओं को लाखों रुपये का नुक़सान उठाना पड़ा. किसानों से धान और चावल लेने वाली संस्थाएं मुंह ताकते रह गईं. बताया जाता है कि कुछ बिचौलिए सासाराम पहुंचने से पहले शिवसागर स्टेशन पर ही रैक की दो बोगियां कटवा कर उस पर अपना माल लाद देते हैं और रैक प्वाइंट पर मौजूद चावल लदे ट्रक खड़े ही रह जाते हैं. जब इस मामले का ख़ुलासा हुआ तो प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन तब तक ख़रीदारी का काम बंद हो चुका था. बाहरी केंद्रों में बतौर कमीशन प्रति क्विंटल 60 रुपये तक देने पड़े, इससे संस्थाओं की कमर टूट गई.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

उर्मिला की राह पर पाखी

बात चाहे भोजपुरी फ़िल्मों की हो या बॉलीवुड की, दोनों जगह सफलता के दो फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं. पहला फॉर्मूला है लकी स्टार्स. इंडस्ट्री में जिन को-स्टार्स की केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आती है या उनकी कुछ फ़िल्में लगातार हिट हो जाएं तो निर्देशक उन्हें लकी मानकर बार-बार अपनी फ़िल्मों में दोहराते हैं. दूसरा फॉर्मूला है एक्सपोजर यानी अंग प्रदर्शन. जो भी अभिनेत्री इन दोनों फॉर्मूलों पर खरी उतरती है, समझ लीजिए कि वही सबसे व्यस्त और चमकता सितारा है. बहुत कम अभिनेत्रियां ही इन दोनों मापदंडों पर खरी उतरती हैं. मगर, पाखी हेगड़े की बात करें तो एवरी थिंग इज पॉसिबल. जी हां, भोजपुरी फ़िल्मों की सबसे सफल एवं सेक्सी स्टार पाखी निरहुआ के साथ एक साल में सर्वाधिक हिट फ़िल्में देकर निर्माताओं के लिए लकी जोड़ीदार बन चुकी हैं. रही-सही कसर उनकी अगली फ़िल्म में उनके ज़बरदस्त एक्सपोजर से पूरी हो जाएगी. दर्शक उनकी अब तक की सबसे बोल्ड इमेज से वाक़िफ़ होंगे. दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित निर्माता-निर्देशक डी रामानायडू की फ़िल्म *शिवा* में दिनेश लाल यादव उर्फ़ निरहुआ एवं पाखी के बीच कई रोमांटिक दृश्य हैं. इन दृश्यों की शूटिंग विज़ाग के ख़ूबसूरत बीच पर हुई है. बक़ौल निर्माता, इस फ़िल्म से पाखी उर्मिला के रंगीला वाले दौर की याद दिलाएगी. पाखी भी कहती हैं कि अभी तक लोगों ने उन्हें रोमांटिक किरदारों में देखा है, पर जिस तरह से उर्मिला ने फिल्म रंगीला से सबको चौंका दिया था, कुछ वैसा ही लोग मुझे फ़िल्म *शिवा* में देखेंगे. तो फिर, आप भी इस नई रंगीला गर्ल के दीदार के लिए तैयार रहिए.

उनकी अगली फ़िल्म एक्सपोजर से भरपूर होगी. दर्शक फ़िल्म *शिवा* में उनकी अब तक की सबसे बोल्ड इमेज से वाक़िफ़ होंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

रणवीर सेना के पसरते पांव

एक तरफ़ झारखंड के वन बाहुल्य, औद्योगिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों ने उत्पात मचा रखा है, वहीं अब दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंधित रणवीर सेना के नाम पर अपराधियों को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है. बिहार में नक्सलियों के साथ लड़ते-लड़ते टूटकर बिखर चुकी इस सेना ने झारखंड को अपना नया चारागाह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. यहां इसका मक़सद नक्सलियों से लोहा लेना नहीं, बल्कि आतंक फैलाकर अवैध वसूली करना है. सर्वविदित है कि बिहार में इसकी आय का ज़रिया लेवी वसूली और गांजे की तस्करी था. झारखंड के माफ़िया सरगना भी इसे आर्थिक मदद देते थे, लेकिन बिहार में पांव उखड़ने के बाद यह झारखंड में अपनी जड़ें फैला रही है. गांजा और कोयला तस्करी पर पहले से ही सेना समर्थकों का क़ब्ज़ा रहा है. अब रंगदार, सूदख़ोर और अपहर्ता गिरोहों के लोगों को भी इसकी छत्रछाया में लाने का प्रयास चल रहा है. कई पुलिस अधिकारी भी इसके संरक्षक बने हुए हैं. झारखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री राज धनवार इलाक़े के दबंग ज़मींदारों के साथ मिलकर पहले भी नक्सल विरोधी सेना के गठन का प्रयास करते रहे हैं. एक पूर्व मंत्री भी उनकी मुहिम में विशेष सहयोगी रहे हैं. अब बदले परिवेश में वह भी गुपचुप तरीक़े से सेना के गठन में सहयोग कर रहे हैं.

माओवादियों ने अफीम को कमाई का ज़रिया बनाया है तो दूसरा पक्ष गांजे से इसका जवाब देने का प्रयास कर रहा है. हालांकि झारखंड में दोनों के बीच टकराव की नौबत शायद ही आए, क्योंकि यहां सामाजिक अंतर्विरोध की कोई लड़ाई नहीं चल रही है. दूसरी बात यह कि रणवीर सेना का सामाजिक आधार मुख्यत: शहरी और औद्योगिक इलाक़ों में सिमटा हुआ है. ग्रामीण क्षेत्रों में इसका आधार अगर है भी तो पलामू, कोडरमा जैसे बिहार के कुछ सीमावर्ती इलाक़ों में. वहां टकराव की स्थिति बन सकती है, अन्यथा अपने-अपने इलाक़ों में दोनों के आतंक का सिक्का चलता रहेगा. दोनों का मक़सद धन की उगाही, हथियार एकत्र करना और आतंक फैलाना है. सेना के संचालक नक्सल विरोधी अभियान में सरकार का साथ देकर सत्ता में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करेंगे. इन्हें अगर सफलता मिली तो विधि व्यवस्था के लिए नक्सली एक बड़ा ख़तरा साबित होंगे. झारखंड में कृष्णा प्रधान को रणवीर सेना का संस्थापक माना जाता रहा है. वह अब व्यवसायी एवं राजनीतिक व्यक्ति बन चुके हैं. सूत्र बताते हैं कि इस बार सेना की गतिविधियां हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक अपराधी पृष्ठभूमि के ठेकेदार के आवास से संचालित हो रही हैं. वह कई हत्याओं का आरोपी रहा है. पिछले वर्ष माओवादियों ने उसके पोकलेन को फूंक डाला था, तभी से वह उनसे खार खाए बैठा है. उसने भाजपा के कुछ वरीय नेताओं से संबंध बना रखे हैं. अब वह स्वयं को कृष्णा प्रधान का आदमी बताकर उनका नाम भुनाने का प्रयास कर रहा है. वह रांची के एक थानेदार को भी अपना रिश्तेदार बताता है. उसके पास अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा लगा रहता है.

बिहार में रणवीर सेना पर दर्ज़नों नरसंहारों, बलात्कार और चोरी के आरोप हैं. जुलाई 1995 में बिहार सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह सेना 19 नरसंहारों समेत 80 घटनाओं को अंजाम देकर 279 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है, जिसमें 79 महिलाएं और 45 बच्चे भी शामिल हैं. यह सेना 19वीं शताब्दी के भूमिहार जाति के एक नायक रणवीर बाबा के नाम पर बनी है. रणवीर बाबा भोजपुर ज़िले के बेलाउर गांव के एक अवकाश प्राप्त सैनिक थे, जिन्होंने राजपूतों के वर्चस्व को चुनौती दी थी और भूमिहार जाति को उसका हक़ और सम्मान दिलाया था. सितंबर 1994 में बेलाउर गांव के धरीक्षण चौधरी की पहल पर ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया के नेतृत्व में सवर्ण लिबरेशन फ्रंट और सनलाइट सेना को मिलाकर इसका गठन किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य बड़े किसानों और सामंतों के हितों की रक्षा के लिए नक्सलियों से लोहा लेना था. इससे पूर्व ज़मींदारों की कई निजी सेनाएं नक्सलियों के विरुद्ध मोर्चा लेकर पराजित हो चुकी थीं. इनमें कुंअर सेना, आज़ाद सेना, ब्रह्मर्षि सेना, किसान मोर्चा, गंगा सेना आदि थीं. 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रणवीर सेना ने 50 दलितों की हत्या कर दी थी. उसके बाद ही इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था. 23 मार्च 1997 को हसबपुर गांव में इसने 10 पार्टी यूनिटी समर्थक मज़दूरों को मार डाला और जाने के पहले ख़ून से रणवीर सेना का नाम लिख दिया. एक दिसंबर 1997 को 16 बच्चों, 27 महिलाओं और 18 पुरुषों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. रणवीर सेना ने इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए कहा था कि उसने बच्चों की हत्या इसलिए की, क्योंकि वे बड़े होकर नक्सली बनते और महिलाओं की हत्या इसलिए की, क्योंकि वे नक्सलियों को जन्म देतीं. उसी रात उन्होंने पांच नाबालिग लड़कियों के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया और उनकी क्षत-विक्षत लाशें छोड़ गए. 25 जनवरी 1999 को उन्होंने शंकरबिगहा गांव में महिलाओं और बच्चों समेत 22 दलितों की हत्या कर दी थी. इसके दो सप्ताह बाद सेना ने नारायणपुर में 12 दलितों को भून डाला था. 29 अगस्त 2002 को रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया पटना में गिरफ़्तार कर लिए गए. उसके बाद 7 दिसंबर 2002 को शमशेर बहादुर सिंह सेना के प्रमुख बने. फिर 25 दिसंबर 2002 को भुअर ठाकुर ने उनकी जगह कमान संभाली. 24 दिसंबर 2002 को वह आरा सासाराम रोड स्थित चरपोखरी के पास अपने दो सहयोगियों के साथ गिरफ़्तार कर लिए गए. एक जनवरी 2009 को काठमांडू के एक मॉल में हुए बम विस्फोट में रणवीर सेना का नाम आया था. इस घटना में एक भारतीय युवक जख्मी हो गया था. एक माह पूर्व काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए बम विस्फोट में भी रणवीर सेना का नाम आया था. नेपाल की घटनाओं से यह साफ हो चुका है कि अब यह सिर्फ नक्सलियों से लड़ने वाली निजी सेना नहीं रही, बल्कि पूरी तरह एक दक्षिणपंथी आतंकी संगठन में तब्दील हो चुकी है.

पुलिस हिरासत में ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया.

नवल किशोर सिंह
feedback@chauthiduniya.com